तमिलनाडुः दक्षिण की सियासी जंग

किसान आंदोलनः अडिग हैं डगर पर

प्रतिरक्षाः असलहों का जटिल जाल

24 फरवरी, 2021 40 रुपए

इंडिया टुडे

कहीं देर न हो जाए!

चमोली में हिमालय पर एकाएक आई विनाशकारी बाढ़ ने फिर चेताया कि इस पर्वतीय क्षेत्र का नाजुक पर्यावरण बचाने पर तुरंत ध्यान देना होगा, साथ ही यहां चल रहे अंधाधुंध विकास कार्यों की समीक्षा करनी होगी

उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटकर गिरने से तबाह पावर प्लांट में फंसे श्रमिकों को खोजते आइटीबीपी के जवान

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

OC

www.indiatodayhindi.in

VISIT…

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरु)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन वग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 13; 18-24 फरवरी, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित.**
संपादक: राज चेंगप्पा

सुर्खियां
पश्चिम बंगाल चुनाव: त्रिकोणीय लड़ाई?
पेज 4

फुरसत
सवाल-जवाब/विधु विनोद
चोपड़ा: बेबाक विनोद
पेज 50

भीतर

18 आवरण कथा

बड़े खतरे की आहट

उत्तराखंड की हालिया तबाही ने बेरोकटोक विकास गतिविधियों की समीक्षा और नाजुक पर्यावरण संतुलन की रक्षा के लिए फौरन कदम उठाने की ओर ध्यान खींचा

तमिलनाडु
26 चुनावी मुकाबला
यह तमिलनाडु विधानसभा का पहला चुनाव है जो बरसों छाए रहे कद्दावर नेताओं के बगैर लड़ा जाएगा.

गोरखपुर
34 योगी के शहर में विकास की गंगा
गोरखपुर में जिस स्तर पर विकास के काम हो रहे हैं, उनसे बड़े हिस्से के लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा.

गोल्ड एक्सचेंज
38 कई रोड़े हैं इस राह में
सोने के कारोबार में पारदर्शिता के लिए गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बनना जरूरी. मगर इसकी स्थापना क्या आसान है?

किशोर बियानी
40 गर्दिश में सितारे
उन्हें अपना कारोबार बेचने को मजबूर होना पड़ा और रिलायंस के साथ उनका सौदा कानूनी दांवपेंचों में फंस गया.

प्रतिरक्षा
43 हथियारों का जंजाल
मनमाने वैश्विक हथियार निर्माताओं पर निर्भरता से भारतीय सेना को काफी परेशानी हो रही है.

सिनेमा
46 जल्द देखिए सिनेमाघर में
प्रोड्यूसर और स्टुडियो साल भर से रोक कर रखी अपनी फिल्मों की रिलीज की तारीखों का ऐलान करने को तैयार.

आवरण फोटो : आइटीबीपी/एपी

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

सुर्खियां

बीएमसी चुनाव 2022: मिशन मुंबई
पेज 7

किसान आंदोलन: अडिग डगर
पेज 8

केरल की जंग: पुख्ता दिख रही पिनाराई की जमीन
पेज 10

हीरा खनन: पन्ना में हीरे का पेंच
पेज 12

संयुक्त मोर्चा हाथरस गैंगरेप के खिलाफ कोलकाता में सीपीएम और कांग्रेस का प्रदर्शन

सुबीर हल्दर

पश्चिम बंगाल चुनाव

त्रिकोणीय लड़ाई?

रोमिता दत्ता

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले वहां एक व्यापक 'धर्मनिरपेक्ष' गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है. कांग्रेस-वाम मोर्चा मौलाना अब्बास सिद्दीकी और 21 जनवरी को गठित उनके इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आइएसएफ) को साथ लाने का प्रयास कर रहा है. 33 वर्षीय सिद्दीकी बंगाल में 3,000 से ज्यादा मस्जिदों पर नियंत्रण रखने वाले फुरफुरा शरीफ के वारिस हैं. वे दक्षिण बंगाल के हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों में मुसलमानों पर खासा प्रभाव रखते हैं. उनके आइएसएफ में आठ संगठन शामिल हैं जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और हिंदू मटुआ का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनका मोर्चा मुसलमानों और समाज के अन्य 'कमजोर वर्गों' को एक नया भविष्य देने की बात करता है. अपनी एक जनसभा को संबोधित करते हुए सिद्दीकी कहते हैं, ''इस बार (विधानसभा चुनाव में) हम किंगमेकर की भूमिका अदा करेंगे.''

कांग्रेस और वाम मोर्चा 294 में से 230 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे चुके हैं और खबर है कि वे सिद्दीकी को बची हुई लगभग 60 सीटों का एक बड़ा हिस्सा देने के लिए तैयार हैं. बहरहाल, सिद्दीकी ने इस प्रस्ताव पर अभी कोई उत्साह नहीं दिखाया है. वे कहते हैं, ''अगर वे (कांग्रेस-वाम मोर्चा) गठबंधन बनाने में रुचि रखते हैं तो उन्हें मेरे साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत करनी चाहिए. मुझे पता है कि वे आपस में 230 सीटों पर बंटवारे को अंतिम रूप दे चुके हैं. इसके बाद उन्होंने मेरे लिए ज्यादा विकल्प ही नहीं छोड़ा है.''

सीटों का बंटवारा ही एकमात्र अड़चन नहीं है. तीनों के बीच कोई भी चुनावी समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि सिद्दीकी बंगाल

में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुसलिमीन (एआइएमआइएम)—जिसे कई लोग भाजपा की बी टीम के रूप में देखते हैं—से खुद को अलग रखना चाहते हैं या नहीं. ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और इस बारे में सिद्दीकी के संपर्क में रहे हैं. कांग्रेस और वाम मोर्चा ओवैसी से दूरी बनाए रखना चाहते हैं. उन्हें इस बात की भी आशंका है कि सांप्रदायिक एजेंडा लेकर चलने वाली ओवैसी की राजनीति से प्रदेश में मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण को और भी बढ़ावा मिल सकता है. 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में व्यापक स्तर पर ध्रुवीकरण देखा गया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को मिलाकर उनके खाते में 83 फीसद (क्रमशः 43.3 फीसद और 40 फीसद) वोट पड़े थे.

वाम मोर्चा और कांग्रेस ने सिद्दीकी को अपने खेमे में लाने के लिए हर तरह से सकारात्मक संकेत दिए हैं. वाम मोर्चा के अध्यक्ष सूर्यकांत मिश्र ने आइएसएफ को पिछड़ों और वंचितों का प्रतिनिधित्व करने वाला धर्मनिरपेक्ष मंच बताया है. कांग्रेस के नेता अब्दुल मक्कान ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को पत्र लिखकर बताया है कि सिद्दीकी के साथ गठबंधन बंगाल चुनाव में बड़ा 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है क्योंकि मौलाना ''केवल मुसलमानों में ही नहीं बल्कि दलितों और आदिवासियों में भी बहुत लोकप्रिय हैं.''

बंगाल के 10 करोड़ मतदाताओं में मुसलमान करीब 30 फीसद हैं. इनमें से करीब एक-चौथाई चार जिलों में केंद्रित हैं जहां फुरफुरा शरीफ (यानी सिद्दीकी) का काफी प्रभाव है. राज्य में मुस्लिम बहुल 125 सीटों में से कांग्रेस और वाम मोर्चा ने 2016 में 40 सीटें जीती थीं और अन्य 85 सीटों पर वे दूसरे नंबर पर रहे थे. अब्बास को अपने साथ लाकर यह नया मोर्चा तृणमूल को नुक्सान पहुंचा आसानी से कामयाबी पा सकता है. माकपा के पॉलित ब्यूरो के सदस्य मो. सलीम कहते हैं, ''मुस्लिम वोटों को हमसे छीनकर ममता बनर्जी ने बड़े-बड़े वादों और तुष्टिकरण के बल पर उन्हें अपने साथ बनाए रखने की कोशिश की है. पर अब मुसलमान तृणमूल को छोड़ने का मन बना चुके हैं क्योंकि वे सुरक्षित विकल्प खोज रहे हैं जो वैचारिक रूप से भाजपा से मुकाबला कर सके.''

भाजपा को भी यह बात पता है कि कांग्रेस और वाम मोर्चा उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर उनके खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं.

3 करोड़
मुसलमान हैं पश्चिम बंगाल के कुल 10 करोड़ मतदाताओं में

125
विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी अधिक है

40
मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस और वाम मोर्चा ने 2016 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी

7 फरवरी को हल्दिया में आयोजित एक रैली में मोदी ने आरोप लगाया कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस-वाम मोर्चा और तृणमूल आपस में 'मैच-फिक्सिंग' कर रहे हैं. उधर, सिद्दीकी खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाली ममता को निशाना बना रहे हैं और मुसलमानों के लिए विकास करने के उनके दावे पर सवाल उठाते हैं. वे कहते हैं, ''ममता के शासन में भाजपा ने बंगाल में पहली बार लोकसभा की 18 सीटें जीत लीं और वह मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है. मुसलमानों को यह बात समझ में आ गई है कि ममता और भाजपा एक-दूसरे के पूरक हैं.''

कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि सिद्दीकी के साथ समझौता करके पार्टी अपने पारंपरिक गढ़ मुर्शिदाबाद (दक्षिण बंगाल) और उत्तर दीनाजपुर तथा मालदा (उत्तर बंगाल) में सफलता हासिल कर सकती है. कांग्रेस दक्षिण दीनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद में सिद्दीकी के लिए कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है. खबर है कि सिद्दीकी दक्षिण बंगाल में 40 सीटों की मांग कर रहे हैं जहां मुस्लिम बहुल 125 सीटों में से 61 सीटें आती हैं. वाम मोर्चा को उनकी इस मांग से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा करने से मुस्लिम वोटों पर तृणमूल की मजबूत पकड़ खत्म हो जाएगी और ममता

गेट्टी इमेजेज

चुनावी दांव
अब्बास सिद्दीकी ने कोलकाता में 21 जनवरी को इंडियन सेक्युलर फ्रंट का गठन किया

को भारी नुक्सान पहुंचाया जा सकता है. 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल के पक्ष में 7 फीसद मुस्लिम वोटों के जाने से बंगाल में वाम मोर्चा के 34 साल पुराने शासन का अंत हो गया था. विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम अगर ममता का साथ छोड़ते हैं तो वे निश्चित रूप से प्रस्तावित कांग्रेस-वाममोर्चा-आइएसएफ गठबंधन के साथ जाएंगे.

पिछले आम चुनाव में वाम मोर्चा के वोटों का हिस्सा केवल 7 फीसद था जबकि 2014 के चुनाव में यह 30 फीसद था. उनके वोटों की हिस्सेदारी में इस गिरावट के चलते भाजपा को 20 फीसद वोटों का फायदा हुआ था. हालांकि आगामी चुनाव में वाम मोर्चा के कॉडरों का एक वर्ग भाजपा को फिर से वोट देने के बारे में पुनर्विचार कर सकता है. ममता की पार्टी को छोड़कर भाजपा में जाने वाले कई नेताओं, जिनमें से कई के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, के कारण बहुतों को लगता है कि भाजपा एक प्रकार से तृणमूल का बदतर संस्करण है.

लेकिन वाम मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं के मुताबिक, जब सारी उठापटक खत्म हो जाएगी तो चुनावी लड़ाई भाजपा बनाम तृणमूल पर आकर सिमट जाएगी. वाम मोर्चा की स्थानीय समिति के एक पूर्व नेता का कहना है, ''वाम मोर्चा का कॉडर, जो एक दशक तक तृणमूल के दमन का शिकार रहा है, एक बार फिर बदले की भावना से सरकार बदलने के लिए वोट देगा. वैसे, एक मजबूत मुस्लिम नेता (सिद्दीकी) कुछ मुस्लिम वोटों को खींच सकते हैं पर वाम मोर्चा के हिंदू वोटरों ने अपना मन बना लिया है.'' वे शायद इन दिनों चल रहे एक नारे का हवाला दे रहे हैं कि 'दूहजारएकुशे राम, चौबीशे बाम'' (2021 में भाजपा, 2026 में वाम मोर्चा). ■

सोनू किशन

नया दायित्व
9 फरवरी को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद राज्यपाल से मिलते शाहनवाज हुसैन

बिहार

समीकरण की फिक्र

अमिताभ श्रीवास्तव

फरवरी की 9 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके एक स्पष्ट संदेश दे दिया है. यह विस्तार पिछले साल 16 नवंबर को सरकार के गठन के पूरे 84 दिनों के बाद हुआ है. विपक्ष के लोग सत्तारूढ़ गठबंधन में अस्थिरता की कहानियां फैला रहे थे और कह रहे थे कि इसी वजह से विस्तार में देरी हो रही है. अब जद (यू) के एक नेता के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि थोड़े-बहुत 'मतभेदों' के बावजूद गठबंधन में सब कुछ अच्छा-भला है.

मुख्यमंत्री ने 17 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया. इनमें 9 भाजपा और 8 जद (यू) के कोटे (एक निर्दलीय सहित) से मंत्री बनाए गए हैं. इसके साथ ही मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री को मिलाकर 31 हो गई है. बिहार विधानसभा के 243 सदस्यों के 15 फीसद के हिसाब से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. इसका अर्थ है कि नीतीश मंत्रिमंडल में अभी पांच और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है. सियासी पर्यवेक्षक मानते हैं कि ये मंत्री पद पाला बदलने की ताक में बैठे कुछ और विधायकों को मौका देने की गरज से खाली छोड़ दिए गए हैं. जद (यू) के कोटे से बने आठ मंत्रियों में बसपा से पाला बदलकर जद (यू) में आए विधायक जमा खान और निर्दलीय विधायक सुमीत सिंह भी हैं. अभी बिहार विधानसभा में भाजपा के 74 विधायक हैं. वहीं, जमा खान को मिलाकर जद (यू) के विधायकों की कुल तादाद 44 हो गई है.

इस विस्तार के बाद नीतीश सरकार में भाजपा के 16 और जद (यू) के 13 (निर्दलीय सुमीत सिंह को मिलाकर) मंत्री हैं. अन्य दो वीआइपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी और हम पार्टी के संतोष मांझी हैं.

मंत्रिमंडल में पार्टी के मंत्रियों की संख्या चाहे जितनी हो, नए मंत्रिमंडल पर अब भी जद (यू) की ही छाप है, क्योंकि गृह, ऊर्जा, जल संसाधन और शिक्षा सरीखे भारी-भरकम मंत्रालय नीतीश कुमार की पार्टी के पास हैं, जबकि भाजपा के पास स्वास्थ्य और सड़क निर्माण जैसे अहम विभाग हैं.

भाजपा सब कुछ नए सिरे से करना चाहती है. यह नई सरकार में पिछले मंत्रियों को नहीं दोहराने से लेकर सुशील मोदी को दिल्ली भेजने तक में दिखा

नए मंत्रियों में जो एक नाम अलग से दिखाई देता है, वह हैं सैयद शाहनवाज हुसैन. अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके शाहनवाज भाजपा के अकेले मुस्लिम सदस्य भी हैं. उन्हें उद्योग जैसा हल्का-फुल्का महकमा दिया गया है पर माना जा रहा है कि शाहनवाज को मंत्री बनाकर भाजपा ने अपना उदार चेहरा सामने रखा है.

बिहार में मुसलमान और यादव राजद का मूल समर्थन आधार हैं. वहीं भाजपा तेजस्वी यादव की राजद की मुख्य विरोधी पार्टी के तौर पर उभरने का मनसूबा बना रही है. इसीलिए वह तमाम सामाजिक स्तरों पर पहुंचना चाहती है और पारंपरिक तौर पर राजद का समर्थक आधार माने जाने वाले तबकों के वोट हड़पने का लक्ष्य लेकर चल रही है. अगर भाजपा राज्य के मतदाताओं में 17 फीसद से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिश करती है, तो शाहनवाज इसमें भूमिका अदा कर सकते हैं.

सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी इसलिए हुई क्योंकि जद (यू) को भाजपा के ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग से जूझना पड़ रहा था. भाजपा ने विधानसभा में अपनी ताकत—जद (यू) के 44 के मुकाबले 74 विधायक—का फायदा उठाकर नीतीश से अच्छे कामकाजी रिश्ते रखने वाले वजनदार नेता सुशील मोदी की जगह उपमुख्यमंत्री के दो पद पहले ही ले लिए हैं. दोनों दलों के बीच रिश्ते कुछ वक्त के लिए असहज रहे, पर जद (यू) के नेता मानते हैं कि नीतीश ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. जद (यू) के सूत्र दावा करते हैं कि पार्टी इस विस्तार में लगभग बराबर तादाद में मंत्री पद पाने में सफल रही क्योंकि बिहार में नीतीश के समर्थन के बगैर कोई सरकार मुमकिन नहीं है. विधानसभा में 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी राजद को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर किया जा सका तो इसीलिए कि नीतीश और उनके 44 विधायक उसके खिलाफ हैं. इसी तरह, अगर भाजपा सरकार में है तो इसलिए कि जद (यू) उसके साथ है. चूंकि भाजपा और राजद आपस में हाथ नहीं मिला सकते क्योंकि इससे उनके मूल वोट बैंक तिरोहित हो जाएंगे, लिहाजा जद (यू) का दबदबा आगे भी बना रहेगा. ■

बीएमसी चुनाव 2022

मिशन मुंबई

किरण डी. तारे

नई राह
मुंबई में 31 जनवरी को मरीन ड्राइव पर तटीय सड़क का चल रहा निर्माण

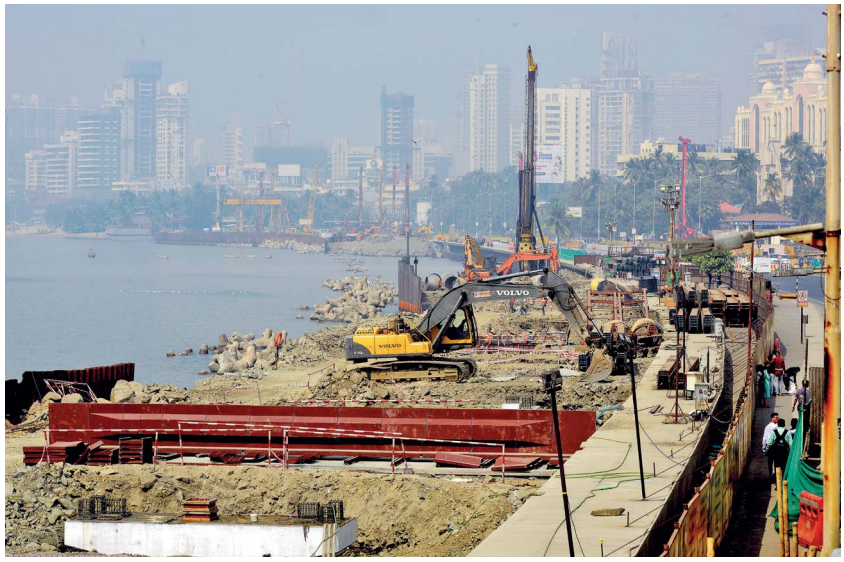

शंकर रावते

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 29 जनवरी को मुंबई मेट्रो के पहले ड्राइवर-रहित कोच का उद्घाटन किया. यह पल इसलिए भी अहम था क्योंकि इससे जुड़े एक विवाद का असर शहर की तीन मेट्रो लाइनों के भविष्य पर पड़ रहा था. ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार कंजूरमार्ग के 210 एकड़ के भूखंड के स्वामित्व के लिए केंद्र से कानूनी जंग लड़ रही है जहां मेट्रो डिपो का निर्माण प्रस्तावित है.

कोच का उद्घाटन करते हुए ठाकरे ने कहा, ''मुझे काम रोकने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी, पर यह सच नहीं है...आप देख सकते हैं कि कई सार्वजनिक बुनियादी ढांचों का काम पूरा होने वाला है.'' आलोचकों का कहना है कि ठाकरे का यह उत्साह फरवरी, 2022 में होने वाले बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) चुनावों से जुड़ा है. बीएमसी एशिया का सबसे दौलतमंद नगर निकाय है जिसका सालाना बजट करीब 39,000 करोड़ रुपए का होता है. 1997 में चुनावी राजनीति में उद्धव के आगाज के बाद से बीएमसी पर शिवसेना की तगड़ी पकड़ है. विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें इस बार भाजपा से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसने पिछले कुछ साल में शहर में अपना आधार बढ़ाया है.

जंग के लिए तैयार

मुंबई में शिवसेना की पकड़ रही है लेकिन भाजपा की बढ़ रही धमक

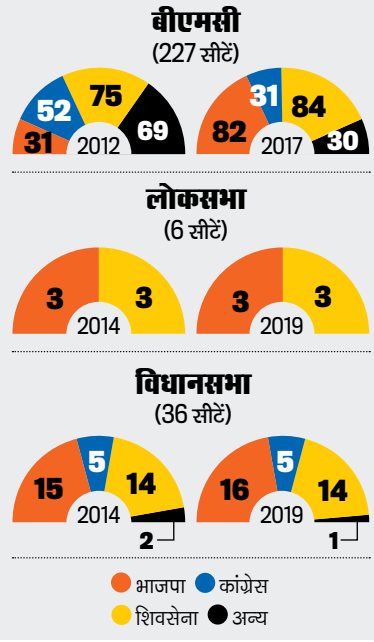

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

ड्राइवर-रहित कोच दहीसर-डीएन नगर मेट्रो लाइन टू ए और दहीसर-अंधेरी ईस्ट मेट्रो लाइन 7 पर दौड़ेगा, जिसके मई में शुरू होने की उम्मीद है. ठाकरे ने कहा कि अगले 3-4 साल शहर के लिए काफी अहम हैं क्योंकि कई मेट्रो गलियारों में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा. ठाकरे सरकार के पास अगले साल तक शहर के कुछ और इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सौंदर्यीकरण से जुड़ी परियोजनाएं हैं, जिनसे ठाकरे को उम्मीद है कि बीएमसी चुनावों से पहले शहर को लेकर उनका संकल्प दिखेगा. ठाकरे अब लगातार दौरे भी करने लगे हैं. बीते साल 27 दिसंबर को, उन्होंने 29.2 किमी लंबे तटीय सड़क के कामकाज का निरीक्षण किया था, जो दक्षिणी मुंबई को समुद्री रास्ते के जरिए उत्तर मुंबई से जोड़ेगा. 28 जनवरी को मुख्यमंत्री ने विश्व विरासत में शामिल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ठीक सामने मौजूद ऐतिहासिक बीएमसी बिल्डिंग में हेरिटेज वॉक के कार्यक्रम की शुरुआत की.

2022 के बीएमसी चुनाव ठाकरे की कूव्वत की परीक्षा होंगे क्योंकि भाजपा मराठी वोटों के दूसरे दावेदार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) से गठजोड़ कर सकती है. अगर मनसे शिवसेना के वोट शेयर में कमी लाने में सफल रही तो भाजपा को बढ़त मिलेगी. ठाकरे इससे अनजान नहीं हैं. उन्होंने बीएमसी चुनावों में हाथ मिलाने के लिए पहले ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से बातचीत शुरू कर दी है. प्रेक्षकों का कहना है कि ऐसे गठजोड़ से सेना के हिंदू जनाधार को नुक्सान पहुंच सकता है. पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत के मुताबिक, पार्टी और मजबूत होगी. वे कहते हैं, ''मुंबई ने हमेशा शिवसेना को वोट दिया है. अगला चुनाव भी कोई अपवाद नहीं होगा.'' भाजपा के मुंबई प्रभारी अतुल भटखालकर कहते हैं, ''मुंबई को अच्छे प्रशासन की तलाश है तो उसे बदलाव करना होगा. हम एकमात्र विकल्प हैं.''

नवी मुंबई, औरंगाबाद, कल्याण-डोम्बिवली, वसई-विरार और कोल्हापुर के नगर निकायों के चुनाव के अगले दौर के बाद ठाकरे अपनी बीएमसी रणनीति की समीक्षा कर सकते हैं. ये चुनाव मार्च में होने हैं. उद्धव शहर के गुजराती वोटरों को लुभाने की फिराक में भी हैं और संकेत दे रहे हैं कि वे एक समावेशी नेता हैं. अगर शिवसेना नवी मुंबई और औरंगाबाद निगमों को जीत जाती है तो ठाकरे अपनी समावेशी सियासत जारी रखेंगे. अगर हार होती है, तो शायद वे अपने 'मराठी माणूस' के एजेंडे पर लौट जाएं. ■

किसान आंदोलन

अडिग डगर

सुजीत ठाकुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को जब लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने के लिए उठे तो अपने भाषण में उन्होंने किसानों के आंदोलन को न सिर्फ पवित्र बताया बल्कि दो-टूक कहा, ''आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का सदन और सरकार भी आदर करती है और करती रहेगी.'' इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत करने का आग्रह करके उस डेडलॉक को तोड़ने का प्रयास भी किया जो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुए हुड़दंग के बाद से बना हुआ है.

दरअसल, 75 दिनों से ज्यादा समय से जारी किसान आंदोलन के नहीं सुलझने की असली वजह, बातचीत के लिए सरकार की ओर से नियुक्त मंत्रियों का रुख और आंदोलन को समर्थन दे रही सियासी हस्तियों का हस्तक्षेप है. सरकार के एक मंत्री स्वीकार करते हैं, ''चूक हुई क्योंकि आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों में उन लोगों का बोलबाला अधिक था जिनके लिए प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया है.'' सरकार से क्या चूक हुई? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं, ''कहीं से किसानों को खालिस्तानी, नक्सली बताया जाने लगा, जबकि सरकार की तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ. बाद में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना स्वीकार्य नहीं है.''

तो क्या अब जल्द ही किसानों के साथ सरकार बातचीत करेगी और बीच का रास्ता निकलेगा? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं कि निश्चित रूप से बातचीत होगी. हालांकि, सरकार के मंत्री दो-टूक कहते हैं कि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, अलबत्ता इनके किसी प्रावधान पर कोई सुझाव किसान संगठनों की तरफ से आता है तो उसमें सुधार करने के लिए सरकार खुले मन से विचार करेगी.

सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर राज्यसभा में 8 फरवरी को प्रधानमंत्री देने आए तो उससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी किसान आंदोलन से जुड़ी हर कड़ी का प्रजेंटेशन करके उससे उन्हें अवगत करा चुके थे. आंदोलन की फंडिंग से लेकर, मीडिया और सोशल मीडिया पर आंदोलन का प्रचार करने वाले, किसान नेताओं को ब्रीफिंग करने वाले और देश भर के किसानों के रुख को लेकर दिए गए प्रजेंटेशन में यह बात सामने आई कि तीनों कृषि कानून की खामियों को लेकर कोई ठोस तर्क न तो सियासी दलों ने और न ही किसान संगठनों ने दिया है. सूत्रों का कहना है कि प्रजेंटेशन में यह बताया गया कि किसानों का विरोध महज धरने तक सीमित है और आंदोलन का हौव्वा सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए पंजाब और हरियाणा के आढ़तियों की शह पर खड़ा किया जा रहा है. इसका पुख्ता तर्क देते हुए कहा गया कि बीती 6 फरवरी को चक्का-जाम का असर कुछ राज्यों में छिटपुट जगह पर ही पड़ा.

तो क्या आंदोलन खत्म करने पर किसान राजी हो जाएंगे? तोमर की राय में वार्ता से ही हल निकलेगा और जो लोग कानून रद्द करने की बात करते हैं उन्हें बताना चाहिए कि कानून में क्या गड़बड़ी है? वे कहते हैं, ''किसानों की एक मांग यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म न किया जाए. सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, कई मंत्रियों ने और अब तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा. इसी तरह यह भ्रम फैलाया गया कि मंडी व्यवस्था खत्म होगी. हम कह चुके हैं कि मंडी खत्म नहीं हो रही.''

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कृषि कानून को लेकर उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा था लेकिन वे पीछे नहीं हटे थे

प्रधानमंत्री की अपील के बाद क्या किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए जाएंगे? किसान नेता राकेश टिकैत कहते हैं, ''किसान सार्थक बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं. हम प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री किसानों का सम्मान रखेंगे, इस सोच के साथ

एएनआइ

बातचीत हो सकती है. फिलहाल हमारी मांग और आंदोलन कायम है.''

आगे क्या

सरकार की पहली रणनीति इस आंदोलन को कुछ किसानों (बड़ी जोत) का विरोध बताकर प्रचारित करने की है. प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसका उल्लेख करते हुए कहा कि 86 फीसद किसान छोटी जोत (2 एकड़ से कम) वाले हैं. इसके लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए कहा, ''छोटे किसानों की दयनीय स्थिति हमेशा चौधरी चरण सिंह को परेशान करती थी.'' दरअसल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर किसान ही गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं जिनमें बहुत-से छोटी जोत के किसान हैं. चौधरी चरण सिंह का जिक्र करके मोदी ने इन्हें ही साधने की कोशिश की है. सरकार की दूसरी रणनीति खुद को देश भर के 86 फीसद किसानों से जोड़ने की है. मोदी जब कहते हैं कि उन्हें छोटे किसानों की चिंता है और उनकी बेहतरी के लिए कानून लाया गया है तो वे दिल्ली के आसपास के आंदोलन से बाकी देश के किसानों को अलग करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं. सरकार की एक और कोशिश किसानों के विरोध को धरने तक सीमित और इसके समर्थन में उतरने वालों को अपनी सियासत साधने वाला बताने की है. मोदी की ओर से 'आंदोलनजीवी जमात' शब्द का प्रयोग इसी संदर्भ में देखा जा रहा है.

गतिरोध कायम

मोदी सरकार का दावा है कि किसानों का प्रदर्शन अब बस धरने तक सीमित

इन सब के बीच सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए चर्चा की टेबल पर नए चेहरों को उतार सकती है. किसानों से बातचीत के लिए राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे चेहरे उतारने पर सरकार विचार कर रही है. सूत्रों का कहना है कि 26 जनवरी की घटना के बाद कई लोगों पर मामले दर्ज हैं. किसानों से बातचीत के दौरान यह मुद्दा उठ सकता है कि जेल में बंद किसानों या जिन किसानों पर मामले दर्ज हैं, उन मामलों को खत्म किया जाए. अगर यह मुद्दा आता है तो सरकार इस मांग पर विचार करेगी और किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले सकती है. बहरहाल, सरकार इस बात को लेकर साफ है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे. खासकर जब मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए कहते हैं, ''कृषि कानून को लेकर शास्त्रीजी को भी विरोध का सामना करना पड़ा. उनका विरोध तो योजना आयोग तक कर रहा था लेकिन शास्त्रीजी पीछे नहीं हटे.'' सरकार उम्मीद कर रही है कि अभी अडिग दिख रहा आंदोलन, बातचीत के जरिए डिगेगा जरूर. ■

प्रशांत वेंबायम

केरल की जंग

पुख्ता दिख रही पिनाराई की जमीन

स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने वाम मोर्चे के चुनाव अभियान में नई जान फूंक दी है. क्या मुख्यमंत्री इससे सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार कर सकते हैं?

जीमोन जैकब

लगभग चार दशकों से केरलवासी बारी-बारी से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) को केरल की सत्ता पर बिठाते आए हैं. लेकिन 2021 का विधानसभा चुनाव हैरान कर सकता है. माना जा रहा था कि सोना तस्करी कांड के उजागर होने और फिर प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद सरकार की छवि बहुत खराब हुई है और उसके लिए जीत मुश्किल होगी. लेकिन बीते दिसंबर में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ एलडीएफ का आश्चर्यजनक प्रदर्शन इस साल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों में अलग पटकथा लिख सकता है.

एलडीएफ की चिंताएं दूर हो गई हैं और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन उत्साह से भरपूर हैं. उन्हें विश्वास है कि उनकी पार्टी सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ, स्थानीय निकाय चुनावों में मिले अपने 40.2 फीसद वोटों को मजबूती से अपने साथ बनाए रखेगा. निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 37.9 फीसद जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 19 फीसद वोट मिले हैं.

साल 2016 में सत्ता संभालने के पहले दिन से ही 75 वर्षीय पिनाराई ने एलडीएफ के जनाधार को बढ़ाने, सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए नई तकनीक को अपनाने और विशेषज्ञों को सरकार के सलाहकार (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ सहित) के रूप में तैनात करने का काम शुरू कर दिया था. राज्य के विकास को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बनाने के लिए 'हरित केरलम' मिशन,

भरपूर उपहार
लाइफ मिशन की एक लाभार्थी के गृह प्रवेश समारोह में पिनाराई विजयन

गरीबों के लिए घर मुहैया कराने वाला लाइफ मिशन, सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 'आरद्रम' और सरकारी स्कूलों की कक्षाओं को उच्च तकनीकी सुविधाओं से लैस करने के लिए शिक्षा मिशन—ये चार ऐसे विशेष मिशन हैं जो उनकी सबसे बड़ी सफलताएं हैं.

राज्य पर आई आपदाओं के दौरान अपने कामकाज से जनता का जीता गया भरोसा ही वह चीज है जो पिनाराई सरकार को एक दूसरे कार्यकाल का मौका दे सकती है. संकटों की शुरुआत निपाह वायरस के प्रकोप के साथ हुई थी. फिर 2018 और 2019 में लगातार बाढ़ और उसके बाद कोविड-19.

आपदाओं के दौरान मुख्यमंत्री के खुद आगे बढ़कर राहत कार्य का मोर्चा संभालने के दृष्टिकोण ने केरलवासियों के मन में उनके लिए गहरी जगह बनाई. एक वरिष्ठ आइएएस अधिकारी बताते हैं, ''बाढ़ के बाद की अवधि में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान के रूप में 4,912 करोड़ रुपये मिले; कोविड-19 के दौरान 523 करोड़ रु. मिले. लेकिन इनसे भी अधिक प्रभावी रही है बेघरों के लिए घरों का निर्माण करने के लिए भूमिदान की पिनाराई की अपील, जो बताती है कि जनता के बीच उनकी गहरी पैठ है. हमें जनता से दान के रूप में लगभग 100 एकड़ जमीन मिली.''

दूसरी पारी की कवायद

निकाय चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री ने चुनाव घोषणापत्र तैयार करने के लिए जिलों के अहम लोगों के साथ गहन विमर्श किया, सरकार के वार्षिक प्रगति कार्ड को प्रसारित किया जा रहा है और पार्टी कॉडर में फिर से उत्साह है. इस बीच सीपीएम नेतृत्व समुदायिक वोटबैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और उसके एजेंडे में सबसे ऊपर सवर्ण हिंदू नायर वोटरों (जो सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर पार्टी से दूर हो गए थे) को वापस लाने के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादा वोटों को खींचना है.

एक बड़ा लाभ केरल कांग्रेस-मणि या केसी (एम) गुट के एलडीएफ में शामिल होने से मिला है. इससे मध्य केरल में पार्टी की संभावनाओं में काफी सुधार होगा; यूडीएफ के खाते से 2.5 फीसद वोटों के खिसकने से खेल बदल सकता है. वोटों में सेंधमारी से ज्यादा बड़ी बात यह है कि पिनाराई को केसी (एम) के नेता जोस के. मणि के रूप में ऐसा शख्स मिला है जो इस क्षेत्र में सीरो-मालाबार कैथोलिक समुदाय से जुड़ने में मददगार होगा. वे उत्तर में मालाबार में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) के प्रभुत्व को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के नेताओं से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं. पिनाराई के अन्य फोकस समूह युवा और महिला मतदाता हैं.

''कांग्रेस केरल में एक ऐसी बाजी खेल रही है जो वह हार चुकी है...वह सांप्रदायिक वायरस फैला रही है जो आने वाले दिनों में कोविड से भी खतरनाक साबित हो सकता है''

ए. विजयराघवन
सीपीएम के राज्य सचिव और एलडीएफ के संयोजक

कांग्रेस की रणनीति

निकाय चुनावों में हार के बाद कांग्रेस निराश नजर आ रही है. पार्टी के नेताओं को सोने की तस्करी प्रकरण और जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसके मुखर अभियान का कोई खास असर नहीं रहा. और जैसा कि एक मीडिया समीक्षक कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वोट डालने के लिए लाइन में खड़े मतदाताओं के दिमाग पर बस महामारी के दौरान मिली फैमिली किट, सरकार के दिए गए 2,50,000 घर और 55 लाख गरीबों को हर महीने मिलने वाली 1,600 रुपए की पेंशन जैसी सहूलियतें हावी रहीं.

कांग्रेस की सारी उम्मीदें अब सबरीमाला मुद्दे को पुनर्जीवित करने पर टिकी हैं और रजस्वला महिलाओं को इस तीर्थस्थल में प्रवेश से रोकने के लिए वह एक नए कानून का मसौदा तैयार कर रही है जिसके उल्लंघन पर दो साल की जेल की सजा का प्रावधान होगा. पार्टी का कहना है कि अगर वह चुनाव जीतती है तो वह नए नियम लागू करेगी. यह कदम, खासकर उस वक्त जब मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के विचाराधीन है, एक निरर्थक कवायद मात्र लगता है.

एलडीएफ के संयोजक और सीपीएम के राज्य सचिव ए. विजयराघवन आगाह करते हैं कि कांग्रेस सांप्रदायिक वायरस फैलाकर एक ऐसा खतरनाक खेल खेल रही है, जो आने वाले दिनों में कोविड से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. वे कहते हैं, ''कांग्रेस केरल में एक ऐसी बाजी खेलने को उतर रही है जो वह पहले ही हार चुकी है. राजनीतिक लाभ के लिए वे एक लोकतांत्रिक प्रणाली में जाति और धर्म जैसे वायरस फैला रहे हैं.''

क्या भाजपा बनेगी 'सुपर विजेता'?

कांग्रेस की तरह, भाजपा भी राज्य में अपनी मौजूदा सियासी स्थिति से चिंतित है. सबरीमाला और सोना तस्करी कांड जैसे जिन मुद्दों पर भाजपा ने लंबे समय तक काम किया, उनमें बहुत दम बचा नहीं है. लेकिन 2016 के बाद से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपने वोट शेयर में सुधार किया है. 2016 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 15 फीसद वोट मिला और इसने 2020 के स्थानीय निकाय चुनावों में इसे 19 फीसद तक पहुंचा दिया. दिग्गज पत्रकार और केरल प्रेस अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एन.पी. राजेंद्रन के मुताबिक, अगर भाजपा अपने वोट शेयर में 3 फीसद का भी इजाफा कर लेती है, तो इससे राज्य से कांग्रेस के पांव उखड़ सकते हैं.

फिलहाल यही भाजपा का उद्देश्य प्रतीत होता है. पार्टी के सबसे बड़े चुनाव प्रबंधक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि पार्टी 25 निर्वाचन क्षेत्रों (140 सीटों वाले सदन) में जीत पर ध्यान केंद्रित करे. अगर वह नेमोम सहित सात सीटें जीतती है तो भी भाजपा नेतृत्व गदगद होगा. भाजपा ने केरल में पहली बार 2016 में नेमोम सीट जीतकर अपना खाता खोला था. आने वाले चुनाव में सात निर्वाचन क्षेत्रों में जीत और 23 फीसद वोट शेयर, भाजपा को केरल में 'सुपर विजेता' बना देगा. फिलहाल भाजपा का एजेंडा राज्य में कांग्रेस को हाशिए पर धकेलना है. कांग्रेस के कमजोर होने से भाजपा को आगे चलकर अपने पांव पसारने और मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने का मौका मिलेगा. भाजपा की यह योजना अन्य राज्यों में तो कारगर साबित हुई है, लेकिन केरल में क्या वे ऐसा कर पाएंगे? ■

हीरा खनन

पन्ना में हीरे का पेंच

राहुल नरोन्हा

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में देश में हीरा खदानों के सबसे बड़े इलाके में 1 जनवरी से कामकाज ठप हो गया क्योंकि 31 दिसंबर 2020 को उसकी वन्यजीव क्षेत्र में खनन संबंधी मंजूरी खत्म हो गई. हीरों की खुदाई वाले इस जिले में खनन का कामकाज रुकने से सरकारी अधिकारियों और वन संरक्षणवादियों के बीच ठन गई है.

पन्ना में बेहद अहम बाघ संरक्षण अभयारण्य भी है. पन्ना बाघ संरक्षण के फील्ड डायरेक्टर यू.के. शर्मा के मुताबिक, अभयारण्य प्रबंधन ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) को वन्यजीव संबंधी मंजूरी खत्म होने के फौरन बाद खनन से जुड़ी सारी गतिविधियां रोक देने को लिखा.

हालांकि 3 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खदान के बंद होने से सार्वजनिक चिंताओं के मद्देनजर ऐलान किया कि पन्ना में मझगवां हीरा खदान बंद नहीं होगी क्योंकि उससे आसपास लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है. संरक्षणवादी तथा राज्य वन्यजीव बोर्ड के पूर्व सदस्य श्यामेंद्र सिंह कहते हैं,

मुश्किल में
मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में मझगवां हीरे की खदान

''मझगवां खदान यहां काम करने वालों के स्थानीय स्तर पर खर्च करने और एनएमडीसी के कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) कार्यों के जरिये स्थानीय अर्थव्यवस्था में पांच करोड़ रुपए का योगदान देती है. स्थानीय लोग खदान के समर्थन में हैं और उसे जारी रखने के पक्षधर हैं.''

एनएमडीसी की खदान पन्ना के मझगवां में है. यह देश की इकलौती मैकेनाइज्ड हीरे की खदान है. एनएमडीसी जिले के बाकी हिस्से में संभावित निजी खदान वालों को 8गुणा8 फुट के 700 प्लॉट भी पट्टे पर देती है. इन छोटी खदानों में करीब 6,000 से 7,000 लोग काम करते हैं. अब अपनी ही खदान के बंद होने के कारण एनएमडीसी इन छोटी खदान वालों को पट्टे भी नहीं दे रही है.

भारतीय खान ब्यूरो के मुताबिक, देश में हीरे के भंडार सिर्फ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही हैं. यह भंडार मध्य प्रदेश में 90 फीसद तक है. एनएमडीसी की वेबसाइट के मुताबिक, मझगवां खदान की क्षमता सालाना 84,000 कैरेट की है. उसमें दावा किया गया है कि इस इलाके से अब तक कुल 10,05,064 कैरेट हीरा निकाला जा चुका है और खदान में प्रति 100 टन मिट्टी में 10 कैरेट हीरा निकलता है.

श्यामेंद्र सिंह कहते हैं, ''हीरे की खदानों ने पन्ना के लोगों को दुनिया भर में पहचान दिलाई है, जिसे वे बनाए रखना चाहेंगे.''

हालांकि नाम न जाहिर करने की शर्त पर वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी कुछ और ही कहानी बताते हैं. ''खदान से उत्पादन बेहद थोड़ा है और एनएमडीसी सीएसआर के मद में हिनौता से पन्ना शहर तक एक बस सेवा शुरू करने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करता. इलाके के नाजुक पर्यावरण संतुलन और बाघों पर खतरे के इतिहास के मद्देनजर कुछ इलाकों को वन्यजीवों के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए.'' संरक्षणवादियों की दलील है कि खनन गतिविधियों की वजह से जंगल के इलाकों में नुक्सान हो रहा है और वे वन्यजीवों के मुक्त विचरण में आड़े आती हैं. पन्ना बाघ संरक्षण क्षेत्र को दिसंबर 2008 में बाघ विहीन घोषित कर दिया गया था. मार्च 2009 में बाघों को यहां फिर आबाद करने का कार्यक्रम शुरू किया गया और फिलहाल पन्ना में बाघों की गिनती करीब 50 बताई जाती है.

84,000
कैरेट सालाना
सालाना की क्षमता है पन्ना स्थित मझगवां खदान की

10,05,064
कैरेट
हीरे अब तक यहां से निकाले जा चुके हैं

8,47,000
कैरेट
हीरे अभी यहां की खदानों में हैं जिनकी कीमत करीब 1,000 करोड़ रु. है

199
लोगों को रोजगार मिला है पन्ना की हीरा खदान में

80%
हिस्सेदारी है भारत की वैश्विक पॉलिश्ड डायमंड मार्केट में

संरक्षणवादी कहते हैं कि खनन गतिविधियों से जंगल के इलाके को नुक्सान पहुंचता है और वन्य जीवों का मुक्त विचरण भी प्रभावित होता है

नाम न जाहिर करने की शर्त पर एनएमडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि राष्ट्रीय अभयारण्य के नियम-कानूनों की वजह से खदान की गतिविधियों पर असर पड़ा है. वे कहते हैं, ''यहां 1,000 करोड़ रु. कीमत के 8.47 लाख कैरेट हीरे का भंडार दबा हुआ है. अगर हम खदान अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे तो हीरे का क्या होगा? हीरे को सुरक्षित करना होगा? हम राष्ट्रीय उद्यान की वजह से वित्तीय नुक्सान झेल रहे हैं. हम दिन में दो पालियों में काम करते हैं, लेकिन तीसरी पाली में काम नहीं कर सकते क्योंकि रात में बत्तियां नहीं जला सकते.''

जब तक ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका में हीरे के भंडार का पता नहीं चला था, तब तक लगभग 3,000 साल से भारत ही दुनिया में इकलौता हीरा उत्पादक देश बना रहा. एशिया में हीरे का एकमात्र स्रोत मझगवां खदान गंगऊ वन अभयारण्य क्षेत्र के 275 हेक्टेयर में फैली है. गंगऊ संरक्षित क्षेत्र पन्ना बाघ अभयारण्य का हिस्सा है. आखिरी बार इसका पट्टा 2005 में 15 साल के लिए इस शर्त के साथ बढ़ाया गया था कि खनन गतिविधियां 2020 तक समेट ली जाएंगी. पन्ना से ही ताल्लुक रखने वाले मध्य प्रदेश के खनन मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह पट्टे की अवधि बढ़ाए जाने के पक्ष में हैं. पहले खदान को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का समर्थन करने वाला राज्य वन्यजीव बोर्ड भी 16 जनवरी को खदान को 2035 तक वन्यजीव मंजूरी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा चुका है. एनएमडीसी के अधिकारियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारसंपन्न समिति और 2005 में राज्य वन्यजीव बोर्ड ने ऐसी किसी खास तारीख का जिक्र नहीं किया था कि कब खनन कार्य रोक दिया जाना चाहिए. दिलचस्प यह भी है कि राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री चौहान ही हैं.

अब प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मेज पर है और मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, एनएमडीसी खदान को अतिरिक्त 10 हेक्टेयर में फैलाना चाहता है, जिसमें से 1.8 हेक्टेयर गंगऊ अभयारण्य में पड़ता है. हालांकि मझगवां खदान के सूत्र इससे इनकार करते हैं कि अतिरिक्त इलाके की मांग की गई है. उनका कहना है कि जिस अतिरिक्त इलाके में खनन की मंजूरी मांगी जा रही है, वह उनके पट्टे वाले इलाके का ही हिस्सा है.

बहरहाल, लगता है कि पन्ना के दो बेशकीमती नग हीरों और बाघों को साथ-साथ रहना सीखना होगा. ■

इलाज : सरकारी अस्पताल में भीड़, प्राइवेट बहुत महंगा

मनीष दीक्षित

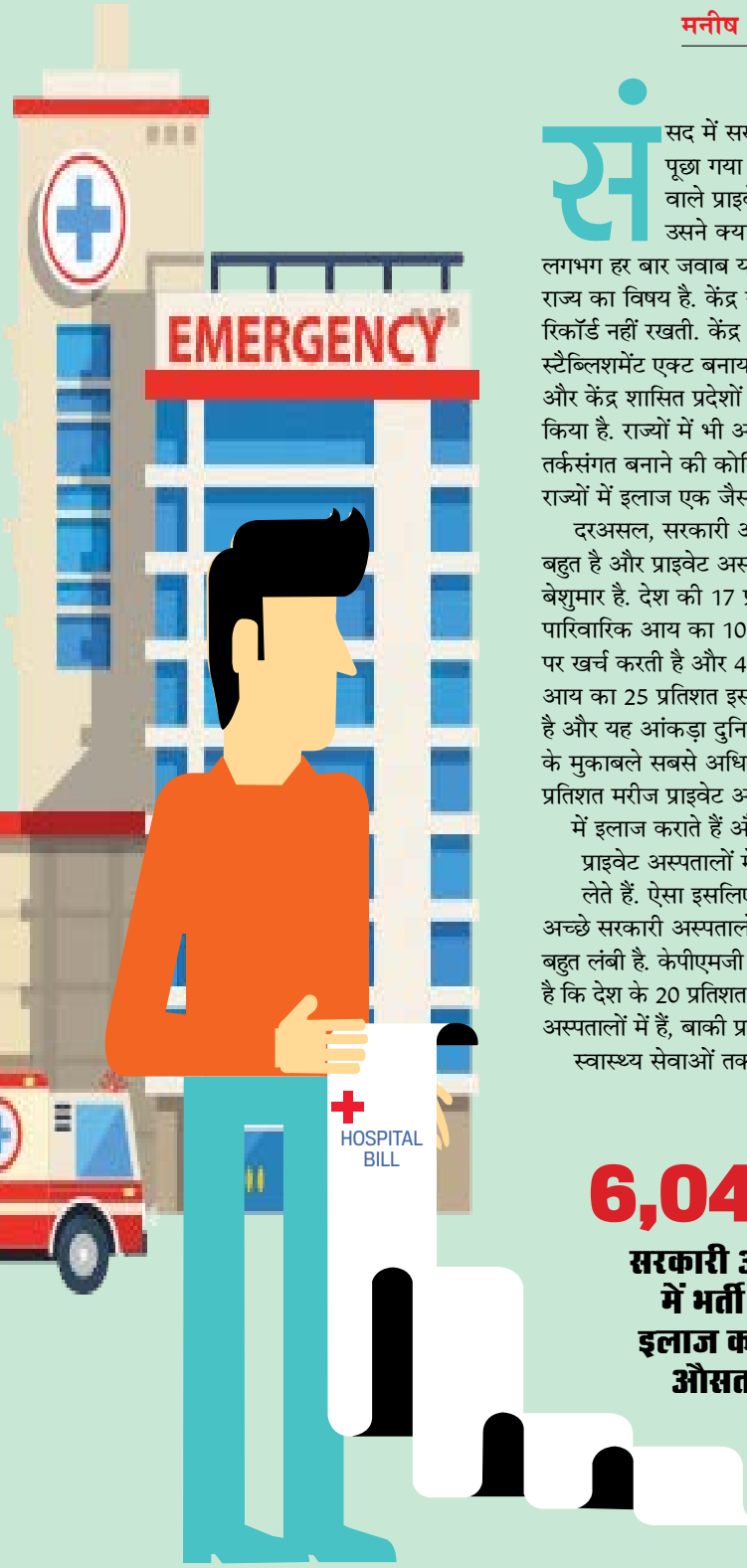

संसद में सरकार से जब भी यह पूछा गया कि जनता को लूटने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर उसने क्या कार्रवाई की तो लगभग हर बार जवाब यही था कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है. केंद्र सरकार इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती. केंद्र सरकार ने क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाया है जिसे 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहां लागू किया है. राज्यों में भी अस्पतालों के चार्ज को तर्कसंगत बनाने की कोशिश नहीं हुई. सभी राज्यों में इलाज एक जैसा महंगा है.

दरअसल, सरकारी अस्पतालों में भीड़ बहुत है और प्राइवेट अस्पताल का खर्च बेशुमार है. देश की 17 प्रतिशत आबादी कुल पारिवारिक आय का 10 प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च करती है और 4 प्रतिशत आबादी आय का 25 प्रतिशत इस मद पर खर्च करती है और यह आंकड़ा दुनिया के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सबसे अधिक है. देश में 74 प्रतिशत मरीज प्राइवेट अस्पताल की ओपीडी में इलाज कराते हैं और 65 प्रतिशत मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज लेते हैं. ऐसा इसलिए है कि एम्स जैसे अच्छे सरकारी अस्पतालों में इलाज की लाइन बहुत लंबी है. केपीएमजी की एक रिपोर्ट कहती है कि देश के 20 प्रतिशत डॉक्टर ही सरकारी अस्पतालों में हैं, बाकी प्राइवेट अस्पतालों में हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होने से

भर्ती होकर इलाज कराने का खर्च (रुपए में)

मर्ज	सरकारी अस्पताल	प्राइवेट अस्पताल
बुखार	2,843	15,513
टीबी/टिटेनस	5,949	51,629
वेक्टरजनित रोग*	3,263	15,697
कैंसर	27,146	99,871
रक्त संबंधी रोग	3,901	24,080
मधुमेह	5,993	28,237
मानसिक/न्यूरो	9,622	44,307
आंख/कान	4,129	18,205
कार्डियो	8,609	58,201
श्वसन रोग	4,938	25,621
पेट संबंधी	5,326	33,268
मसलस्केलेटल	7,597	49,518
जेनिटोयूरिनरी	7,313	35,662
प्रसूति	3,811	29,307
चोटें	7,903	44,967
अन्य	8,191	39,207

(* मच्छर, मक्खी आदि से फैलने वाली बीमारियां)

6,049 रु.
सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने का औसत खर्च

34,214 रु.
प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने का औसत खर्च

ओपीडी में इलाज कराने का खर्च (रुपए में)

मर्ज	सरकारी अस्पताल	प्राइवेट अस्पताल
बुखार	322	716
टीबी/टिटेनस	1,641	2,205
वेक्टरजनित	529	745
कैंसर	2,643	4,447
रक्त संबंधी रोग	321	2,115
मधुमेह	300	780
मानसिक/न्यूरो	701	1,284
आंख/कान	534	946
कार्डियो	395	720
श्वसन रोग	350	650
गैस्ट्रो	520	1,311
मसलस्केलेटल	544	1,008
जेनिटोयूरिनरी	966	2,429
प्रसूति	843	2,403
चोटें	1,074	1,738
अन्य	559	1,074

स्रोतः आर्थिक सर्वे, 2021

होने वाली मौतों से दोगुना मौतें घटिया स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से होती हैं. आर्थिक सर्वेक्षण में 2018 के आंकड़े के हवाले से बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच न होने से 8.38 लाख मौतें हुईं जबकि घटिया स्वास्थ्य सेवा के कारण 15.99 लाख लोगों की जान गई. 1990 से 2016 तक गैर संक्रामक बीमारियों से मौतें 37 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हो गईं. जबकि संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए बेहतर स्वच्छता, पेयजल जैसी चीजें जरूरी होती हैं. हालांकि सरकार का कहना है कि बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर संक्रामक बीमारियां रोकने की गारंटी नहीं है. बहरहाल, एक ही बीमारी के इलाज पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के खर्च में बड़ा फर्क है, जैसे—कैंसर का इलाज सरकारी अस्पताल के मुकाबले 3 गुना, हृदय रोगों का इलाज 6 गुना से ज्यादा और चोटों का इलाज 5.9 गुना महंगा है. ■

समाचार सार

वंशवाद नहीं चलेगा

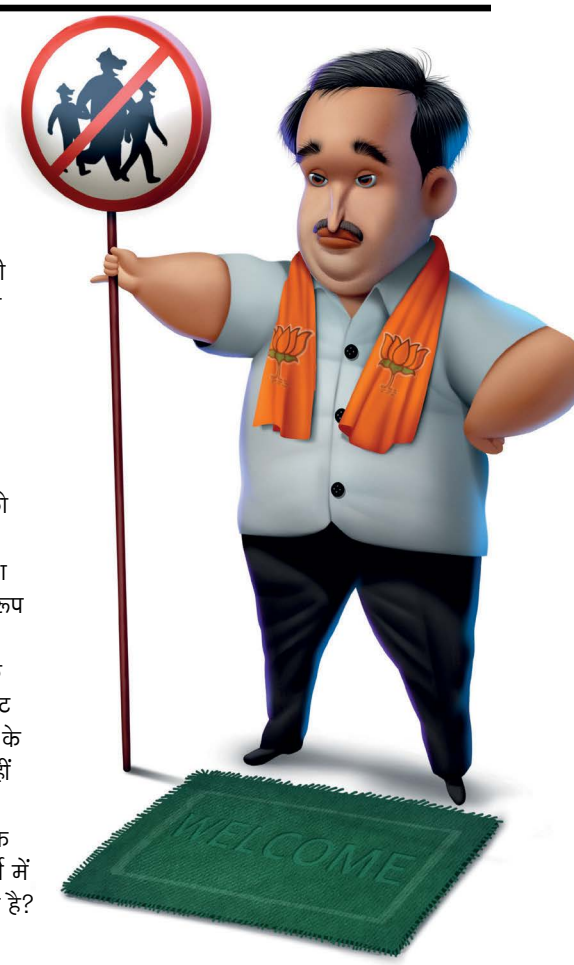

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी सोनल मोदी को 21 फरवरी को होने जा रहे अहमदाबाद नगर निगम के चुनावों में टिकट देने से हाल ही भाजपा ने इनकार कर दिया. फरवरी के पहले हफ्ते में गुजरात भाजपा ने नए नियमों की फेहरिस्त जारी की. इसके तहत पार्टी के किसी नेता के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा. ऐसे में सोनल का रसूखदार पारिवारिक रिश्ता भी प्रदेश अध्यक्ष **सी.आर. पाटील** को अपवाद स्वरूप मंजूरी देने के लिए राजी नहीं कर पाया. इससे झुंझलाई सोनल ने दावा किया कि वे गंभीर भाजपा कार्यकर्ता के नाते टिकट चाहती हैं, न कि मोदी की रिश्तेदार होने के नाते. मगर उनका यह तेवर भी काम नहीं आया. अलबत्ता पाटील को अपने अडिग फैसले की वजह से प्रधानमंत्री की तारीफ जरूर मिल गई. तो क्या यह भगवा पार्टी में वंशवाद चलाने वालों के लिए कोई संदेश है?

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

वैलेंटाइन झटका

मध्य प्रदेश भाजपा ने 12-13 फरवरी को अपने विधायकों और कार्यकारिणी सदस्यों के प्रशिक्षण का आयोजन स्थल पचमढ़ी से अब बदल दिया है. पता चला कि इस सुहाने हिल स्टेशन में उस दौरान सभी होटल वैलेंटाइन डे सप्ताहांत के लिए बुक हैं. आखिरकार आयोजकों को उज्जैन की मंदिर नगरी में जगह मिली. भला ऐसी नाशुक्र किस्म की रुकावटें गंभीर लोगों के किसी उपक्रम में कैसे आड़े आ सकती हैं?

नए ट्विटरिया बिहारी बाबू

कृष्ण मुरारी किशन

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री **जीतन राम मांझी** राज्य के नए ट्विटर सेलेब्रेटी हैं. 76 वर्षीय बुजुर्ग नेता ट्विटर पर अपनी मौजूदगी का पूरा आनंद लेते दिख रहे हैं. हाल ही उन्होंने बिहार पुलिस की टीका-टिप्पणी करने वाले नेताओं के लिए कहा कि अगर उन्हें राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं है तो उनको मिली सुरक्षा लौटा देनी चाहिए. उन्होंने लोजपा के चिराग पासवान और राजद के तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विरोधी कुछ ट्वीट्स पर कहा कि वे अपने गठजोड़ को सार्वजनिक करें. मांझी ने अब ट्विटर से आग्रह किया है कि उनके एकाउंट को प्रमाणित करे.

– **संदीप उन्नीथन**, साथ में **अमिताभ श्रीवास्तव** और **राहुल नरोन्हा**

एयरो इंडिया 2021

स्वदेशी उड़ान

संदीप उन्नीथन

महामारी के दौर में आयोजित एयरो इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यह रही कि उसे भौतिक आयोजन बनाया गया. एशिया का यह सबसे बड़ा आयोजन बेंगलूरू में हर दो साल में होता है. इसकी दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि प्रतिरक्षा विमानन उद्योग में स्वदेशीकरण की ओर सरकार का ध्यान स्पष्ट तरीके से दिखा. सैन्य उड्डयन, हथियार उद्योग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत खर्चीला है. एक राफेल लड़ाकू जेट की कीमत 20 टी-90 टैंकों के बराबर होती है. स्वदेशी विमानन तंत्र को तैयार करना समय खपाऊ काम है और इसके लिए ध्यान और पैसे का भारी निवेश चाहिए. इस दिशा में भारत ने अभी डगमगाते हुए कदम रखने ही शुरू किए हैं.

'वोकल फॉर लोकल' पहल के हिस्से के रूप में, सरकार ने एयर शो में वायुसेना के लिए 83 एलसीए तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपयों का ऑर्डर दिया है—यह भारतीय रक्षा उद्योग का सबसे बड़ा अनुबंध है. ये 123 एलसीए (विभिन्न किस्मों के 40 जेट एक दशक पहले ऑर्डर किए गए थे) इतनी ही संख्या के मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे जो इस दशक में रिटायर होने वाले हैं.

2014 से 2019 के बीच भारत रक्षा हार्डवेयर का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा है और यह दुनिया में हथियारों की कुल बिक्री का 9.5 फीसद हिस्सा खरीदता है. इस खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा लड़ाकू विमानों और मालवाहक विमानों का होता है. मसलन, भारतीय वायुसेना की योजना 110 मल्टीरोल लड़ाकू विमानों की खरीद की है जिसकी लागत करीब 20 अरब डॉलर (1.4 लाख करोड़ रुपए) है और केंद्र सरकार की योजना अगले पांच साल में सैन्य आधुनिकीकरण पर करीब 130 अरब डॉलर (9.47 लाख करोड़ रुपए) खर्च करने की है. सैन्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना सरकार के बड़े लक्ष्यों में से एक है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2022 के अंत तक रक्षा आयातों को 2 अरब डॉलर (14,564 करोड़ रुपए) तक कम करने की घोषणा की है और उन्हें उम्मीद है कि 2025 तक रक्षा निर्यात 5 अरब डॉलर (36,410 करोड़ रुपए) तक बढ़ाया जाएगा. पूर्वी लद्दाख में चीन से तनातनी का माहौल भी उन्नत किस्म के सैन्य हार्डवेयर की जरूरत पर जोर दे रहा है.

आने वाले वक्त में स्वदेशी हथियारों के ऑर्डर भी आयात को कम करने में अहम साबित होंगे और इससे सैन्य विमानन मजबूत होगा. इसमें वायुसेना के लिए 15 हल्के लड़ाकू हेलिकॉप्टरों (एलसीएच) के लिए 3,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर शामिल है और साथ ही करीब 7,000 करोड़ रुपए का 106 एचएएल एचटीटी-40 प्रशिक्षण विमान का ऑर्डर भी शामिल है. सरकारी एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) देश की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है, पर इसका एकाधिकार जल्द ही खत्म हो सकता है जब यूरोपियन विमानन दिग्गज एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के संयुक्त उपक्रम को 15,000 करोड़ रु. का ऑर्डर दिया जाएगा. यह ऑर्डर 56 सी-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए होगा और इससे निजी क्षेत्र की क्षमताएं भी बढ़ेंगी.

डीआरडीओ का एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) अब तेजस मार्क-2 के पहले प्रोटोटाइप को अगले साल शुरू कर रहा है. महत्वाकांक्षी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रोटोटाइप एडवान्स्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) 2024 में उड़ान भरेगा. हालिया वर्षों में किसी और देश ने इतने कम समय में इतने अधिक प्रोटोटाइप की शुरुआत नहीं की है जितनी की एडीए ने इस दशक में की है—यानी मिग-29, मिराज 2000 और जगुआर की जगह लेने के लिए उठाए कदम. एडीए के निदेशक गिरीश देवधर भविष्यवाणी करते हैं कि 2035 तक लड़ाकू विमानों के मामले में भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा और देश भारी सु-30 एमकेआइ को छोड़कर बाकी हर श्रेणी के मानवसहित और मानवरहित लड़ाकू जेट उत्पादन करने लगेगा. हालांकि, तकनीक के स्तर पर कुछ काम अभी भी बाकी है. मसलन, 83 तेजस एलसीए के महज 50 फीसद स्वदेशी हैं. लेकिन भविष्य के लिहाज से एक बड़ी शुरुआत हो चुकी है. ■

आगे बढ़ते कदम

स्वदेशी प्रतिरक्षा विमानन के लिए यह बड़ी कामयाबी है कि इसे सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए के ठेके दे दिए हैं और 25,000 करोड़ रुपए के अन्य ऑर्डर अभी कतार में हैं

एलसीए तेजस

ऑर्डर का मूल्य

48,000 करोड़ रु.

स्थिति: 3 फरवरी को एचएएल को इसका ठेका दिया गया

कतार में

एचटीटी-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट

अनुमानित मूल्य

7,000 करोड़ रु.

स्थिति: डिफेंस एक्वीजिशन काउंसिल (डीएसी) ने अगस्त 2020 में इसे हरी झंडी दे दी है, वायुसेना ने 4 फरवरी को 70 एयरक्राफ्ट के लिए एचएएल को आरएफपी जारी किया

सी-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट

टाटा-एयरबस का संयुक्त उपक्रम इसका निर्माण करेगा

अनुमानित मूल्य

15,000 करोड़ रु.

स्थिति: सीसीएस (कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी) की स्वीकृति लंबित है

लाइट अटैक हेलिकॉप्टर

अनुमानित मूल्य

3,000 करोड़ रु.

स्थिति: मार्च 2021 में समझौता होना है

अर्थात्

गुम राह की तलाश

अंशुमान तिवारी

डिजिटल करेंसी, सरकारी कंपनियों के निजीकरण और फसलों की सही कीमत के बीच क्या रिश्ता है? सरकार इन तीनों को ही टालना चाहती थी लेकिन वक्त ने इनको अपरिहार्य बना दिया. तीन साल से दायें-बायें कर रहा और प्रतिबंधों पर टिका निजाम अंतत: डिजिटल करेंसी के लिए कानून लाने पर मजबूर हो गया. ठीक इसी तरह बजट के घाटे ने यह हालत कर दी कि अब खुलकर कहना पड़ा कि सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण के अलावा कोई रास्ता नहीं है.

बदलता वक्त बेहद तेज आवाज में सरकार को बता रहा है कि भारत में फसलों का पारदर्शी और उचित मूल्य (प्राइस रियलाइजेशन) तय करने के सुधारों का वक्त आ गया है. आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली का तख्त नहीं बस यही सुधार तो मांग रहे हैं. और सरकार फसल मूल्यों की पारदर्शी व्यवस्था के बगैर हवा में फसलों का बाजार खड़ा कर देना चाहती है. इसलिए शक सुलग उठे और किसानों का ध्वस्त भरोसा अब किसान महापंचायतों में उमड़ रहा है.

किसानों को अचानक सपना नहीं आया कि वह उठकर समर्थन मूल्य की गारंटी मांगने लगे और न ही वह ऐसा कुछ मांग रहे हैं जो सरकार के एजेंडे में नहीं था. सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के जिस वादे को बार बार दोहरा रही थी, फसलों की सही कीमत (केवल सीमित सरकारी खरीद नहीं) उसका अपरिहार्य हिस्सा रही है. इन बिलों से पहले तक तैयार हुए तीन आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य के तहत फसल मूल्य सुधारों के एजेंडे पर काम चल रहा था, जिससे किसान भी अनभिज्ञ नहीं थे.

फसल की वाजिब कीमत के अलावा कृषि सुधार और हैं क्या? खेती की जमीन बढ़ नहीं सकती. फसलों का विविधीकरण, नई तकनीकों के इस्तेमाल करने, खेती में निजी निवेश बढ़ाने या फिर छोटे किसानों की आय बढ़ाने के सभी उपाय इस बात पर केंद्रित हैं कि उत्पादक (किसान) को अधिकांश उत्पादन (फसल) की सही कीमत कैसे मिले. खेती में तरक्की के सभी रास्ते इससे ही निकलते हैं.

नवंबर 2018 में नीति आयोग ने न्यू इंडिया @75 नाम का दस्तावेज बनाया था, जिसकी भूमिका स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी थी. इसमें 2022 तक कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को खत्म कर एग्री प्राइसिंग ट्रिब्यूनल बनाने का लक्ष्य रखा गया. नीति आयोग से कहा गया था कि वह

- एमएसपी के समानांतर मिनिमम रिजर्व प्राइस (एमआरपी) की प्रक्रिया तय करे. इस एमआरपी पर मंडियों में फसल की नीलामी शुरू होनी चाहिए.
- तैयारी यह भी थी कि देश में सरप्लस उत्पादन, देश में कम लेकिन विदेश में ज्यादा और दोनों जगह कम उत्पादन वाली फसलों के लिए एमएसपी से अलग कीमत तय की जाए.
- मंडी कमीशन और फीस का ढांचा बदलने की भी राय थी ताकि किसानों को एमएसपी का प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल सके.
- अच्छे और खराब मानसून के दौरान अलग-अलग कीमतें तय करने पर भी बात हो रही थी.

यह दस्तावेज किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति की सिफारिशों (सितंबर 2018) के बाद बना था जिसमें किसानों की समग्र उत्पादन लागत पर कम से कम 50 फीसदी मुनाफा देने की सिफारिश की गई थी. इससे पहले 2011 में नरेंद्र मोदी (तब मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता वाली समिति एमएसपी को महंगाई से जोड़ने और बाजार में फसल की बिक्री एमएसपी पर आधारित करने के वैधानिक उपाय की राय दे चुकी थी.

ये तैयारियां इन स्वीकृतियों की देन थीं

- अधिकांश फसल (सरकारी खरीद कुल उपज का केवल 13%) लागत से कम कीमत पर बिकती है. विभिन्न फसलों में खलिहान मूल्य (हार्वेस्ट प्राइस) बाजार के खुदरा मूल्य से 35 से 63 फीसदी तक कम हैं—नीति आयोग
- 1980 के बाद से अब तक किसानों की आय कभी भी गैर खेतिहर श्रमिकों की आय के एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकी. यानी 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने को उनकी कमाई सालाना 10.4 फीसदी की दर से बढ़ानी होगी.

इस हकीकत और तैयारी की रोशनी में नए कानूनों पर हैरत लाजिमी है जिनमें फसलों की वाजिब कीमत तय करने की योजना तो दूर समर्थन मूल्य शब्द का जिक्र भी नहीं था. यानी मंदी के बीच किसान अर्से से जिन सुधारों की बाट जोह रहे थे उनकी जगह उन्हें कुछ और दे दिया गया. नतीजा: आशंकाएं जन्मी और विरोध उबल पड़ा.

यहां न सरकार गुमराह है, न किसान. सरकारें आदतन आलसी होती हैं. किसी 'खास' को फायदा देने के अलावा वे अक्सर संकट और सियासी नुक्सान पर ही जागती हैं. सो कभी कभी आंदोलन भी सुधार का रास्ता खोल देते हैं. फसल मूल्य सुधार जटिल हैं, इनसे तत्काल बड़े राजनैतिक नारे नहीं बनेंगे लेकिन इन सुधारों को अब शुरू करना ही होगा क्योंकि उस विचार को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है (विक्टर ह्यूगो). @anshuman1tiwari

चाहे-अनचाहे किसान आंदोलन भारतीय कृषि को सबसे बड़े सुधार की दहलीज पर ले आया है

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

आसन्न खतरे की आहट

हिमालय में हिमनद खिसकने से अचानक आई बाढ़ की भारी तबाही इलाके के नाजुक पर्यावरण संतुलन की रक्षा और बेरोकटोक विकास गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए फौरन कदम उठाने की जरूरत का एहसास दिला गई

अनिलेश एस. महाजन

जान बचाने की जद्दोजहद
एक पावर प्लांट की सुरंग में भारी मलबा आकर जम गया. वहां कार्यरत श्रमिकों की तलाश करते एनडीआरएफ के जवान

एपी

उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतों पर नंदादेवी चोटी की ढलान पर 'झूलते ग्लेशियर' का एक हिस्सा खिसका तो 7 फरवरी को अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने हिमालय के नाजुक पर्यावरण संतुलन से छेड़छाड़ के प्रति खतरे की घंटी बजा दी है. राज्य के चमोली जिले में जोशीमठ के ऊपर रैणी गांव के पास ग्लेशियर के अचानक टूटने से अलकनंदा नदी की सहायक नदियों धौलीगंगा और ऋषिगंगा में भारी बाढ़ के साथ गाद-मिट्टी, चट्टान नीचे की ओर बहे तो प्रमुख पनबिजली परियोजनाओं सहित रास्ते में पड़ने वाले इलाकों में भारी तबाही बरपा हो गई. कम से कम 36 लोग मारे गए और 166 से अधिक लापता हैं.

इससे जून 2013 में केदारनाथ तीर्थ के पास बादल फटने से आई बाढ़ के बाद राज्य में हुए जल प्रलय की यादें ताजा हो गईं, जिसमें लगभग 4,500 लोग मारे गए थे. हालांकि, शाम तक वैसी तबाही की आशंका कम होने लगी क्योंकि नीचे पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में बांध के फाटक खोल दिए गए और टिहरी बांध के फाटक बंद कर दिए गए ताकि नीचे आने वाला पानी देव प्रयाग पर अलकनंदा के संगम से गंगा में समा जाए.

बाढ़ ने एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड स्थित 520 मेगावाट की पनबिजली परियोजना ध्वस्त हो गई और निर्माणाधीन ऋषिगंगा छोटी-विद्युत परियोजना, सड़कों, पुलों के साथ-साथ घरों का तो नामोनिशन ही मिट गया. लापता लोगों में से अधिकांश के इन दो बिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे होने की आशंका है. टीएचडीसी इंडिया की 444 मेगावाट की पीपलकोटी और जेपी ग्रुप की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग पनबिजली परियोजनाओं को भी भारी क्षति की रिपोर्ट मिल रही है. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), सेना,

ग्लेशियर हादसा

अचानक तबाही का मंजर

7 फरवरी की सुबह उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदादेवी की ढलानों पर 'झूलते ग्लेशियर' का एक हिस्सा टूट गया, जिससे अलकनंदा नदी की सहायक नदियों में बाढ़ आ गई और भारी तबाही हुई

ग्राफिक: नीलांजन दास

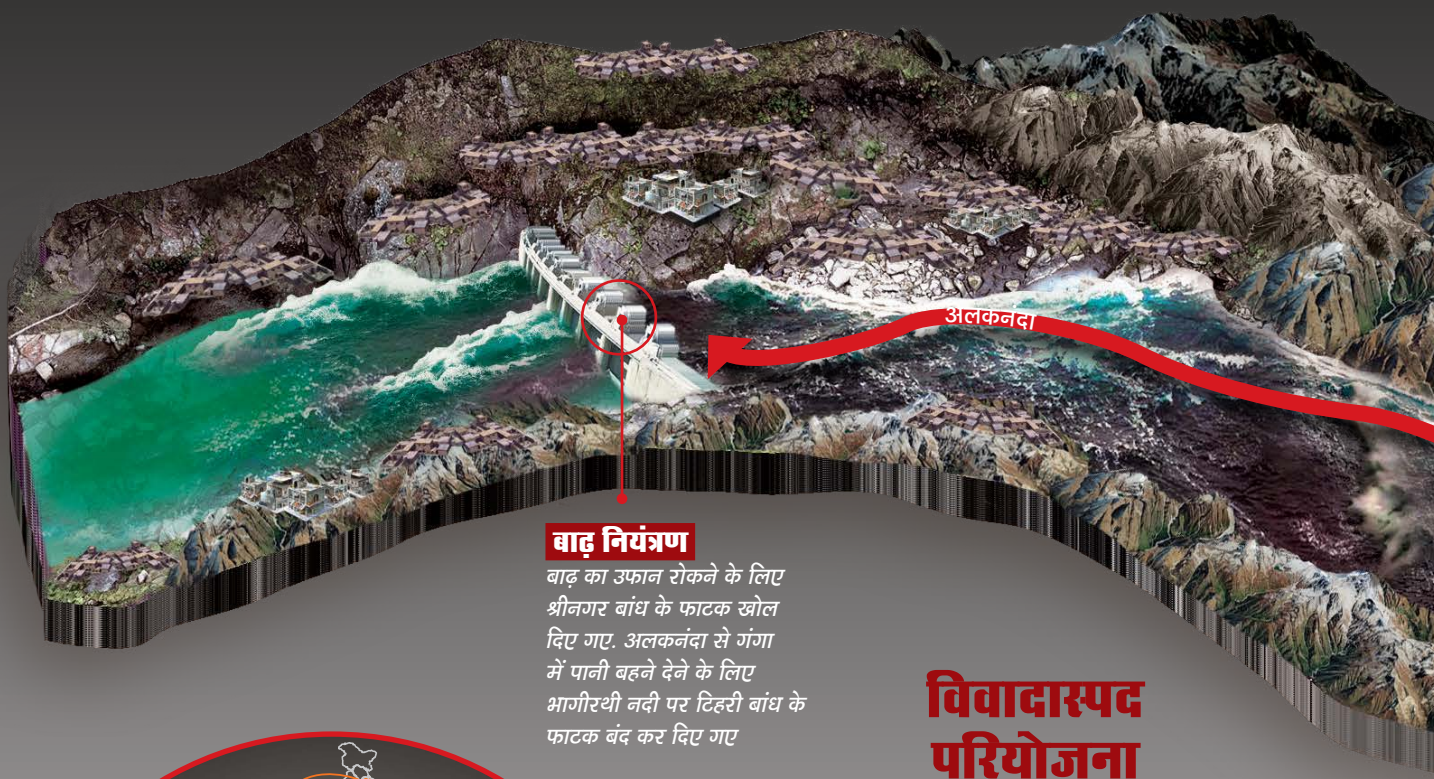

बाढ़ नियंत्रण

बाढ़ का उफान रोकने के लिए श्रीनगर बांध के फाटक खोल दिए गए. अलकनंदा से गंगा में पानी बहने देने के लिए भागीरथी नदी पर टिहरी बांध के फाटक बंद कर दिए गए

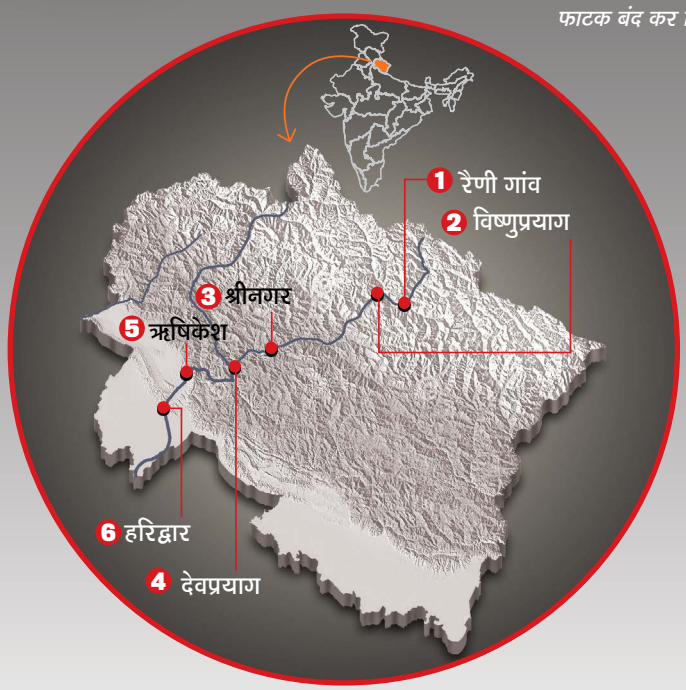

विवादास्पद परियोजना

आपत्ति की अनदेखी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की आपत्तियों के बावजूद, 816 किलोमीटर लंबे चार धाम राजमार्ग को पूरा करने पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार दोनों का जोर है

वनों का नाश

हाइवे की चौड़ाई 10 मीटर रखने के लिए अधिक संख्या में पेड़ों को काटने की आवश्यकता होगी और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न मंचों पर आपत्तियां जताई गई हैं

बिजली का लोभ

उत्तराखंड में करीब 200 बड़ी, मध्यम और छोटी पनबिजली परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में

आपदा के कंक्रीट

कंक्रीट जैसी आधुनिक निर्माण सामग्री, गर्मी पैदा करती है और तापमान बढ़ाती है, जो ग्लेशियरों को प्रभावित करती है

बर्फ में ढंका सैलाब

हिमालय के ग्लेशियरों के खिसकने से झीलें बन जाती हैं जो अमूमन गाद-मिट्टी और चट्टानों से बंधी होती हैं. किसी वजह से यह बांध टूटने से बड़ी मात्रा में पानी नीचे नदियों और झरनों में उतर आता है. पानी रास्ते में आने वाली मिट्टी-गाद, चट्टानों और अन्य मलबे को बहा लाता है, जिससे भारी तबाही बरपा होती है

गर्म होती सतह

नेपाल स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (आइसीआइएसओडी) की एक रिपोर्ट में हिंदुकुश-हिमालय क्षेत्र में बढ़ते तापमान को लेकर चेतावनी दी गई है. भले ही वैश्विक तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम है, लेकिन ऊंचाई आधारित तापमान वृद्धि के कारण हिंदुकुश क्षेत्र में कम से कम 1.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है

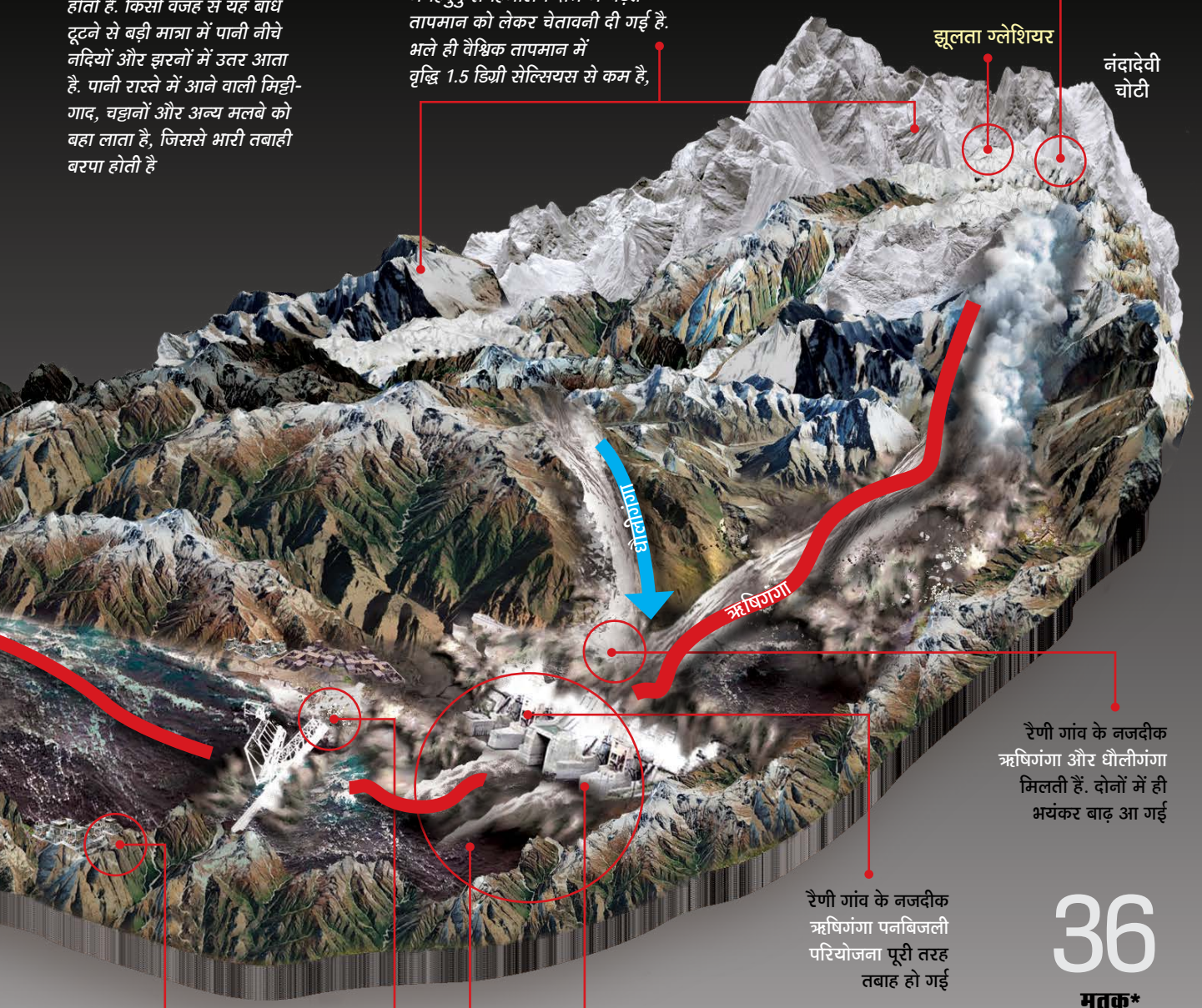

रैणी गांव के नजदीक ऋषिगंगा और धौलीगंगा मिलती हैं. दोनों में ही भयंकर बाढ़ आ गई

रैणी गांव के नजदीक ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना पूरी तरह तबाह हो गई

36
मृतक*

166
लापता*
करीब 15 शव चमोली और चार रुद्रप्रयाग में पाए गए. बचाए गए लोगों में ज्यादातर बाढ़ से बर्बाद हुई पनबिजली परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूर

छह चरवाहे और उनके मवेशी बह गए. कुछ गांवों के मकान भी डूब गए

जोशीमठ-मलारी राजमार्ग पर बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) का एक पुल और बाढ़ग्रस्त नदियों के दोनों तरफ के गावों को जोड़ने वाले दो 'झूला' पुल बह गए

तपोवन के पास धौलीगंगा पर एनटीपीसी की 520 मेगावाट की पनबिजली परियोजना पूरी तरह तबाह हो गई. यहां 900 मीटर लंबी सुरंग बनाने में सौ से अधिक मजदूर लगे थे. उनमें 20 मजदूरों को पानी का स्तर बढ़ने से पहले 150 मीटर की एक नई सुरंग खोदकर बचाया जा सका

जोशीमठ से प्रभावित क्षेत्रों में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की करीब 200 जवानों की दो टीमें रवाना की गईं. राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ), वायु सेना, थल सेना और उत्तराखंड की एजेंसियों की टीमें 200 लापता लोगों की तलाश और बचाव कार्य में जुटी हैं

विहंगम नजारा माप के लिए नहीं, कलाकार का चित्रांकन

*11 फरवरी, शाम 7 बजे तक

बातचीत | त्रिवेंद्र सिंह रावत

“आपदा परियोजनाओं की वजह से नहीं आई...और हम विकास की उपेक्षा नहीं कर सकते”

चमोली में मौजूदा आपदा से एक बार फिर हिमालय के संवेदनशील क्षेत्र में पनबिजली परियोजनाओं और दूसरी विकास योजनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं. लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री **त्रिवेंद्र सिंह रावत** की राय में आपदाओं के डर से विकास को रोका नहीं जा सकता. उनसे **अखिलेश पांडे** की बातचीत के अंश:

● 2013 की केदारनाथ घाटी आपदा से इस आपदा के बचाव कार्य में क्या फर्क था?

यह आपदा चट्टान खिसकने और हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने से हुई. यह सब दिन में हुआ, जब लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में मशगूल थे. केदार आपदा अत्यधिक बारिश से चोराबाढ़ी ग्लेशियर के झील में पानी बढ़ने और उसके टूटने से हुई थी. वह आपदा रात के समय आई. इसलिए बचाव की गुंजाइश कम थी लेकिन आपदा का पता दो दिन बाद चला था तो उसका असर कम करने का मौका नहीं था. वर्तमान आपदा रात में आई होती तो मजदूर बच जाते क्योंकि तब वे काम पर नहीं होते.

● क्या आपदा की पूर्व-चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया?

किसी विशेषज्ञ ने यह नहीं कहा था कि वर्तमान आपदा के क्षेत्र में कोई ऐसी नाजुक स्थिति बनी हुई है. सावधानी बरतने की तो हमेशा गुंजाइश बनी रहती है. लेकिन हैंगिंग ग्लेशियर टूट जाएगा, यह चेतावनी कभी किसी ने नहीं दी. प्राकृतिक गतिविधियों को कौन रोक सका है. हां, बचाव किया जा सकता है, जो इस दौरान किया गया तो साफ दिखा भी. जिस नंदा घुंघटी क्षेत्र में यह सब हुआ, उसको लेकर कभी किसी ने ऐसी आशंका व्यक्त नहीं की.

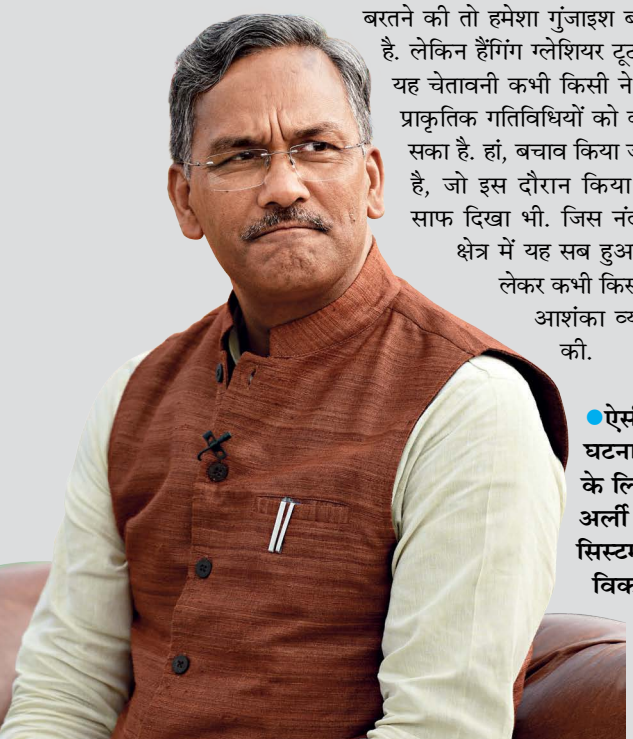

●ऐसी घटनाओं के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना क्या संभव नहीं है?

बिलकुल संभव नहीं है. हां, कुछ कंपनियों ने संवेदनशील क्षेत्रों की साल भर सैटेलाइट निगरानी का कोई सिस्टम विकसित किया है. मैंने अधिकारियों से कहा है कि वे इन कंपनियों से मालूम करें कि वे कैसे तबाही से बचाने में मदद कर सकती हैं. कहा गया है कि ये कंपनी साल का एक-डेढ़ करोड़ रुपया फीस लेती हैं. सरकार ऐसा करार करने को तैयार है.

● क्या इस क्षेत्र की पनबिजली परियोजनाओं के लिए बने बैराज के कारण तबाही अधिक हुई?

ये पनबिजली परियोजनाएं रन ऑफ द रिवर पर बनी हैं, न कि बड़े बांध बनाकर. इनमें छोटे बैराज टनल तक पानी डाइवर्ट करने के लिए बने हैं. ऐसे में यह कहना कि इन बैराज से तबाही ज्यादा हुई, झूठी बात है. सही यह है कि तपोवन में बने एनटीपीसी के बैराज ने तो इस तबाही को बड़ी होने से बचाया है, ठीक जैसे टिहरी बांध ने 2013 की अत्यधिक बारिश के वक्त पानी की बाढ़ रोककर अधिक तबाही होने से बचाया था.

● कई पर्यावरणविद् और विशेषज्ञ तो कह रहे हैं कि ये परियोजनाएं न होतीं तो तबाही नहीं होती. यह सरकारी तबाही है, ग्लेशियर को नाहक दोष दिया जा रहा है.

वहां न कोई बांध था, न कोई जलाशय. ये विशेषज्ञ अंदाज लगाकर कह देते हैं कि बिजली बन रही है तो बांध ही होगा. यह सोचना बिलकुल गलत है. ऋषिगंगा परियोजना भी रन ऑफ द रिवर पर है और तपोवन विष्णुगाड परियोजना भी. तपोवन विष्णुगाड परियोजना के बैराज ने तो निचले क्षेत्र को तबाही से बचाया, वरना सेलंग में नदी किनारे पनबिजली परियोजना के कैंप और उनमें रहने वाले लोग भी तबाह हो जाते.

● ग्लेशियर के नाजुकमिजाज की बाबत कोई सर्वे कराएंगे?

निश्चित तौर पर ग्लेशियर को लेकर अध्ययन कराने की महती आवश्यकता है, ताकि जानकारियां जुटाकर बर्बादी से बचा जा सके.

● क्या हिमालय की संवेदनशीलता को समझे बगैर पनबिजली परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी उचित है?

पर्यावरण मंजूरी तो सुप्रीम कोर्ट की हाइ पावर कमेटी देती है. सरकारों का इसमें कोई हाथ नहीं होता. एनजीटी पर्यावरण स्वीकृति देती है. जहां तक परियोजनाओं के संवेदनशील क्षेत्र में होने की बात है, तो वैज्ञानिकों की भी राय एक नहीं होती. एक्सपर्ट या वैज्ञानिकों को धरातल की स्थिति को जाने बगैर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. मैं स्वयं हामी हूं कि पर्यावरण का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन विकास भी उतना ही जरूरी है.

● क्या भविष्य में पनबिजली परियोजनाओं या दूसरी विकास योजनाओं के बारे में सरकार की नीति बदलेगी?

यह प्रश्न ही कहां पैदा है? आपदा कोई इन योजनाओं से आई? क्या हमारे पहाड़ों के लोकगीत आपदाओं के दृष्टांतों से भरे पड़े नहीं हैं? यह पहला मौका थोड़े ही है जब यहां आपदा आई. लेकिन इस डर से विकास की उपेक्षा करना भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते.

चंद्रदीप कुमार

मुश्किल मुकाम
चमोली जिले के रैणी गांव के पास पनबिजली परियोजना स्थल पर बचाव कार्य की तैयारी में जुटे एनडीआरएफ के जवान

एपी

वायु सेना और राज्य एजेंसियों की टीमें बचाव और निकासी कार्यों में लगी हुई हैं.

क्यों हुई तबाही?

आपदा किस वजह से हुई, अब तक इसका स्पष्ट कारण पता नहीं है. केंद्र और उत्तराखंड सरकार दोनों ने विशेषज्ञों को काम पर लगा रखा है. इनमें भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक भी शामिल हैं.

श्रीनगर में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध ग्लेशियोलॉजिस्ट (हिमनद विशेषज्ञ) एच.सी. नैनवाल का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र में कोई भी ग्लेशियर झील नहीं है. वे कहते हैं, ''हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है कि पानी कहां से आया.''

आइआइटी-इंदौर के ग्लेशियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर मोहम्मद फारूक आजम के अनुसार, ''ग्लेशियर विस्फोट कभी-कभार ही होते हैं. सैटेलाइट और गूगल अर्थ की तस्वीरों में भी कोई ग्लेशियर झील नहीं दिखती है, लेकिन इस क्षेत्र में ग्लेशियर के भीतर बड़ी झीलों की संभावना है. पानी का ऐसा ही कोई स्रोत फूट गया होगा, जिससे यह घटना हुई. लेकिन हमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मौसम और अन्य आंकड़ों के और अधिक विश्लेषण की आवश्यकता है.''

मौसम विभाग ने आपदा स्थल के आसपास 6-7 फरवरी को खुली धूप की सूचना दी थी. हालांकि हिमालय में हिमस्खलन आम है, लेकिन केवल हिमस्खलन से अलकनंदा की सहायक नदियों में जल स्तर में अचानक और इतनी खतरनाक वृद्धि होने की संभावना नहीं है. कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के भू-विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डैन शुगर ने आपदा के पूर्व और बाद में कैद की गई सैटेलाइट इमेज के साथ किए अपने कई ट्वीट में संभावना जताई है कि कोई बड़ी चट्टान खिसककर ग्लेशियर से टकराई हो सकती है, जिससे यह हादसा हुआ.

ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉ. डी.पी. डोभाल के अनुसार सात फरवरी की विभीषिका टूटे हैंगिंग ग्लेशियर से बनी कृत्रिम झील के बंध टूटने से हुई. उनके मुताबिक, सैटेलाइट इमेजरी से यही पता लग रहा है. डॉ. डोभाल ग्लेशियोलॉजी मिशन के तहत वाडिया इंस्टीट्यूट में स्थापित हिमालयन ग्लेशियोलॉजी सेंटर के डाइरेक्टर रहे और इस सेंटर को स्थापित करने में भूमिका निभाई. उन्होंने 2007 में ग्लेशियर में पड़ने वाली बरफ का आयतन मापने के लिए बांस के डंडों का उपयोग कर एक नई शुरुआत की, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली. उनके इस काम की सराहना *टाइम* पत्रिका ने भी की थी.

दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या को समझने और करोड़ों भारतीयों को जीवन देने वाले हिमालय की सुरक्षा और उस पर हो रहे पर्यावरण बदलावों के अध्ययन और वैकल्पिक अनुसंधानों को बढ़ाने के लिए डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने 2009 में 211 करोड़ रुपए के साथ हिमालयन ग्लेशियोलॉजी सेंटर की स्थापना की थी. लेकिन जून 2020 में इसे बंद कर दिया गया और उसका विलय वाडिया इंस्टीट्यूट में कर दिया गया. उत्तराखंड में 968 ग्लेशियर हैं, जो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में फैले हुए हैं.

विकास की कीमत

हालांकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी लेकिन कुछ विशेषज्ञ ग्लोबल वार्मिंग और उत्तराखंड की पारिस्थितिकी में निरंतर गिरावट को त्रासदी की वजह बता रहे हैं. इस घटना ने नंदादेवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में अनियंत्रित विकास कार्यों को सुर्खियों में ला दिया है. इन क्षेत्रों की बनावट ऐसी है कि चाहे वह निर्माण गतिविधि हो या जलवायु परिवर्तन, यहां की सभी नदियों में अचानक बाढ़ आने की आशंका बनी रहती है. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल (आइपीसीसी) की एक रिपोर्ट सहित कई अध्ययनों में इन क्षेत्रों में बर्फ के तापमान प्रोफाइल के बढ़ने की बात कही गई है. यह अब शून्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे है, जबकि एक समय शून्य से 20 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस नीचे तक का तापमान हुआ करता था. इससे बर्फ के जल्द पिघलने की आशंका काफी बढ़ जाती है.

जाहिर है, 2013 में उत्तराखंड में आई उस प्रलंयकारी बाढ़ से कोई सबक नहीं लिया गया, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी और अनुमानित 2,000 घरों, 1,300 सड़कों और 150 पुलों को नष्ट कर दिया था. अगले वर्ष, उत्तराखंड सरकार ने यूएनडीपी से प्राप्त इनपुट आधारित जलवायु परिवर्तन पर एक कार्य योजना तैयार की थी, लेकिन उस योजना को धरातल पर उतारे जाने के प्रमाण कम ही दिखते हैं.

एएनआइ

सबक सीखने से साफ इन्कार

क्या इस प्राकृतिक आपदा से कोई सबक लिया जाएगा, या विकास का लालच और आपदाएं लाएगा?

मीनाक्षी कंडवाल

बाढ़ में बर्बाद
धौलीगंगा के किनारे तबाह मकान

मृतकों की तलाश
गाद और मिट्टी से शव निकालते एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान

एएनआइ

उत्तराखंड का रैणी गांव. 7 फरवरी को आई आपदा का ग्राउंड जीरो. रैणी गांव के नीचे ही ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना थी, जिसका अब नामोनिशान मिट चुका है. लेकिन, कुदरत के कहर से दो-चार होने से पहले रैणी की पहचान गौरा देवी से थी. गौरा देवी ने 26 मार्च 1974 की सुबह चंद महिलाओं के साथ जंगल काटने पहुंचे ठेकेदारों से लोहा लिया था. ठेकेदार के आदमियों ने डराने-धमकाने के लिए बंदूक निकाली तो गौरा देवी महिलाओं समेत पेड़ से चिपक गईं और बोलीं, ''मारो गोली. पेड़ नहीं कटने देंगे.'' गांव में उनकी वीरता के सम्मान में बना स्मृतिद्वार बरबस ध्यान खींचता है.

लेकिन गांव के लोगों की आंखों में सवालों की ज्वाला फिर धधकने लगी है. गांव के बचन सिंह कहते हैं, ''हमने पावर प्लांट के खिलाफ कई शिकायतें दीं, आंदोलन चलाया. हमारी बात किसी ने नहीं सुनी. 1971 में हमने ऋषिगंगा में बाढ़ देखी थी, लेकिन इस बार हालात भयंकर थे.'' गौरादेवी के साथ चिपको आंदोलन में हिस्सा ले चुकीं कली देवी कहती हैं, ''कंपनी की वजह से बहुत नुक्सान हुआ है. अजीब-सा डर है. जाने कब क्या हो जाए. हमारी शिकायतों का कोई मतलब नहीं.''

उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को हुए भयानक हादसे ने विकास बनाम विनाश के द्वंद्व को फिर ताजा कर दिया है. हालांकि, राज्य में यह कोई पहला विनाशकारी हादसा नहीं था. उत्तराखंड में तो आपदाओं का लंबा इतिहास है. 1803 में आए 'गढ़वाल भूकंप' ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया था. आजादी के बाद 1951 में सतपुली में नयार नदी की बाढ़, 1979 में रुद्रप्रयाग के कौंथा में बादल फटने की घटना, 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप, 1998 में रुद्रप्रयाग तथा मालपा में भू-स्खलन, 1999 में चमोली तथा रुद्रप्रयाग में भूकंप, 2010 में बागेश्वर के सुमगढ़ में भू-स्खलन, 2012 में उत्तरकाशी तथा रुद्रप्रयाग में बादल फटने और भू-स्खलन जैसी घटनाएं प्रमुख हैं. 2013 की केदारनाथ त्रासदी ने तो प्राकृतिक आपदाओं के साए में उत्तराखंड के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए.

इन सबके बावजूद कमेटी और सिफारिशों के अलावा कुछ खास नहीं हुआ. उत्तराखंड की पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक और केदारनाथ त्रासदी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एक्सपर्ट कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा कहते हैं, ''मैंने तमाम रिसर्च के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी. एक सिफारिश यह भी थी कि जिन घाटियों का तल 2,000 मीटर से ज्यादा गहरा है, वहां बांध नहीं बनना चाहिए, इसलिए 23 बांध रद्द कर दिए जाएं. इनमें तपोवन विष्णुगाड वाला बांध भी था. लेकिन, हमारी रिपोर्ट के खिलाफ निर्माण कंपनियां कोर्ट में चली गईं और मामला लंबित है.''

केदारनाथ त्रासदी के बाद तो सुझावों का अंतहीन सिलसिला चला था. अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री के पूर्व वैज्ञानिक नवीन जुयाल कहते हैं, ''भूगर्भ संरचना को लेकर जो चिंता होनी चाहिए, वह नदारद है. 2013 केदारनाथ हादसे के बाद हम लोगों की एक कमेटी बनी थी, जिसका अहम उद्देश्य यह जानना था कि आपदा में पनबिजली परियोजनाओं की क्या कोई भूमिका थी? हमने शोध में पाया था कि नदियों के भीतर बंपर टू बंपर पावर प्लांट की श्रृंखला नहीं होती तो उस बाढ़ की तीव्रता इतनी मारक नहीं होती.''

लेकिन, आशंका के बावजूद विकास बनाम विनाश के बीच संतुलन की कोई ठोस रणनीति नहीं बन सकी. केदारनाथ त्रासदी को लेकर 4 सितंबर 2013 को लोकसभा में चर्चा के दौरान भाजपा की वरिष्ठ नेता दिवंगत सुषमा स्वराज ने कहा था, ''मैं मांग करती हूं कि गंगा मैया

पर बनने वाले सारे बांध निरस्त करिए. जितना भी पैसा उन पर खर्च हो चुका होगा, जो पैसा राहत और पुनर्वास पर खर्च होने वाला है, वह उससे कहीं कम होगा.'' इतना ही नहीं, उन्होंने केदारनाथ त्रासदी के बाद आपदा से निबटने में विफल रहने पर राज्य सरकार की लानत-मलामत की और कई सुझाव दिए थे. उन्होंने कहा था, ''एक तो पूरे उत्तराखंड की जीआइएस मैपिंग करवाइए. हर यात्री का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए. उसको एक माइक्रो चिप दीजिए ताकि उसकी लोकेशन का पता लग सके. सभी गांवों में पक्के हेलीपैड बनवा दीजिए. हर जिला अधिकारी के पास सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराइए. वहां ऑल-वेदर रोड्स बनाइए.''

कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाजपा अब केंद्र और राज्य में सत्ता में है, लेकिन न तो गंगा पर बनने वाले सारे बांध निरस्त हुए हैं और न सभी गांवों में हेलीपैड हैं. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कहते हैं, ''केदार हादसे के बाद हमने हिमालय सब मिशन बनाया था, जो बहुत महत्वपूर्ण था. लेकिन, उस पर काम आगे नहीं बढ़ सका.''

योजना आयोग ने 17 मार्च 1992 को डॉ. जे.एस. कासिम की अध्यक्षता में विशेषज्ञों का एक दल बनाया, जिसने पूरे हिमालय का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला था कि हिमालयी राज्यों का एक अलग मंत्रालय होना चाहिए. इस कमेटी की सिफारिशें अभी भी लंबित हैं. वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी 2014 में संसद में हिमालय नीति और अलग मंत्रालय की मांग की थी.

निशंक अब केंद्र में मंत्री हैं और मांग ठंडे बस्ते में है. वाडिया इंस्टीट्यूट, देहरादून के पूर्व ग्लैशियोलॉजिस्ट डॉ. डी.पी. डोभाल कहते हैं, ''नीति जब बनेगी, तब बनेगी. लेकिन अब कम से कम ग्लेशियर के अध्ययन को लेकर कोई अच्छा संस्थान बने. अब यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि जहां भी हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहां ग्लेशियर की क्या स्थिति है.''

जुयाल चेताते हैं, ''पनबिजली परियोजनाओं की भूख बढ़ती ही गई. बड़े-बड़े बांध बनाकर नदियों के स्वाभाविक बहाव को रोक दिया गया. फिर छोटे बांध बनाने लगे. जंगल तो काटा ही जाता है. ऊपरी हिमालय में नदियों का बहाव रोकना, आज नहीं तो कल तबाही का कारण बनेगा.''

इस वक्त उत्तराखंड में 41 हाइड्रो पावर प्रोजक्ट निर्माणाधीन हैं, जबकि 150 से ज्यादा प्रस्तावित हैं. लेकिन क्या चमोली में आई आपदा से हम चेतने को तैयार हैं? या फिर कुछ नई कमेटियां और उनकी सिफारिशों के बीच इस आपदा को भुला दिया जाएगा? ■

उत्तराखंड का पारिस्थितिकी तंत्र काफी नाजुक है, जिसका 71 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है. पिछले एक दशक में राज्य सरकारें विकास और पारिस्थितिकी वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाने की बातें कर रही हैं लेकिन बिजली पैदा करने के लिए नदियों को भारी पैमाने पर क्षति पहुंचाई गई है, नदी के किनारों पर बस्तियों का निर्माण हुआ है और सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लिए पहाड़ों में सुरंगें बनाई जा रही हैं.

मसलन, केंद्र और उत्तराखंड सरकार दोनों ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के तीर्थस्थलों को जोड़ने के लिए 816 किलोमीटर लंबे चार धाम राजमार्ग को पूरा करने का कार्य आक्रामक रफ्तार से आगे बढ़ा रहे हैं. मंजूरी को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के साथ राज्य प्राधिकरण और एनएचएआइ (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के बीच ठनी हुई है. एनजीटी चाहता है कि जंगलों और पहाड़ों को होने वाला नुकसान कम से कम रखने के लिए निर्माणाधीन सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर (फिलहाल यह 10 मीटर चौड़ी है) तक सीमित कर दी जाए. लेकिन 537 किमी लंबी सड़क पहले से ही बनकर तैयार हो चुकी है और मूल योजना में अब किसी भी तरह के बदलाव की संभावना बहुत कम है. उत्तरकाशी में गंगा आह्वान नागरिक मंच में सक्रिय तथा और भागीरथी पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र पर नजर रखने वालीं मल्लिका भनोट का कहना है कि चार धाम राजमार्ग निर्माण कम से कम समय में अधिक से अधिक ढलान-कटाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. वे बताती हैं, ''लंबी ढलानों-अमूमन 45 डिग्री से अधिक झुकाव वाले 60-70 मीटर तक ऊंचे स्थलों को स्थानीय भूगर्भीय संरचना पर विचार किए बिना काट दिया गया है. यह भारी जोखिम वाला है जो कई बड़े भूस्खलनों का कारण बना है.''

हाल के वर्षों में, इस पहाड़ी राज्य में बिजली उत्पादन के लिए जल संसाधनों के अधिकतम दोहन के बड़े प्रयास शुरू हुए हैं. करीब 200 बड़ी, मध्यम और छोटी पनबिजली परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास के विभिन्न चरणों में हैं. इस तरह की परियोजनाओं में भारी मात्रा में कंक्रीट का उपयोग होता है, जो गर्मी पैदा करता है और तापमान बढ़ाकर आसपास के क्षेत्र में हिमखंडों और ग्लेशियरों को अस्थिर करता है. नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो मंजू मेनन का कहना है कि उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग परियोजनाओं ने पहाड़ों को और अधिक नाजुक बना दिया है. वे कहती हैं, ''पारिस्थितिकी की बेहतर समझ न केवल पहाड़ों को बचाने में मदद करेगी बल्कि निवेशकों को अपनी परियोजनाओं के लिए सर्वोत्तम तकनीक के इस्तेमाल के लिए मार्गदर्शन भी करेगी.''

सुप्रीम कोर्ट में 2016 में दायर एक हलफनामे में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने कहा था कि उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों को जल विद्युत परियोजनाओं से दूर रखा जाना चाहिए. लेकिन उत्तराखंड अपनी मजबूरियों का हवाला देता है. राज्य में लगभग 3.8 गीगावाट बिजली पैदा होती है, लेकिन उसे राष्ट्रीय ग्रिड से अतिरिक्त बिजली खरीदने की जरूरत पड़ती है. राज्य सरकार अगले कुछ वर्षों में अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य रखती है.

जून 2018 में, उत्तराखंड हाइकोर्ट ने नदियों के किनारे अनुचित रूप से मलबे जमा करने के कारण राज्य में सभी जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2020 में, परियोजनाओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी, बशर्ते नदियों को बर्बाद किए बिना मलबे का निबटान किया जाए.

हालांकि मौजूदा आपदा की सटीक वजह की अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि हिंदुकुश हिमालयी क्षेत्र में 8,000 से अधिक हिमनदीय (ग्लेशियल) झीलें मौजूद हैं, जिनमें से 200 खतरनाक हैं. अकेले उत्तराखंड में करीब 1,000 हिमनदीय झीलें हैं. चमोली में हिमनद के टूटने से हुई यह त्रासदी तब तक एक आखिरी त्रासदी नहीं होगी जब तक कि देश के पहाड़ी राज्य अपने विकास मॉडल का पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई, हिमालय और उसकी नाजुक पारिस्थितिकी का चौबीस घंटे मूल्यांकन और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के आकलन के लिए अधिक वैज्ञानिक तरीके अपनाना शुरू नहीं करते.

जाहिर है, समस्या विकराल होती जा रही है और फौरन कदम नहीं उठाए गए तो और बड़ी आपदा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. अगर 2013 में केदारनाथ आपदा से ही सबक लिया गया होता तो आज कुछ हद स्थितियां काबू में आ गई होतीं. लेकिन उससे सबक लेने के बदले पनबिजली परियोजनाओं और सड़क निर्माण में जैसी तेजी दिखाई जा रही है, उस पर फिर नए सिरे से विचार करने का वक्त आ गया है. —साथ में, **अखिलेश पांडे**

दक्षिण की जंग

यह तमिलनाडु विधानसभा का पहला चुनाव है जो बरसों छाए रहे कद्दावर नेताओं के बगैर लड़ा जाएगा. लेकिन मुकाबला अब भी दो दिग्गज द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआइएडीएमके के बीच है. इसमें राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका सीमित ही रहती दिख रही है

अमरनाथ के. मेनन

भ्रष्टाचार के आरोपों में बेंगलूरू की जेल में बंद विवेकानंद कृष्णावेणी शशिकला चार साल बाद रिहा होकर 9 फरवरी को पौ फटने के कुछ ही वक्त बाद चेन्नै लौटीं. समर्थकों के साथ गद्दीनशीन एआइएडीएमके (ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम) के कुछ नेताओं ने उनकी जोरदार अगवानी की. शुभचिंतकों ने रास्ते में कई जगहों पर आतिशबाजी और फूलों से 66 वर्षीय नेता का अभिनंदन किया (यह भी एक वजह थी कि आमतौर पर छह घंटे के सफर में लगभग पूरा दिन लग गया). रास्ते में वे कुछेक मंदिरों में भी रुकीं. एक जगह तो उन्हें इतनी भारी-भरकम फूलमाला भेंट की गई कि उसे उनके पास लाने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा.

एआइडीएमके से टूटकर अलग हुए धड़े अम्मा मक्काल मुनेत्र कड़गम (एएमएमके) और पार्टी के भीतर उनके वफादारों ने इस पूरे प्रदर्शन का इंतजाम किया. अप्रैल-मई में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की दौड़ में खुद को जयललिता की वारिस के तौर पर पेश करते हुए शशिकला ने अपने समर्थकों से कहा, ''पार्टी ने पहले भी कई संघर्ष किए हैं, लेकिन हमेशा फीनिक्स की तरह राख झाड़कर उठ खड़ी हुई है. अम्मा (दिवंगत जे. जयललिता) ने हमें बताया था कि उनके बाद अगले 100 सालों तक एआइएडीएमके को कैसे चलाना है और उनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ाना है. मैं अपनी बाकी जिंदगी पार्टी के विकास के लिए जिऊंगी. पार्टी ही परिवार है और परिवार ही पार्टी है...जयललिता के सारे बच्चे मेरे भी बच्चे हैं.''

सत्तारूढ़ एआइएडीएमके के लिए चिंतित होने की वजह है. 2011 के बाद हरेक चुनाव में उसकी वोट हिस्सेदारी कम होती गई है. 2019 के लोकसभा चुनाव में तो यह 18.7 फीसद के रसातल पर पहुंच गई. फिर

फोटो इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

10 साल से सत्ता में होने की वजह से सत्ता-विरोधी भावना भी है. लिहाजा तेजी से बदले की कार्रवाई करते हुए एआइएडीएमके ने उन पार्टी सदस्यों को निकाल बाहर किया, जिन्होंने जेल से वापसी पर शशिकला की अगवानी के लिए पलक-पांवड़े बिछाए थे. साफ इशारा था कि 'चिन्नम्मा' (मौसी), जैसा कि उनके साथी आदर से उन्हें कहते हैं, अब भी बहिष्कृत हैं.

बीते कुछ दिनों में शशिकला के प्रदर्शन ने एआइएडीएमके और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के बीच विधानसभा चुनाव की उस लड़ाई से ध्यान हटा दिया जो आने वाले दिनों में पहली बार उनके कद्दावर नेताओं जे. जयललिता और एम. करुणानिधि के बगैर लड़ी जाएगी. द्रविड़ राजनीति की दोनों बड़ी पार्टियां लंबे वक्त से इन कद्दावर शख्सियतों के भरोसे रही हैं, जिनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूजा करते थे. इस बार डीएमके मुख्यमंत्री पद के अपने उम्मीदवार के तौर पर करुणानिधि के बेटे एम.के. स्तालिन को पेश कर रही है, जबकि एआइएडीएमके भी गद्दीनशीन ई.के. पलानीस्वामी (ईपीएस) को सीएम पद का उम्मीदवार बना रही है.

सत्ता विरोधी भावना की चुनौती

मुख्यमंत्री पलानीस्वामी खास तौर पर कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं क्योंकि एआइएडीएमके लगातार तीसरा कार्यकाल जीतने की कोशिश कर रही है. वे भी जयललिता की विरासत की दुहाई दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों के दिलों में गूंजती है. साथ ही निवेश आकर्षित करने और राजकाज में अपना रिकॉर्ड भी सामने रख रहे हैं. इसमें कई कल्याणकारी उपाय और खास तौर पर किसानों के लिए ''तमाम कर्ज माफियों की अम्मा'' भी है. 5 फरवरी को इसका ऐलान किया गया, जिसमें 12,110 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज माफी की बात कही गई जिसका फायदा 16.4 लाख किसानों को मिलेगा. यह खैरात बांटने की वही राजनीति है जो द्रविड़ पार्टियां 1960 के दशक के शुरू से ही करती आई हैं. इसकी शुरुआत डीएमके के पहले मुख्यमंत्री सी.एन. अन्नादुरै ने 'प्रति मद्रास तौल (एक किलो से कुछ कम) एक रुपए' चावल से की थी. पलानीस्वामी कहते हैं, ''मैं किसान हूं. मैंने किसानों के बकाया फसल कर्ज केवल इसलिए माफ किए क्योंकि मैं किसानों की मुश्किलें दूर करना चाहता था.''

पलानीस्वामी ने चतुराई से ओ. पन्नीरसेल्वम के साथ अपनी अदावत खत्म की और उनके नेतृत्व वाले धड़े को वापस लाकर अन्नाद्रमुक में टूट पर विराम लगा दिया

हालांकि खैरातों और रेवड़ियों का कुल जमा असर यह हुआ है कि तमिलनाडु 2012 से 2019 के बीच अतिरिक्त राजस्व वाले राज्य से घाटे वाले राज्य में बदल गया. अच्छी बात यह है कि 15वें वित्त आयोग की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सतत विकास लक्ष्यों के कई पैमानों, मसलन-गरीबी उन्मूलन, अच्छा स्वास्थ्य और कुशलता और अच्छी शिक्षा पर दौड़ में आगे रहा है.

विकास के मुद्दे पर जोर देते हुए ईपीएस कोविड-19 के शुरुआती दिनों से ही राज्य में व्यापक दौरे कर रहे हैं. वे जोर-शोर से कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान नियंत्रण के उपायों को लागू करने में राज्य दूसरों से आगे रहा (चेन्नै के कोयंबेडु बाजार को छोड़कर, जिसने बहुत ज्यादा संक्रमण फैलाया). अपनी रैलियों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह एआइएडीएमके ''अम्मा के पदचिन्हों पर चल रही है'', लोगों की भलाई के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और किस तरह निवेश लाई है और नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं. बेशक अम्मा आज भी तमाम योजनाओं में सबसे अहम हैं और इसलिए ईपीएस राज्य भर में जयललिता के स्मारक और प्रतिमाओं का उद्घाटन करते रहे हैं.

तमिलनाडु की राजनीति में ईपीएस का सियासी सफर न तो उतना लंबा है और न ही उतना समृद्ध जितना उनसे महज एक साल बड़े डीएमके प्रमुख स्तालिन का है. पेशे से किसान ईपीएस 1980 के दशक में एआइएडीएमके में आए और 1987 में संस्थापक एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) के निधन के बाद पार्टी में फूट पड़ी तब उन्होंने जयललिता के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी. एआइएडीएमके के भीतर उन्हें काम करने वाला माना जाता है और राज्य प्रशासन में व्यावहारिक तथा जमीन से जुड़ा राजनीतिज्ञ. इससे उन्हें मुख्यमंत्री की भूमिका में खुद को सुचारु ढंग से ढालने में मदद मिली. मगर 2017 के घटनाक्रम के बाद लोग उनसे चौकन्ने भी हो गए हैं. उन्होंने जिस तरह जयललिता की असामयिक मौत के बाद कमान संभाल रही शशिकला का विश्वास जीता या उनके हाथों मुख्ममंत्री के पद के लिए चुने जाने के बाद भी वे उनके खिलाफ हो गए, यह सब अब पार्टी की किंवदंतियों और इतिहास में दर्ज है.

फिर जिस चतुराई से उन्होंने अपने से पहले मुख्यमंत्री के पद पर आसीन ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) के साथ अदावत खत्म की, ओपीएस की अगुआई वाले धड़े को वापस एआइएडीएमके में ले आए और जयललिता के बाद पार्टी के टूटने की आशंकाओं को उन्होंने टाल दिया, वह भी सबने देखा. यह सब करते हुए उन्होंने सरकार की कमान भी संभाली और राजकाज के लक्ष्यों से कभी अपना ध्यान डिगने नहीं दिया. शुरुआत में ईपीएस भले ही कम जाने-माने नेता रहे हों, लेकिन इत्तेफाकन मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने चतुर अवसरवाद के साथ पूरा फायदा उठाया और आज अपनी यात्राओं और प्रचार-प्रसार के जरिए जाना-पहचाना चेहरा बन गए हैं.

द्रविड़ राजनीति के गढ़

मगर 10 साल सत्ता में होने के अपने नुक्सान हैं और डीएमके प्रमुख स्तालिन इसी का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं. पिछले साल मार्च से ही वे पूरे जज्बे और बारीकी से अभियान चलाते आ रहे हैं. 67 वर्षीय स्तालिन 1970 के दशक से ही सियासत में हैं, वे चेन्नै के मेयर रहे हैं और अपने पिता के मातहत उपमुख्यमंत्री भी रहे हैं और अब पार्टी अध्यक्ष के नाते डीएमके के निर्विवाद नेता हैं.

2016 के पिछले विधानसभा चुनाव से पहले स्तालिन ने राज्य भर में जमीनी हकीकतों का जायजा लेने के लिए पांच से ज्यादा महीनों तक 1,100 किमी का सफर करते हुए 'नमक्कू नामे (हमारे द्वारा, हमारे लिए)' रोडशो किया था. इस दौरे से स्तालिन जन नेता के तौर पर प्रस्तुत हुए, लेकिन फिर भी डीएमके गठबंधन बहुत थोड़े (40.9 के मुकाबले 39.8 फीसद वोट हिस्सेदारी के साथ महज एक फीसद वोटों के) अंतर से एआइएडीएमके से 2016 का विधानसभा चुनाव हार गया. एआइएडीएमके ने 234 सदस्यों की विधानसभा में 136 सीटें हासिल करके दूसरा कार्यकाल जीता जबकि डीएमके ने 89 सीटें जीतीं, लेकिन सहयोगी दलों की तरफ से उसे मायूस होना पड़ा, जिनमें कांग्रेस भी शामिल थी जो महज आठ सीटें जीत सकी.

तमिलनाडु की राजनीतिक आकाशगंगा

सहायक कलाकार

तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य पर मुख्यतः द्रविड़ राजनीति के दो प्रमुख दल द्रमुक और अन्नाद्रमुक ही हावी रहते हैं. कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा, जाति/समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कई अन्य दलों की हैसियत सहायकों की भूमिका निभाने मात्र की ही रही है. इन छोटे खिलाड़ियों के बीच कुछ दल ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में एक प्रतिशत से अधिक वोट हासिल किए हैं:

पट्टालि मक्कल काच्चि (पीएमके)

एस. रामदास

पीएमके के संस्थापक आरएसएस के प्रशंसक रहे हैं और चाहते हैं कि उनका काडर भी आरएसएस के तौर-तरीके अपनाए

उत्तरी तमिलनाडु की एक दबंग ओबीसी जाति वन्नियार की इस पार्टी के पास 5 प्रतिशत वोट हैं. पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा करने के लिए जानी जाती है. आर्थिक विकास से ग्रामीण तमिलनाडु में वन्नियार बड़ी खेतिहर जाति के रूप में उभरे हैं. पार्टी ने 2016 के विधानसभा या 2019 के लोकसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीती थी.

देसिय मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके)

विजयकांत

अभिनेता, जिन्हें 'करुप्पु (अश्वेत) एमजीआर' के रूप में भी जाना जाता है, बीमार हैं; पार्टी को अब उनकी पत्नी और पार्टी की कोषाध्यक्ष प्रेमलता चलाती हैं.

डीएमडीके 41 सीटों की मांग कर रही है. एआइएडीएमके से 2011 में इसे इतनी ही सीटें मिली थीं (तब उसने 29 सीटें जीत भी लीं थी). उसके बाद से पार्टी बुरे दौर में है. यह 2016 के विधानसभा चुनाव या 2019 के लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत सकी.

मरुमलारची द्रविड मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके)

वाइको

लंबे समय तक राज्यसभा सांसद रहे करुणानिधि के पूर्व सहयोगी, श्रीलंकाई तमिलों के अधिकारों के कट्टर समर्थक हैं

डीएमके से टूटकर बनी यह पार्टी कई सालों तक अस्तित्व के संघर्ष और 2016 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद वापस डीएमके के पास लौट आई. डीएमके के साथ गठबंधन के बाद वाइको की पार्टी, 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके के चुनाव चिन्ह पर एक सीट जीतने में सफल रही. यह चुनाव, एमडीएमके अपने चुनाव चिह्न पर लड़ सकता है.

विदुतलाई चिरुतैगल काच्चि (वीसीके)

तोल. तिरुमावलावन

लड़ाका मिजाज वाले हैं और दलित अधिकारों तथा तमिल राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष करते हैं

पूर्व में दलित पैंथर्स के नाम से जाना जाने वाला वीसीके एक गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल है. पीएमके के साथ इसके टकराव के कारण दलितों और वन्नियारों के बीच लगातार हिंसक झड़पें होती रही हैं. 2019 में डीएमके की मदद से थिरुमावलवन लोकसभा के लिए चुने गए.

इन पार्टियों में पीएमके और डीएमडीके के अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन करने के आसार हैं. भाकपा और माकपा समेत अन्य दल डीएमके के पक्ष में वोट ट्रांसफर करते हैं जिनका छोटा लेकिन स्थायी वोट आधार है.

अब भी ताकतवर
9 फरवरी को चेन्नै आने पर शशिकला की कार को उनके समर्थकों की भीड़ ने घेर लिया

2021 के चुनाव के लिए स्तालिन केवल रोडशो के भरोसे नहीं हैं. फरवरी 2020 में उन्होंने पार्टी दिग्गजों के शको-शुबहों को दरकिनार कर प्रशांत किशोर की इंडियन पोलिटिकल एक्शन कमेटी (आइ-पीएसी) की सेवाएं लीं, ताकि कोविड-19 की वजह से ग्रामीण इलाकों में चुनाव अभियान के लिए आना-जाना नामुमकिन हो जाने के बाद समर्थन जुटाने की बिल्कुल नई रणनीतियां बना सकें. शुरुआती दिनों में स्तालिन ने 'ओनद्रिनैवम वा (संग-साथ की ताकत)' अभियान चलाया और इससे प्रवासी मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों और बेघरों तक पहुंचे जिनकी जिंदगियां लॉकडाउन की वजह से तहस-नहस हो गई थीं. कोई भी जरूरतमंद स्तालिन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकता था और पार्टी का एक कार्यकर्ता उसकी जरूरत पूरी करने के लिए उसके पास पहुंच जाता.

साथ ही डीएमके ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान 'एल्लोरम नाम्मुदन (सब हमारे साथ हैं)' भी शुरू किया जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टी सदस्य के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाया. स्तालिन कहते हैं कि यह अभियान समान विचारों वाले लोगों को साथ लाने के लिए था ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता से जुड़े मुद्दों से निबटा जा सके. इसके साथ पार्टी ने उस प्रक्रिया को भी आसान और कारगर बना लिया है जिसमें जिला सचिव नेता के साथ जुड़ते और मुद्दों पर चर्चा करते हैं. यह दोतरफा संवाद केवल पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच ही नहीं होता, बल्कि दूसरे समर्थकों और शुभचिंतकों के बीच होता है.

डीएमके ने 'विदियुम वा (फिर सुबह होगी)' कार्यक्रम के तहत तमिल समाज के विकास के लिए काम करने वाले लोगों की पहचान की और उन्हें स्तालिन के दस्तखत वाले व्यक्तिगत प्रशंसा पत्र भेजे. वे स्तालिन एएनआइ ऐप भी लेकर आए जिस पर आम लोग पार्टी नेता से जुड़ सकते हैं और पार्टी से जुड़ी खबरें और आयोजन भी साझा कर सकते हैं.

नवंबर आते-आते डीएमके प्रमुख पार्टी के चुनाव प्रचार रफ्तार देने के लिए 10,000 से ज्यादा चुनिंदा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सिलसिलेवार वर्चुअल पार्टी बैठकें कर रहे थे, जिन्हें 'तमिलगम मीटपोम (तमिलनाडु को वापस पाना)' नाम दिया गया. सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्तालिन ने कहा, ''हमारा लक्ष्य मिशन 200 (विधानसभा सीटें) है. सरकार बनाने के लिए हमें बस 117 सीटें चाहिए लेकिन उससे हमें गर्व नहीं होगा. हम 200 से कम सीटें कतई स्वीकार नहीं कर सकते.''

पार्टी की छवि में चार चांद लगाने के लिए 'नैल्लोर कूडम (हम सब)' अभियान शुरू किया गया है जो एक किस्म का राहत कार्यक्रम है. इसमें विभिन्न इलाकों के गरीब लोगों को खाना पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों को स्थानीय रसोईघरों से जोड़ा गया है. पार्टी ने व्हाट्सएप पर मोहल्लों के समूह बनाए हैं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके. राज्य भर के दस लाख से ज्यादा परिवारों को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है. इसमें शक नहीं कि इस चुनाव में डीएमके और एआइएडीएमके के

कुछ डीएमके नेताओं को लगता है कि अगर सहयोगी दल सीट बंटवारे पर मतभेद के चलते गठबंधन से बाहर हो जाएं तब भी उनके वोट पार्टी को मिलेंगे. आशंका है कि सहयोगी दल अपने खाते में आई सीटें जीत न सकें

बीच कड़ा मुकाबला होगा. डीएमके ने 39 में से 38 सीटें हथियाकर 2019 का लोकसभा चुनाव एकतरफा जीत लिया था. बाद में उसने स्थानीय निकायों के चुनाव भी जीते, जिसमें एआइएडीएमके ने एक तरह से कुछ वापसी जरूर की लेकिन दूसरे नंबर पर (डीएमके के 243 के मुकाबले 214 से ज्यादा जिला पंचायत वार्डों के साथ) रही थी. इसी से आने वाला चुनावी मुकाबला कड़ा हो गया है. दोनों पार्टियां साझा चुनौतियों से भी जूझ रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती सहयोगी दलों को संभालना है. बीते सालों के दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों दिल्ली में अपने दम-खम के बल पर राज्य में अपने फीके पड़ते दबदबे की भरपाई करने की कोशिश करती रही हैं. लेकिन अभी तक वे द्रविड़ राजनीति के गढ़ों में बड़ी सेंध नहीं लगा पाई है. दोनों सीटों का ज्यादा बड़ा हिस्सा हासिल करने की कोशिश करेंगी, लेकिन डीएमके और एआइएडीएमके को बहुत-से छोटे दलों को भी साथ जोड़े रखना और जगह देना है. उनके लिए एक मुश्किल यह भी है कि भाजपा (3 फीसद से कम) और कांग्रेस (10 फीसद से कम) दोनों ही पिछले दो विधानसभा चुनावों में ठीक-ठाक वोट भी हासिल नहीं कर पाई थीं. हाल में भाजपा ने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिली. राजनैतिक टीकाकार एन. सत्यमूर्ति कहते हैं, ''राजनैतिक नजरिए से द्रविड़ राजनीति ने अपनी चतुराई से हिंदुत्व के नेताओं को मात दे दी है. हिंदुत्व के अगुआ पहले तीसरे विकल्प के तौर पर रजनीकांत को उछालकर और फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को राजनैतिक-चुनावी ताकत के तौर पर पेश कर डीएमके और अन्नाद्रमुक को पीछे धकेल देने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह सब उस तरह कामयाब नहीं हो पाया जैसी उन्होंने उम्मीद की थी.''

साल 2020 में भाजपा के मंसूबे वाकई पूरे नहीं हो सके, चाहे वह वेल यात्रा हो, जिसमें उसने हिंदुत्व की सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का जतन किया या एआइएडीएमके के मुकाबले रजनीकांत को खड़ा करने की कोशिश हो. रजनीकांत ने बीते साल के ज्यादातर वक्त हरेक की उत्सुकता को जिलाए रखने के बाद आखिर में राजनीति से किनारा कर लिया और भाजपा को एआइएडीएमके से जुड़ी और उसकी कृपा की मोहताज पार्टियों की कतार में लौटने को मजबूर कर दिया.

दो बड़ी द्रविड़ पार्टियों के दबदबे ने हाल के दशकों में कई छोटी पार्टियों को जन्म दिया है, जो अपनी मांगें मनवाने के एवज में गठबंधनों को मजबूत करने को हमेशा तैयार रहती हैं. उनमें ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने 2011 से या तो अपने दम पर या दोनों बड़ी पार्टियों के कंधे पर सवार रहकर एक फीसद या उससे कुछ ज्यादा वोट हासिल किए हैं और 2021 में फिर सीटों के लिए बातचीत कर रही हैं. दोनों ही गठबंधन एक-एक वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए उन्हें अपने सहयोगी दलों को गंभीरता से लेना पड़ रहा है. 1989 से तमाम दलों को मिले वोटों के एक विश्लेषण से पता चलता है कि एआइएडीएमके और डीएमके दोनों ने मिलाकर हरेक चुनाव में 60 फीसद या उससे भी ज्यादा वोट हासिल किए हैं. गठबंधनों के भागीदार दलों के वोट भी जोड़ लिए जाएं तो दोनों बड़ी द्रविड़ पार्टियों और उनके सहयोगी दलों ने 70 और 89 फीसद के बीच वोट हासिल किए.

अम्मा के नाम पर

पार्टी आइकन के नाम का भरपूर इस्तेमाल, आगामी चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक की मुख्य रणनीति है

चेन्नै के मरीना बीच पर 80 करोड़ रुपये की लागत से अमर पक्षी फीनिक्स की आकृति वाला जे. जयललिता का स्मारक दूर से ही नजर आता है. यह मरीना बीच पर ही स्थित उनके राजनीतिक पूर्ववर्तियों—सी.एन. अन्नादुरै, एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) और एम. करुणानिधि के स्मारक से बड़ा है.

अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में 27 जनवरी को सीएम ई. के. पलानीस्वामी के हाथों स्मारक का उद्घाटन सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक का एक रणनीतिक कदम था. स्मारक परिसर में एक संग्रहालय और एक नॉलेज पार्क है, जो जयललिता के व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन के बारे में डिजिटल अनुभव और प्रभावी सामग्री प्रदान करता है. यह परिसर 24 फरवरी को अम्मा की जयंती पर जनता के लिए खुलेगा.

अप्रैल 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्मारक के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. याचिका में तर्क दिया गया था कि चूंकि जयललिता आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी थीं, इसलिए राज्य को उनके स्मारक निर्माण के लिए सरकारी खजाने से पैसा खर्च नहीं करना चाहिए. यह अपील पहले मद्रास हाइ कोर्ट में की गई थी जिसे 2019 में अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उनकी मौत के बाद 'दोषी' का टैग हट चुका है. उसके बाद शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर की गई थी. स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर पलानीस्वामी ने कहा, ''डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने स्मारक का विरोध करने के लिए एक बेनामी का इस्तेमाल किया. यह उनकी बुरी मंशा को दर्शाता है.''

अगले दिन, सीएम ने चेन्नै में एक अन्य स्मारक अम्मा के घर—वेदा निलयम- का भी उद्घाटन किया. हालांकि, जनता के लिए स्मारक खोलने के खिलाफ मद्रास हाइ कोर्ट के आदेश के मद्देनजर, यह कार्यक्रम उतना बड़ा नहीं था. जयललिता के कानूनी वारिस, भतीजी जे. दीपा और भतीजे जे. दीपक ने इस आधार पर उद्घाटन पर आपत्ति जताई थी कि बंगले के अंदर मौजूद संपत्ति की सूची उनकी उपस्थिति में नहीं बनाई गई थी.

4 फरवरी को जयललिता के स्मारक के निर्माण के लिए पारित अधिनियम के खिलाफ जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने कहा, ''हम अनादर नहीं कर रहे लेकिन आप एक के बाद एक, हर मुख्यमंत्री के लिए ऐसा नहीं कर सकते.'' हालांकि, पलानीस्वामी के लिए चुनाव में अन्नाद्रमुक की खातिर अम्मा की स्मृति बनाए रखना आवश्यक है. सरकार की मौजूदा तिरुवल्लुवर विश्वविद्यालय को द्विभाजित करके जयललिता के नाम पर नया विश्वविद्यालय स्थापित करने की भी योजना है. अम्मा संसार भले न हों, लेकिन स्मृतियों से कभी विदा नहीं होंगी.

व्यापक असर
जयललिता के स्मारक का उद्घाटन करते ईपीएस

एएनआइ

एआइएडीएमके के गठबंधन में (भाजपा के अलावा) पट्टालि मक्कल काच्चि (पीएमके) और देसिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) के शामिल होने की संभावना है, जिन्होंने ऐसी मांगें पेश की हैं जिन्हें पूरा करना आसान होगा. पीएमके पास पक्के 5.5 फीसद वोट हैं, जिन्हें वह दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में दिलवा सकती है जबकि भाजपा के पास करीब 2.9 फीसद वोट है (2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक). डीएमडीके को शामिल करने पर एआइएडीएमके बहुत ज्यादा उत्सुक दिखाई नहीं देती क्योंकि वह हमेशा ऐसी मांगें करती है जो वोटों की शक्ल में उसके जनसमर्थन के मुकाबले बहुत भारी-भरकम होती हैं.

पीएमके वनियारों की पार्टी है जो उत्तर तमिलनाडु में दबदबा रखने वाला ओबीसी धड़ा है. यह सबसे पिछड़े वर्गों में अलग कोटे की मांग कर रही है. जहां तक डीएमडीके की बात है, पार्टी की कोषाध्यक्ष और इसके संस्थापक अभिनेता विजयकांत की पत्नी प्रेमलता विजयकांत 41 सीटें मांग रही हैं. 2011 में एआइएडीएमके ने इतनी सीटें उसे दे दी थीं. उस वक्त डीएमडीके ने 29 सीटें जीती थीं और डीएमके को तीसरे नंबर पर धकेलकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. उसके बाद अकेले लड़ते हुए डीएमडीके ने किसी बड़े चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती है.

इस पूरे घालमेल में शशिकला क्या करेंगी? पूरे 25 साल जयललिता की सहयोगी के तौर पर काम करते हुए उन्होंने अपने को राजगद्दी के पीछे की असल ताकत के तौर पर विकसित किया है और वे यह दिखाने को आमादा हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में वे अब भी मजबूत ताकत हैं. शशिकला 2027 तक किसी भी निर्वाचित पद पर आसीन होने से अयोग्य करार दी जा चुकी हैं, पार्टी से निष्कासित कर दी गई हैं और उनकी कानूनी मुश्किलें जारी हैं. लिहाजा पार्टी को लेकर या अपनी संपत्तियां फिर हासिल करने के लिए कोई कदम उठाने से पहले उन्हें इन चुनौतियों से निबटना होगा. विश्लेषकों का कयास है कि वे वक्त लेंगी और चुनाव नतीजों का इंतजार करेंगी. अगर एआइएडीएमके चुनाव हार जाती है, तो कभी संयोग से उनकी छत्रछाया में पले-बढ़े मौजूदा नेतृत्व को कठघरे में खड़े करने का मौका उन्हें मिलेगा और तब वे बदलाव की मांग करेंगी.

जहां उनकी अगवानी में खड़े होने वाले एआइएडीएमके नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी की कार्रवाई जारी है, वहीं चेन्नै की दीवारों पर शशिकला के पोस्टर नमूदार हो रहे हैं, जो इस मुद्दे पर पार्टी के दोफाड़

खास बातचीत
एम.के. स्टालिन

"हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ देने की इच्छा से प्रेरित हैं"

जैसन जी.

● डीएमके (द्रमुक) के लिए यह चुनाव पिछले चुनावों से अलग कैसे है?

तमिलनाडु एक समृद्ध राज्य था और अन्नाद्रमुक ने पिछले 10 वर्षों के शासन में इसकी प्रगति बाधित कर दी. मैं एआइएडीएमके के शासन को पझाईपोना पथु वरुडांगल (बर्बादी के 10 साल) के रूप में परिभाषित करूंगा. इसने राज्य के अधिकारों का केंद्र के सामने पूरी तरह समर्पण कर दिया और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है. राज्य सरकार को 50 प्रतिशत अन्नाद्रमुक और 50 प्रतिशत भाजपा चलाती है—यही तथ्य विधानसभा चुनाव को हमारे लिए अलग बनाता है. लोग तमिलनाडु की गरिमा फिर स्थापित करने के लिए द्रमुक की ओर देख रहे हैं.

● आपके अभियान में नए तत्व क्या हैं और रणनीति कैसे अलग होने वाली है?

पिछले पांच वर्षों में मैं और मेरे साथी लगातार लोगों के बीच रहे हैं, उनसे संवाद किया है ताकि उनकी चिंताओं, सपनों और आकांक्षाओं को समझ सकें. सबसे बड़ी तारीफ तो हमें खुद मुख्यमंत्री से मिली जो हमारी ओर से उठाए गए हर मुद्दे को दोहराते हैं और हमारे हर वादे की नकल करते हैं. विपक्षी पार्टी होने के बावजूद, हम लोगों से याचिकाएं प्राप्त कर रहे हैं और हमने आश्वासन दिया है कि सत्ता में आने के पहले 100 दिनों के भीतर समस्याओं को संबोधित किया जाएगा. हजारों की तादाद में मिली याचिकाएं प्रमाण हैं कि जनता का हम पर कितना भरोसा है और वह हमें जीतते हुए देखने को उत्सुक है.

● जनता को द्रमुक के पक्ष में वोट करने के वास्ते आप क्या वादे कर रहे हैं?

मेरा पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा है कि वर्तमान अन्नाद्रमुक सरकार ने राज्य के हितों को केंद्र के पास गिरवी रख दिया है, उसे वापस लाने और तमिलनाडु के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कुछ भी करने की जरूरत हुई वह करूंगा. मेरा दूसरा वादा है कि लोगों की बातें धैर्य से सुनूंगा—मैं यहां हूं और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा, चाहे वह महामारी हो या और कोई स्थिति. मेरा तीसरा वादा यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद सरकारी मदद से वंचित न रहने पाए.

● द्रमुक को इस चुनाव के लिए एक राजनीतिक रणनीतिकार को काम पर क्यों लगाना पड़ा है? पार्टी की तरक्की और समर्थन बढ़ाने में उनका किस प्रकार का योगदान मिल रहा है?

हम पार्टी के दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से लोगों के बीच रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं और विशेषज्ञों को जिम्मेदारी देने की इच्छा से प्रेरित हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने और तमिलनाडु के लोगों को सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने में मदद मिले. यह उन सब चीजों पर लागू होता है जो कुछ हम करते हैं और यह तब भी लागू होगा जब हम लोगों के आशीर्वाद से अपनी सरकार बना लेंगे.

पी.आर.ओ.

जनता की ताकत
मदुरै में एमएनएम के रोड शो के दौरान कमल हासन; और राहुल गांधी (नीचे) करूर में कांग्रेस की रैली के दौरान एक लड़की की मदद करते हुए

ट्विटर/@

होने की तरफ इशारा करते हैं. कइयों का कहना है कि उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम, जो कई मुद्दों पर ईपीएस के साथ इत्तेफाक नहीं रखते, दबाव में आकर शशिकला को दबा-छिपा समर्थन दे सकते हैं. ऐसा तब और भी हो सकता है जब थेवर समुदाय (शशिकला भी थेवर समुदाय की हैं) के उनके समर्थकों को पर्याप्त तादाद में पार्टी टिकट नहीं दिए जाते हैं. शशिकला के साथ टूटकर गए धड़े ने अपनी चुनावी योजनाओं का ऐलान अभी नहीं किया है.

इसके बावजूद, शशिकला के पास एआइएडीएमके नेताओं को चुनाव के अपने मंसूबों पर बढ़ने से रोकने की कम से कम अभी न तो इच्छा है और न ही साधन. अगर वे पार्टी संगठन में तमाम स्तरों पर घात लगाए बैठे अपने समर्थकों को (जिन्हें 'मन्नारगुडी माफिया' कहकर बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता रहा है) लामबंद करके दखल देने की कोशिश करती भी हैं, तब भी इससे उन्हें ही नुक्सान होगा क्योंकि ऐसे में एआइएडीएमके अपने वोट और चुनाव दोनों ही गंवा सकती है.

जो बात एआइएडीएमके पर लागू होती है, वह डीएमके के लिए भी सही है. उसे पुराने सहयोगी दलों—कांग्रेस, विदुतलाई चिरुतैगल काच्चि (वीसीके), मारुमलार्चि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके), सीपीआइ, सीपीआइ(एम) और कई छोटी-छोटी पार्टियां—पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे अपने वोट गठबंधन के उम्मीदवारों के हक में डलवा पाएं. बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को छोड़कर, अलग-अलग पार्टियों के तौर पर उनकी वोट हिस्सेदारी, खासकर सीटों की उनकी मांगों के मुकाबले, नाम मात्र की ही है. डीएमके के कुछ नेताओं को लगता है कि अगर ये साथी दल सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार की वजह से छोड़कर चले जाएं तब भी उनके वोट गठबंधन को ही मिलेंगे. आशंका तो ये भी है कि सहयोगी दल कहीं वे सीटें न हार जाएं जहां उनके पास जीतने लायक उम्मीदवार या खुद अपना पर्याप्त समर्थन आधार नहीं है. अपनी इस बात के समर्थन में डीएमके नेता 2016 और 2019 के चुनावों का हवाला देते हैं.

कांग्रेस के साथ टकराव की ठीक यही वजह है. वह चिंतित इस बात से है कि इस बार उसे 2016 में दी गई 40 से भी कम सीटें दी जा रही हैं (तब पार्टी ने 6.4 फीसद वोट हिस्सेदारी के साथ महज आठ सीटें जीती थीं). सीट बंटवारे को लेकर बातचीत में इसलिए भी खटास पैदा हो गई है कि डीएमके ने पड़ोसी राज्य पुदुच्चेरि में सीटों पर दावा कर दिया है, जहां कांग्रेस सत्ता में है. डीएमके को लगता है कि उसे गर्मियों में होने जा रहे चुनाव में वहां भी गठबंधन की अगुआई करनी चाहिए.

एक प्रतिशत का गणित

कई 'एक प्रतिशत वाले दल' (जिनके पास एक प्रतिशत से अधिक वोट शेयर नहीं है) हैं जो अलग-अलग जाति समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं. भले ही द्रविड़ विचारधारा जातिविहीन समाज पर जोर देती है, फिर भी ये दल पनपे. मूर्ति कहते हैं, ''जाति निश्चित रूप से एक कारक है और कई छोटे-छोटे हिस्सों में तो निर्णायक भी है. लेकिन उत्तर में केवल पीएमके ही ऐसा दल है जिसने 1991 में स्थापना के बाद से बार-बार साबित किया है कि उसके पास पांच प्रतिशत से अधिक वोट शेयर है.''

पश्चिमी क्षेत्र पर वेल्लालर गाउंडर का दबदबा है तो राज्य के दक्षिण में थेवरों, अर्थात मुकुलुथोरस का राजनीतिक वर्चस्व है. दोनों एआइएडीएमके के गढ़ हैं, लेकिन कुछ मौकों पर, 1996 के चुनाव में और बाद में भी, दोनों क्षेत्रों ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण एआइएडीएमके को वोट नहीं दिया. ऐसा ही 2019 के आम चुनाव में भी हुआ. 2016 में केवल पश्चिमी क्षेत्र एआइएडीएमके के साथ रहा, जबकि द्रमुक और उसके सहयोगियों ने राज्य के उत्तर और दक्षिण में अपना झंडा गाड़ा.

राज्य का दक्षिणी हिस्सा नादरों का है. यह समुदाय इस इलाके में हावी है और वे कांग्रेस और भाजपा के बीच बंटे हैं. यह निर्वाचन क्षेत्रों और उम्मीदवारों की जाति पर निर्भर करता है, खासकर द्रमुक और अन्नाद्रमुक के लिए. ऐसी मिसालें भी हैं जहां सबसे प्रभावशाली उम्मीदवार का प्रभुत्व खत्म करने के लिए जातियों ने हाथ भी मिलाया है. ऐसे में कई बार उम्मीदवारों को पार्टी की पहचान का कवच काम आता है.

पिछले 50 वर्षों में एक गैर-द्रविड़ मोर्चा शायद ही कभी सम्मानजनक वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रहा हो (गैर-द्रविड़ों में कांग्रेस का वोट शेयर 1989 में सर्वाधिक 19.8 प्रतिशत रहा था). यह भी एक वजह है कि अभिनेता से राजनेता बने कमल हासन की मक्कल नीति मइअम (एमएनएम) जैसी पार्टी बड़ा सेंध लगाने में असमर्थ होगी. और सक्रिय राजनीति में उतरने से रजनीकांत की हिचकिचाहट (पिछले साल सभी की आशाओं को बढ़ाने के बावजूद) से लगता है कि वे भविष्य में भी राजनीतिक दल शुरू करने से कतरा सकते हैं. 2021 के परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर मद्रास विश्वविद्यालय के राजनीति और लोक प्रशासन विभाग के प्रमुख प्रो रामू मणिवन्नन कहते हैं, ''द्रमुक के लिए संभावनाएं 50 प्रतिशत से अधिक हैं. देखना होगा कि अन्नाद्रमुक और भाजपा-पीएमके-डीएमडीके का गठबंधन उसे कितनी टक्कर दे पाता है.'' बेशक मैदान में सितारों का जलवा नहीं रहेगा लेकिन चुनाव में उत्तेजना की खुराक रत्तीभर भी कम नहीं रहने वाली. ■

गोरखपुर में कलेसर जीरो प्वाइंट पर बने फ्लाइओवर का नजारा

खास रपट **गोरखपुर**

योगी के शहर में विकास की गंगा

पूर्वांचल के प्रमुख शहर गोरखपुर में जिस स्तर पर विकास के काम हो रहे हैं, उनसे बड़े हिस्से के लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा. परोक्ष लाभ तो पूरे प्रदेश को होगा

आशीष मिश्र

गोरखपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर लखनऊ-गोरखपुर हाइवे पर सहजनवां तहसील पहुंचते ही फोरलेन की रंगत बदल जाती है. डिवाइडर पर लगीं अत्याधुनिक फसाड स्ट्रीट लाइटें सड़क को दूधिया रोशनी से नहला देती हैं. फोरलेन पर करीब पांच किलोमीटर आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर ट्रांसपोर्ट नगर में परिवहन विभाग का आधुनिक कार्यालय बनकर तैयार है. यहीं पास में चार करोड़ से अधिक की लागत से सिम्युलेटर कक्ष, सेंटर हेड कक्ष, सर्विलांस कक्ष, आइटी लैब से सजा पूर्वांचल का अत्याधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र जनता को सेवाएं देने के लिए तैयार हो रहा है. यहां से करीब छह किलोमीटर चलने पर कलेसर जीरो प्वाइंट गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश की चमचमाती फोरलेन सड़क से जुड़ाव का गवाह बना है. यहां ''ट्रंपेट फ्लाइओवर'' के जरिये जंगलकौड़िया से होते हुए नेपाल को जोड़ने वाला नया फोरलेन मिलता है तो दूसरी तरफ कुशीनगर जाने वाला फोरलेन हाइवे भी निकलता है. कलेसर प्वाइंट गोरखपुर में बन रही रिंग रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां लखनऊ के अलावा पूर्वांचल तक सड़क से पहुंचने की राह आसान हो जाएगी.

कलेसर जीरो प्वाइंट को पार करके राप्ती नदी के बंधे से सटे फोरलेन में तब्दील हो चुके गोरखपुर-पैडलेगंज रोड पर आगे बढ़ते ही दाहिनी ओर उपेक्षित रहे गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथारिटी (गीडा) का कायाकल्प दिखता है. दाहिनी ओर जाने वाली नई शान बिखेरती सड़कें उद्यमियों की अगवानी करती प्रतीत होती हैं. यहां नए कार्यालय में स्थानांतरित होने के बाद गीडा गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन का इंतजाम करने में जुटा है. उद्योगों के लिए नई जमीनों का विकास और गारमेंट पार्क जैसी योजनाएं गोरखपुर में औद्योगिक माहौल के लिए उत्प्रेरक के रूप में तैयार की जा रही हैं. करीब पांच किलोमीटर आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर जैतपुर गांव जाने वाली सड़क अचानक महत्वपूर्ण हो गई. यहीं से करीब 5,900 करोड़

राजेश राय

रुपए की लागत वाले 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है. यह एक्सप्रेसवे संतकबीरनगर, आंबेडकर नगर होते हुए आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से मिलेगा. यहां से गोरखपुर बाइपास पर आगे बढ़ते ही नौसढ़ इलाके में बाईं ओर राप्ती नदी के बंधे का सुंदरीकरण ध्यान खींचता है. इससे गुजरते हुए राप्ती नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां एक तरफ रामघाट और दूसरी तरफ राजघाट के रूप में चल रहा सुंदरीकरण का कार्य गोरखपुर को नई पहचान दिलाने के लिए बेताब है. इस तरह सहजनवां से गोरखपुर आने वाली सड़क गोरक्षनगरी में चल रहे विकास कार्यों की एक झलक पेश करती है.

91
किलोमीटर
लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है

30,000
करोड़ रुपए
से अधिक लागत की परियोजनाएं गोरखपुर में आकार ले चुकी हैं

विश्वप्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मार्च, 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद गोरखपुर में बड़े पैमाने पर विकास योजनाओं का श्रीगणेश किया था. 30,000 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली ये योजनाएं अब आकार ले चुकी हैं (देखें ग्राफिक्स), जिन्होंने गोरखपुर को नई पहचान दी है. गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश सिंह कहते हैं, ''गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास की धुरी बनकर उभर रहा है. गोरखपुर में शुरू हुई विकास योजनाओं से पूर्वांचल के करीब डेढ़ दर्जन जिले सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे.''

एक वक्त था जब गोरखपुर में पर्यटन का दायरा गोरखनाथ मंदिर तक ही सिमट कर रह जाता था लेकिन तारामंडल इलाका गोरखपुर के पर्यटन हब के रूप में उभर रहा है. रामगढ़ताल को मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह संवारा गया है. गोरखपुर की भव्यता दिखाने के लिए यहां लाइट ऐंड साउंड शो की शुरुआत हो चुकी है. रामगढ़ताल के पानी का इस्तेमाल वाटर स्पोर्ट्स में करने के लिए 40 करोड़ की लागत से वाटर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण किया गया है. गोरक्षधरा पर कई आध्यात्मिक धरोहर उपेक्षा का दंश झेल रहे थे. योगी ने इन सभी धार्मिक केंद्रों के जीर्णोद्धार की बड़ी योजना शुरू की. क्राइस्टचर्च, इमामबाड़ा, जटाशंकर गुरुद्वारा और रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय को नए सिरे से संवारा गया है. गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ महामंत्री और प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता समीर सिंह बताते हैं, ''गोरखपुर में मोहद्दीपुर-जंगल कौड़िया फोरलेन बाइपास निर्माण के लिए गोरखनाथ मंदिर की दुकानें तुड़वाकर मुख्यमंत्री योगी ने विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है.'' पर्यटन विकास के लिए गोरखपुर को हवाई मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और प्रयागराज से जोड़ा गया है. गोरखपुर एयरपोर्ट को बेंगलूरू, वाराणसी, लखनऊ समेत देश के अन्य शहरों से जोड़ने का प्रयास चल रहा है. इसी वजह से हवाई मार्ग से गोरखपुर आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. वर्ष 2014-15 में गोरखपुर एयरपोर्ट से 26,000 यात्रियों ने सफर किया था तो 2019-20 में यह आंकड़ा 5.50 लाख पहुंच गया. 2020-21 में गोरखपुर एयरपोर्ट से सात लाख लोग सफर कर चुके हैं. एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल तीन का निर्माण कराया जा रहा है. गोरखपुर में सुमेर सागर, खरैया पोखरा, असुरनपुरा समेत 40 से अधिक तालाबों से अवैध कब्जे हटवाकर गोरखपुर सदर तहसील के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरवसिंह सोगरवाल ने 70 एकड़ जमीन मुक्त कराई है. सोगरवाल बताते हैं, ''तालाबों पर अवैध कब्जा हटाने से शहर में जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी और विकास योजनाओं के लिए एक लैंड बैंक भी तैयार हुआ है.''

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) भीटीरावत इलाके के 50 एकड़ में गारमेंट पार्क स्थापित करने जा रहा है. योगी सरकार ने भी रेडीमेड गारमेंट को टेराकोटा के बाद गोरखपुर के 'एक जिला, एक उत्पाद' (ओडीओपी) में दूसरे उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया है. इससे गोरखपुर के उद्यमी काफी उत्साहित हैं. गीडा से ही पिपरौली क्षेत्र जुड़ा है, जहां रेडीमेड गारमेंट का अच्छा काम होता है. ओडीओपी के तहत सरकार ने गारमेंट उद्योग लगाने पर 20 लाख रुपए तक के अनुदान की भी घोषणा की है. गारमेंट पार्क में 50 से अधिक उद्यमियों ने निवेश करने की इच्छा जताई है. चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद अजितसरिया बताते हैं, ''जितने निवेशकों ने अब तक गारमेंट पार्क में निवेश की इच्छा जताई उससे कम से कम 2,500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा.'' चैंबर आफ इंडस्ट्रीज को गारमेंट पार्क में 500 औद्योगिक इकाई स्थापित होने का अनुमान है. ऐसा होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 25,000 लोगो को रोजगार मिलेगा.

गोरखपुर में विकास से जुड़ी 100 से अधिक छोटी-बड़ी योजनाएं संचालित हो रही हैं. यहीं पर कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाने

''गोरखपुर में मोहद्दीपुर-जंगल कौड़िया फोरलेन बाइपास निर्माण के लिए गोरखनाथ मंदिर की दुकानें तुड़वाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है''

समीर सिंह
प्रवक्ता, प्रदेश भाजपा

चार चांद लगा रहीं योजनाएं

खाद कारखाना

दुनिया में सबसे ऊंचे149.5 मीटर के प्रिलिंग टावर वाले खाद कारखाने का 90 फीसदी से अधिक काम पूरा हो गया है. करीब 7,000 करोड़ रु. की लागत से बन रहा यह कारखाना इसी वर्ष जून में काम करना शुरू कर देगा. इससे रोजाना 3,850 मीट्रिक टन खाद का उत्पादन होगा.

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे

करीब 91 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर बाइपास एनएच-27 पर स्थित ग्राम जैतपुर के पास शुरू होकर आजमगढ़ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा. 5,867 करोड़ रु. की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा हो जाने का लक्ष्य रखा गया है.

एम्स

गोरखपुर के कूड़ाघाट क्षेत्र में 45 हेक्टेयर जमीन पर 1,800 करोड़ रुपए की लागत से आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज (एम्स) का निर्माण कराया गया है. ओपीडी शुरू होने के बाद इस वर्ष जून तक एम्स में आंतरिक रोगी विभाग शुरू हो जाएगा. 750 बेड वाले सुपरस्पेशिएलिटी विंग की भी शुरुआत होगी.

तरुकुलानी रेग्युलेटर

खोराबार क्षेत्र के 47 गांवों की 42,000 की आबादी और 2,838 हेक्टेयर भूमि को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए तरकुलानी रेग्युलेटर का निर्माण कराया जा रहा है. इस वर्ष जुलाई से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस पर 85 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

प्राणि उद्यान

गोरखपुर में बन रहे शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान पेंग्विन की मौजूदगी वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर होगा. प्रदेश के इस तीसरे प्राणि उद्यान का निर्माण 221 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है. इसमें 58 प्रजातियों के 387 वन्यजीव रखे जाएंगे. यह अप्रैल तक शुरू होगा.

बाल रोग चिकित्सा संस्थान

गोरखपुर मेडिकल कालेज परिसर में 274 करोड़ की लागत से बना 500 बिस्तरों वाला बाल रोग चिकित्सा संस्थान अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगा. मेडिकल कालेज के तहत 150 करोड़ रु. की लागत से बने सुपर स्पेशिएलिटी सेंटर में कई विभागों की ओपीडी सेवा शुरू होगी.

महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय

जंगल कौड़िया क्षेत्र के चकिया रसूलपुर गांव में 11 करोड़ रु. की लागत से तीन एकड़ में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय और 27 करोड़ रु. की लागत से महंत अवैधनाथ ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण हो रहा है.

फोरेंसिक लैब

गोरखपुर जिला अस्पताल के पास 66 करोड़ रु. की लागत से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया है. इसी वर्ष शुरू होने वाली फोरेंसिक लैब में बाल, नाखून, विसरा आदि की जांच होगी. नमूनों को लखनऊ, आगरा या पुणे भेजने की जरूरत नहीं होगी.

रिंग रोड

गोरखपुर-लखनऊ मार्ग पर कलेसर से जगदीशपुर तक 37 किमी फोरलेन बन चुका है. कलेसर से जंगल कौड़िया तक 17 किमी लंबे बाइपास का निर्माण हुआ है. जंगल कौड़िया से जगदीशपुर तक 25 किमी फोरलेन बनने के साथ गोरखपुर का करीब 81 किलोमीटर लंबा रिंग रोड पूरा हो जाएगा. इसमें 1,500 करोड़ रु. से अधिक खर्च होंगे.

रामगढ़ताल

रामगढ़ताल को यूपी का पहला वेटलैंड घोषित किया गया है. वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, झील मनोरंजन की सुविधा विकसित करने के साथ रामगढ़ताल में गिरने वाले नालों को टैप किया जा रहा है. इन पर 150 करोड़ रु. से अधिक खर्च होंगे. ताल के किनारे लंदन आइ जैसा झूला लगाने का भी प्रस्ताव है.

पिपराइच चीनी मिल

वर्ष 2010 से बंद पड़ी पिपराइच चीनी मिल को नवंबर 2019 में दोबारा शुरू किया गया. 417 करोड़ रु. की लागत से 50,000 क्विंटल क्षमता की चीनी मिल शुरू हुई. बिजली उत्पादन के साथ ही प्रदेश में पहली बार सल्फरलेस चीनी का भी उत्पादन पिपराइच मिल में शुरू हुआ है.

सीवर लाइन

शहर के नालों का पानी रामगढ़ताल, राप्ती और रोहिणी नदी में गिरने से बचाने के लिए अमृत मिशन के तहत 650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 247 किलोमीटर लंबी सीवर लाइन बिछाई जा रही है. नालों के पानी को साफ करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर में एसटीपी का निर्माण होना है.

प्रेक्षागृह

रामगढ़ताल के सामने 50 करोड़ रुपए की लागत से तीन एकड़ जमीन पर मुक्ताकाशी मंच यानी ओपेन थियेटर और प्रेक्षागृह का निर्माण कराया गया है. पूर्वांचल के सबसे बड़े प्रेक्षागृह में 1,076 दर्शकों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल और 250 दर्शकों की क्षमता वाला एक अन्य हॉल भी बनाया गया है.

राजघाट और रामघाट

राप्ती नदी के किनारे राजघाट स्थित अंत्येष्टि स्थल को राजस्थानी शैली 'गजीबो' और 'पालकी' के जरिए नया रूप दिया जा रहा है. 150 मीटर लंबे इस घाट पर शिव मंदिर आकर्षण का केंद्र होगा. राजघाट के दूसरी तरह रामघाट का निर्माण हो रहा है. इस योजना में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे.

पंख लगने को तैयार प्रोजेक्ट

लाइट रेल: योगी कैबिनेट ने गोरखपुर में यातायात सुगम बनाने के लिए लाइट रेल ट्रांजिट (एलआरटी) परियोजना की डीपीआर को अनुमोदन प्रदान कर दिया है. परियोजना की कुल लागत 4,672 करोड़ रुपए है.

आयुष विश्वविद्यालय: चौरीचौरा तहसील के मलमलिया गांव में 24 हेक्टेयर जमीन पर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जाएगा. यूपी के सभी आयुष मेडिकल कालेजों को इससे संबंद्ध किया जाएगा.

सैनिक स्कूल: फर्टिलाइजर क्षेत्र में 50 एकड़ जमीन पर सैनिक स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है. इस में एकेडमिक ब्लाक, मल्टीपरपज हाल, डाइनिंग हाल, ब्वायज और गर्ल्स हॉस्टल समेत आवास भी बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने इसकी डीपीआर बनाने को कहा है.

वेटरिनरी मेडिकल कालेज: चरगवां में प्रदेश का दूसरा वेटरिनरी कालेज बनेगा. इमारत के लिए कृषि विभाग की 30 एकड़ जमीन पशुपालन विभाग के नाम ट्रांसफर की जा चुकी है. 250 करोड़ रु. से बनने वाले इस कालेज में 80 सीटों पर प्रवेश मिलेगा.

जीआइएस बिजलीघर: खोराबार क्षेत्र में 220 केवी जीआइएस ट्रांसमिशन बिजलीघर बनेगा. इससे 12 लाख की आबादी को निर्बाध बिजली आपूर्ति होगी.

वाले विपुल सिंह बताते हैं, ''बड़े पैमाने पर गोरखपुर में हो रहे निर्माण कार्यों में यहां मजदूर से लेकर तकनीकी दक्ष युवक समेत कुल 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है.'' प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क लगाने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया है. गोरखपुर के बड़हलगंज निवासी हरवंश तिवारी चेन्नै के तीरपुर स्थित देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क में एक फैक्ट्री के मालिक हैं. वे बताते हैं, ''तीरपुर में काम कर रहे बहुत सारे उद्यमी उत्तर प्रदेश के ही हैं. गोरखपुर में मेगा टेक्साटाइल क्लस्टर बनने पर ये उद्यमी अपने प्रदेश लौटना चाहेंगे. अगर यहां 1,000 टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगती है तो कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा.''

गोरखपुर में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए सुधार ने दिमागी बुखार पर नकेल कस दी है. गोरखपुर और आसपास के इलाकों में वर्ष 2016 में दिमागी बुखार यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से कुल 136 और जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) से 9 मौते हुई थीं. अगले साल एईएस और जेई को मिलाकर 120 मौते हुई लेकिन वर्ष 2020 में जेई और एईएस से मिलाकर 22 मौते हुई हैं. गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में छह बेड की आइडिपेंसी यूनिट अब बढ़कर 60 बेड की हो गई है. आइसीयू में पहले जहां 60 वेंटीलेटर थे, अब बढ़कर 120 हो गए हैं. बाल रोग विभाग में पहले 14 वार्मर की जगह अब 40 से अधिक हैं. गोरखपुर में 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) हैं. चौरीचौरा, गगहा और पिपरौली में मिनी पीड्रियाटिक इंटेसिंव केयर यूनिट खोला गया. पीएचसी पर दो तथा सीएचसी पर छह बेड इंसेफ्लाइटिस मरीजों के लिए आरक्षित हैं. गोरखपुर मेडिकल कालेज के प्राचार्य डॉ. गणेश कुमार बताते हैं, ''पीएचसी और सीएचसी पर इलाज मिलने से इंसेफ्लाइटिस मरीजों की मौतों पर रोक लगी है.''

गोरखपुर में चल रहे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए ''गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम'' नाम से वेबसाइट और मोबाइल ऐप का सहारा लिया जा रहा है. जिलाधिकारी के. विजयेंद्र पांडियन ने गोरखपुर में चल रहे सभी प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट रोज उन्हीं ऐप और वेबसाइट में दर्ज करने का आदेश दिया है. प्रोजेक्ट के निर्माणकार्य की गति के हिसाब से इसे तीन श्रेणी लाल, पीला और हरा में बांटा गया है. धीमे विकास कार्यों को अतिरिक्त जोर लगाकर गति दी जा रही है. आने वाले कुछ महीनों में गोरखपुर का कायाकल्प होना तय है.■

कई रोड़े हैं इस राह में

सोने का कारोबार बढ़ाने और उसके लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बनना जरूरी. लेकिन इसकी स्थापना क्या इतनी आसान है? एक पड़ताल

शुभम शंखधर

दिल्ली के रवि प्रकाश निवेश के लिए सोने को सबसे बढ़िया विकल्प मानते हैं. शेयर बाजार को नहीं समझने वाले रवि बैंक और छोटी बचत योजनाओं में घटते रिटर्न से भी परेशान हैं. वित्त मंत्री का ताजा बजट भाषण सुनकर सोने में निवेश और कारोबार करने वाले सभी लोग झूम उठे. एक तरफ आयात शुल्क में कटौती की गई और दूसरी तरफ यह ऐलान हो गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज का नियामक होगा. यही वह रोड़ा था गोल्ड एक्सचेंज स्थापित होने की दो साल पुरानी घोषणा अटकी हुई थी. दरअसल देश में स्पॉट एक्सचेंज बनने के बाद सोने की खरीद, शुद्धता और कीमत से जुड़े कई बदलाव अपेक्षित हैं, जो छोटे निवेशकों के लिए बहुत मायने रखते हैं. नियामक तय होने के बाद क्या रवि जैसे निवेशकों की उम्मीदें परवान चढ़ेंगी? परतें उधेड़ने पर पता चलता है कि मंजिल अभी दूर है.

कहां अटकी थी गाड़ी?

साल 2018-19 के बजट में भी सरकार ने एक व्यापक गोल्ड पॉलिसी बनाने और देश में गोल्ड एक्सचेंज शुरू करने की मंशा जाहिर की थी. लेकिन संभावित दोनों ही नियामकों भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी का कहना था कि हाजिर बाजार का कामकाज उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं है. सेबी के तहत आने वाले सभी एक्सचेंज वायदा कारोबार से जुड़े हैं. 2018 में सेबी ने यह भी सुझाया था कि हाजिर बाजार के लिए एक अलग नियामक बनना चाहिए. नियामक तय न होना ही गोल्ड एक्सचेंज की राह का बड़ा रोड़ा था. अब स्थिति स्पष्ट होने से चीजें तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि 17 फरवरी को होने वाली सेबी की बोर्ड बैठक में गोल्ड एक्सचेंज के रोडमैप पर चर्चा हो सकती है.

अब निबटाने हैं ये मसले?

अब तय हो गया है कि सेबी के निर्देशों के तहत ही एक्सचेंज का कारोबार होगा. यह गोल्ड एक्सचेंज खुलने की दिशा में अहम पड़ाव है. पर सवाल कई और हैं जिनके जवाब ढूंढ़ने होंगे. इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर के चेयरपर्सन प्रोफेसर अरविंद सहाय कहते हैं, ''गांधीनगर गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज स्थापित करने का काम पहले से ही चल रहा है. बजट में ऐलान हुआ कि डोमेस्टिक स्पॉट एक्सचेंज देश का दूसरा एक्चेंज होगा. ये दोनों पूरी तरह अलग हैं.'' अब इन दोनों के कामकाज में समन्वय बनाना एक चुनौती होगा. दोनों ही एक्सचेंज पर कारोबार बढ़ाना होगा क्योंकि एक सीमा तक के कारोबार के बिना एक्सचेंज जीवित रहना मुश्किल होगा. ऐसा भी न हो कि वे एक-दूसरे से खरीदें और इस तरह कारोबार बढ़े. दोनों एक्सचेंज के वॉल्यूम बढ़े इसके लिए एक समन्वय बनाना होगा.

सोने-चांदी के कारोबार से जुड़ी संस्था एमएमटीसी पीएएमपी के सलाहकार और इंडिया बुल्स ऐंड ज्वेलरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपध्यक्ष राजेश खोसला कुछ ऐसे ही और सवालों की ओर ध्यान खींचते हुए कहते हैं, ''देश में करीब 1,000 टन सोने की सालाना खपत है. इसमें से 700-750 टन सोना हम आयात करते हैं. इसी खपत और आयात का एक हिस्सा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्पॉट एक्सचेंज पर ट्रेड होने लगेगा. अब पेंच यह है कि खरीदेगा कौन? अभी तक कुछ नामांकित बैंक, एजेंसियां, स्टार ट्रेडिंग हाउस ही सोने का आयात करते हैं. बड़े ज्वेलर्स और रिफाइनर्स भी इन्हीं से सोना लेकर घरेलू बाजार में पहुंचाते हैं. क्या आगे भी ये ही आयात करते रहेंगे या ब्रोकिंग हाउस/रिटेल निवेशकों को भी अंतरराष्ट्रीय स्पॉट एक्सचेंज पर सौदे करने की इजाजत होगी? जिन बैंकों या एजेंसियों को आयात का अधिकार होगा उन्हें ट्रेडिंग करनी होगी. वॉल्यूम बढ़ाना है तो बेशक ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी. एक और पेंच है: अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर गिफ्ट सिटी में ऑफिस बनाकर यहां ट्रेड करता है और सेटलमेंट के लिए सोना लाता है तो उसके लिए क्या नियम होंगे? उसे बिना कस्टम ड्यूटी या ड्यूटी चुकाकर सोना लाने की इजाजत होगी? अगर हां तो क्या देश में आयात के दो मार्ग हो जाएंगे?

यहीं दूसरा सवाल खड़ा होता है जो करों से जुड़ा है. मान लीजिए किसी ब्रोकर ने अंतरराष्ट्रीय स्पॉट एक्सचेंज पर कोई सौदा किया और उसकी डिलीवरी ली तो जीएसटी, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सरीखे कौन-से कर लगेंगे. अगर किसी सौदे में भारत से सोना बाहर भेजना है तो ड्यूटी रिफंड का क्या ढांचा होगा. इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर ने अपनी रिपोर्ट वायबिलिटी ऑफ ए गोल्ड एक्सचेंज इन इंडिया में सुझाया था कि चीन और सिंगापुर की तरह भारत में भी निवेश के लिए खरीदा

फाइल फोटो

दीवाली तक फिर चमकेगा सोना

अगस्त 2020 में 56,200 रुपए प्रति दस ग्राम का उच्चतम स्तर छूने के बाद वायदा बाजार में सोने की कीमतें (09 फरवरी 2020 को) 48,000 रुपए प्रति दस ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही हैं. सोने की कीमतों में 8,000 रुपए से ज्यादा की इस गिरावट के पीछे विशेषज्ञ जिन वजहों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उनमें कोरोना की वैक्सीन का आना, सोने के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती का ऐलान और अमेरिकी बॉण्ड बाजार में आई तेजी है. विशेषज्ञों के मुताबिक, लोगों के मन में अब कोरोना का भय कम हो रहा है. टीकाकरण का अभियान भी पूरी दुनिया में शुरु हो चुका है. ऐसे में वे निवेशक जिन्होंने सुरक्षित निवेश विकल्प के तौर पर सोने को चुना था, मुनाफावसूली कर रहे हैं. इसके अलावा बजट में सोने के आयात पर लगने वाले 12.5 फीसदी शुल्क को घटाकर 7.5 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि इस पर 2.5 फीसदी का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐंड डेवलपमेंट सेस लगा दिया गया है. एक जानकार की राय में, दीवाली तक सोने के भाव एक बार फिर 55,000 रुपए प्रति दस ग्राम का स्तर दिखा सकते हैं. इसकी वजह शादियों के सीजन में सोने की मांग का बढ़ना है. साथ ही शेयर बाजार में मौजूदा स्तर पर जोखिम अधिक है और सोने ने अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में अच्छे रिटर्न दिए हैं. ऐसे में शेयर बाजार में मुनाफावसूली सोने की कीमतों में वापसी का कारण बन सकती है.

गया सोना वैट और जीएसटी जैसे अप्रत्यक्ष करों से मुक्त होना चाहिए.

तीसरा मुद्दा समाशोधन और निबटान (सेटलमेंट और क्लीयरिंग) से जुड़ा है. स्पॉट एक्सचेंज पर अगर कोई भागीदार बिकवाली करता है तो या तो उसे मुनाफा होगा या नुक्सान. मुनाफे हुआ तो उसके खाते में पैसा आएगा और नुक्सान हुआ तो खाते से जाएगा. इसके लिए एक ऐसी समाशोधन व्यवस्था करनी होगी जिसकी साख विश्व स्तर पर हो. इन लेन-देनों पर चार्ज भी तर्कसंगत रखना होगा.

केडिया कमोडिटीज के निदेशक अजय केडिया एक्सचेंज के लिए जरूरी लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे की ओर ध्यान खींचते हुए कहते है, ''कुछ ऐसी बड़ी और अनुभवी एजेंसियों की जरूरत होगी जो सोने के रखरखाव और पूरे देश में इसकी आपूर्ति तय समय में सुनिश्चित कर सकें.'' घरेलू स्पॉट एक्सचेंज में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह बेहद जरूरी है. केडिया हालांकि एक्सचेंज को सोने के बाजार के लिए गेमचेंजर मान रहे हैं. उनके शब्दों में, ''भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, हम करीब 89 फीसदी सोना आयात करते हैं. इतने बड़े उपभोक्ता होने के बाद भी सोने की कीमत तय करने में हमारा कोई दखल नहीं. एक्सचेंज बनने के बाद हम कारोबार के केंद्र में आएंगे और कीमतें तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे. घरेलू बाजार में भी कीमतें और शुद्धता तय करने में एक्सचेंज की अहम भूमिका होगी. अभी देश के अलग अलग हिस्सों में सोने के दाम भिन्न होते हैं. स्पॉट एक्सचेंज बनने के बाद देश में सोने का एक भाव होगा. साथ ही सोने की शुद्धता के बेहतर पैमाने तय हो सकेंगे.''

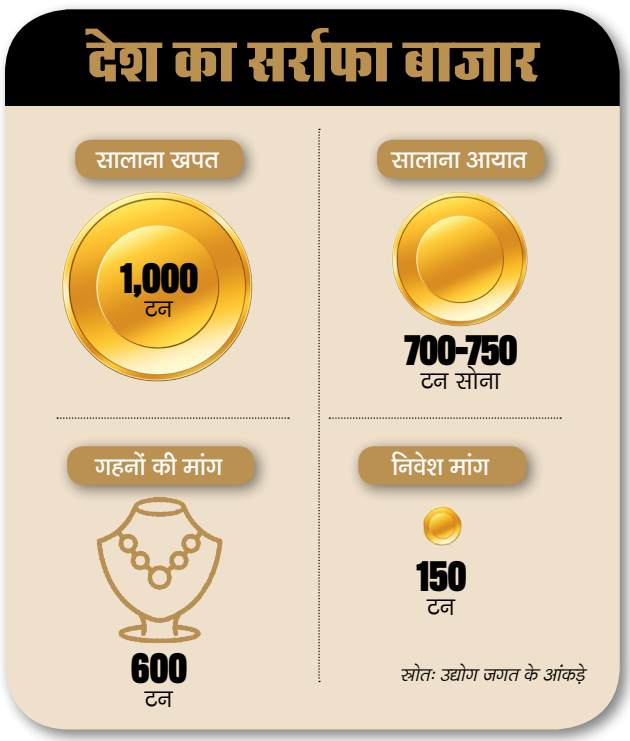

बदलेगी सर्राफे की सूरत

द बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेल सिंघल कहते हैं, ''इसमें कोई संदेह नहीं कि गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत से व्यापार को बल मिलेगा और लेन-देन में पारदर्शिता आएगी.'' अपनी बात विस्तार से समझाते हुए वे कहते हैं कि अभी शेयर बाजार में किसी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको एक्सचेंज पर ही जाना पड़ता है. उससे इतर शेयर खरीदने का कोई तंत्र नहीं है. इसी तरह स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज शुरु होने के बाद सोने की खरीद-फरोख्त का एक पारदर्शी तंत्र होगा. सर्राफा कारोबारी, रिफाइनर या खुदरा निवेशक कोई भी एक्सचेंज से सोना खरीद सकेगा. अभी किसने कितना आयात किया या घरेलू बाजार से खरीदारी की, इसका कहीं कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं है. एक्सचेंज बनने से घरेलू और वैश्विक सभी लेन-देनों में पारदर्शिता आएगी.

सरकार के प्रयासों को मिलेगा बल

आयात बिल पर काबू पाने के लिए सरकार ने बीते वर्षों में कई ऐसे प्रयास किए जिससे निवेशकों का रुझान फिजिकल सोने की ओर कम हो. मसलन, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड बॉण्ड, गोल्ड बचत खाता आदि. केडिया मानते हैं, ''एक्सचेंज बनने से गोल्ड मॉनेटाइजेशन जैसी स्कीमें अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं.'' पहले मॉनेटाइजेशन स्कीम में लोग घरों का सोना देने से इसलिए कतराते थे क्योंकि उसके उसी रूप में वापस मिलने की उम्मीद नहीं होती थी. या तो पैसे मिलते थे या फिर सोना किसी अन्य रूप में. एक्सचेंज के लिए अगर देश में वॉल्ट और वेयरहाउस बनते हैं तो सरकार सोने को उसी रूप में वापस देने पर विचार करके घर और मंदिरों में रखे सोने को बाहर ला सकती है.■

गर्दिश में सितारे

उन्हें अपना कारोबार बेचने को मजबूर होना पड़ा, रिलायंस के साथ उनका सौदा कानूनी दांवपेंचों में फंस गया, उसके बाद पूंजी बाजार में उनके कारोबार पर साल भर की पाबंदी लग गई. खुदरा बाजार के नायक रहे किशोर बियानी को भी क्या यही दिन देखने थे!

एम.जी. अरुण

रवीत गोस्वामी

किशोर बियानी को नए-नए कामों का उस्ताद, इंसानी मनोविज्ञान का पारखी और चतुर उद्यमी माना जाता है. फ्यूचर ग्रुप के इस 59 वर्षीय सीईओ ने कारोबारी फैसलों के लिए अक्सर पॉवरपॉइंट प्रस्तुतियों को ताक पर रखकर अपनी स्वाभाविक सूझबूझ पर भरोसा किया. भारत में संगठित खुदरा बाजार के अगुआ माने जाने वाले बियानी ने लगातार भौतिक खरीदारी के प्रति भारतीयों के झुकाव पर दांव लगाया. लेकिन फिर ऑनलाइन रिटेल के हमले ने उनके कारोबारी साम्राज्य की चूलें हिला दीं. किराने के सामान की उनकी रिटेल चेन बिग बाजार की तरफ से गणतंत्र दिवस पर आयोजित बिक्री में हमेशा कई हजार लोग उमड़ पड़ते थे. इस हद तक कि कुछ मौकों पर, जैसा कि उन्होंने 2007 के अपने संस्मरण *इट हैप्पंड इन इंडिया*

में लिखा है—डर माल खत्म होने का नहीं बल्कि खरीदारों की सुरक्षा का होता था. समय के साथ बिग बाजार भारतीय मध्य वर्ग के लिए सस्ते सामान की खरीदारी की दुकान का पर्याय बन गया. बिग बाजार की लोकप्रियता में उछाल के साथ बियानी की महत्वाकांक्षएं भी परवान चढ़ीं. मगर ई-टेल में अचानक आई तेजी से उनके कारोबार में व्यवधान पैदा हुआ और 2015 में वे अपने समूह को नए सिरे से ढालने को मजबूर हो गए. अभी हाल ही में कोविड महामारी में बियानी का ऑफलाइन बिजनेस मॉडल अचानक भरभराकर ढह गया. उन्हें अपना बेशकीमती कारोबार बेचने के लिए रिलायंस रिटेल के साथ सौदा करना पड़ा. मगर अब ई-टेल की दिग्गज कंपनी अमेजन की तरफ से सिंगापुर की अदालत में इस सौदे को चुनौती दिए जाने के साथ बियानी कानूनी दलदल में धंस गए हैं. अपने करियर की ऊंचाई पर मिल रही वाहवाही से बिल्कुल उलट, अब वे बाजार नियामक सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) की ओर से 2017 के एक मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में शेयर बाजारों से एक साल के प्रतिबंध का सामना कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी है.

बिग बाजार ने बियानी को खुदरा कारोबार का शहंशाह बना दिया, लेकिन उनकी शुरुआत इससे नहीं हुई थी. उन्होंने मुंबई में अपने परिवार के कपड़ा कारोबार से शुरुआत की (उनके दादा ने राजस्थान के निम्बी जोधा से वहां आकर कपड़े की दुकान खोली थी) और 1983 में परिधान के लिए तैयार कपड़ों के कारोबार में कदम रखा. 1987 में उन्होंने मैन्ज वियर ब्रान्ड लॉन्च किया जो बाद में गारमेंट रिटेलर पैंटालूंस बन गया. अपनी विस्तार योजनाओं के लिए धन जुटाने की खातिर 1992 में उन्होंने पैंटालून रिटेल को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया. 2012 में जब कर्जों का अंबार बढ़ने लगा तो उन्होंने पैंटालून रिटेल में अपना बहुसंख्यक हिस्सा आदित्य बिड़ला नुवो को 1,600 करोड़ रुपए में बेच दिया. बिग बाजार, सेंट्रल, ईजोन, ब्रान्ड फैक्ट्री और होमटाउन ब्रान्ड उनके पास बने रहे. कंसल्टेंसी फर्म थर्ड आइसाइट के सीईओ देवांशु दत्ता कहते हैं, ''जो चीज (शुरुआती वर्षों में) उनके काम आई, वह यह थी कि उनका समूह अलग-अलग (कारोबारी) विचारों को आजमाने का इच्छुक था और नाकामी से कतराता नहीं था.'' इसी इनोवेटिव नजरिये से फ्यूचर ग्रुप इस क्षेत्र में कई दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी मौजूदगी दर्ज कर पाया. बढ़ती पूंजी को संभालना, उस पूंजी को उद्यमों में लगाना और यह समझना कि उनमें से कौन-सा कारगर है और कौन-सा नहीं, यह मुश्किल बाजीगरी का काम था, जिसे बियानी ने बखूबी संभाला. मगर नई मुश्किलें उनकी ताक में थीं.

ई-कॉमर्स की चुनौती

ऊंची वृद्धि के एक दशक बाद फ्यूचर ग्रुप के कारोबार 2010 से सुस्त पड़ने लगे. सुविधा और छूट की बदौलत फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजन सरीखे ई-टेलरों की कामयाबी बड़ा खतरा बनकर उभरी. प्रतिद्वंद्वी रिलायंस रिटेल का बढ़ना भी खतरा ही था. साल 2015 आते-आते बियानी के सामने अपनी फर्म को नींद से झकझोरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा. उन्होंने कई नई पहल कीं, जिन्हें उन्होंने समूह का 'पुनर्जन्म' कहा. मसलन, फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेज के तहत व्हाइट-लेबल एफएमसीजी उत्पाद लाए, खरीदारों को कहीं से भी खरीदने और कहीं भी डिलिवरी लेने की छूट दी, वगैरह. (व्हाइट-लेबल रणनीति में एक कंपनी के बनाए उत्पाद विभिन्न ब्रान्ड नामों के तहत दूसरी कंपनियों की ओर से पैकेज किए और बेचे जाते थे.)

अगले कुछ वर्षों के दौरान बियानी अपने स्टोरों की गिनती बढ़ाते रहे और परिधानों और जीवनशैली से लेकर किराने तक विभिन्न फॉर्मेट में उनकी तादाद 1,800 तक ले गए. अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकों से धन लेकर उन्होंने बीते सात साल में छह कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया. उन्होंने जिस कारोबार को आखिरकार रिलायंस रिटेल को बेचा, 2019-20 तक उससे प्राप्त कुल राजस्व 28,272 करोड़ रूपए था. लेकिन उनका कर्ज भी विशाल होता गया. फ्यूचर रिटेल का कर्ज 19,000 करोड़ रुपए का था जिसे रिलायंस ने सौदे के तहत अपने सिर ले लिया. आखिरी धक्का महामारी की शक्ल में आया, जब उनके कारोबारों में ठहराव आ गया और वे अपने कर्ज चुका नहीं पाने की कगार पर पहुंच गए. ई-कॉमर्स शाखा की गैरमौजूदगी ने उनके कारोबार के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए.

ई-टेल प्रतिस्पर्धा और महामारी ने किशोर बियानी के बिजनेस मॉडल को ध्वस्त कर दिया है, ऐसे में वे रिलांयस के साथ अपना सौदा पूरा करने को लेकर बेताब हैं

महामारी के दौरान बियानी ने रिलायंस रिटेल के साथ जो सौदा किया, वह उनकी कारोबारी सेहत के लिए जरूरी था. भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी फर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन 63 वर्षीय मुकेश अंबानी के मन में ई-टेल को लेकर बड़ी महत्वाकांक्षाएं उछाल मारती रही थीं, लेकिन ऑनलाइन रिटेल में गर्व करने के लिए उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स (रिलायंस रिटेल के तीन-चौथाई स्टोर इसी के थे और यह उसे 45,000 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री दे रहा था) के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था. अपने रिटेल कारोबार के लिए उन्हें फ्यूचर ग्रुप में मुकम्मल प्लेटफॉर्म नजर आया. कइयों को लगता है कि 24,713 करोड़ रुपए का सौदा अंबानी को बहुत सस्ते में पड़ा, लेकिन बियानी भी इससे बेहतर की मांग नहीं कर सकते थे. ई-कॉमर्स कंपनियों का मूल्य निर्धारण आसमान छू रहा है और इसने अमेजन और वॉलमार्ट सरीखी दिग्गज वैश्विक कंपनियों को भारतीय बाजार के प्रति आकर्षित किया है, लेकिन फिजिकल स्टोर वाले कारोबारों के बहुत ज्यादा खरीदार नहीं है, खासकर महामारी के दौरान, जिसने अर्थव्यवस्था को लगभग पूरी तरह ठप कर दिया. संक्षेप में बियानी के लिए अंबानी रक्षक से कम नहीं थे. यह सौदा अंबानी के लिए फायदेमंद है और पूरा होने के बाद उनके लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए का कारोबार तैयार कर देगा. यह रिलायंस रिटेल के नजदीकी प्रतिद्वंद्वी एवेन्यू सुपरमार्ट जो डीमार्ट स्टोर चलाता है, से चार गुणा बड़ा होगा.

अमेजन-रिलायंस की लड़ाई

मगर दिग्गज ई-टेल कंपनी अमेजन ने फच्चर फंसा दिया. अमेजन ने 2019 में फ्यूचर रिटेल के प्रोमोटर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपंस की 49 फीसद हिस्सेदारी करीब 2,000 करोड़ रुपए में खरीदी थी. इस सौदे से फ्यूचर रिटेल के उत्पादों को अमेजन के ऑनलाइन बाजार पर लाने में मदद मिलती और उधर अमेजन को 'कॉल' विकल्प मिल गया, जिसकी बदौलत वह समझौते के तीन से दस साल के भीतर कंपनी में फ्यूचर कूपंस की प्रोमोटर कंपनी फ्यूटर रिटेल की आंशिक या पूरी हिस्सेदारी खरीद सकती थी. अंबानी के साथ बियानी के बिक्री सौदे को अमेजन ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआइएसी) में चुनौती दे दी. उसने दलील दी कि अगस्त 2020 में किया गया फ्यूचर-रिलायंस सौदा 'प्रथम-इनकार का अधिकार' समझौता और एक गैर-प्रतिस्पर्धा धारा का उल्लंघन है जिस पर उसने 2019 में फ्यूचर ग्रुप के साथ दस्तखत

शख्सियत
किशोर बियानी

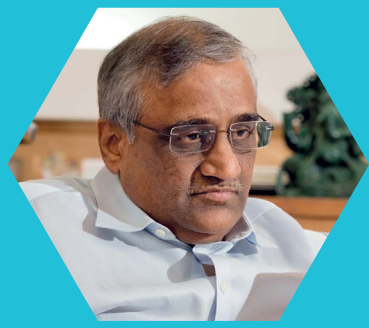

एक रिटेलर का सफर

1987: बियानी ने मैन्ज **वियर ब्रान्ड लॉन्च** करके परिधानों के कारोबार में प्रवेश किया. यही ब्रान्ड बाद में पैंटालूंस बना

1992: पैंटालून रिटेल को उन्होंने शेयर बाजार में सूचीबद्ध करवाया

2001: अन्य कारोबार में पैर पसारने की योजना, **बिग बाजार ग्रोसरी स्टोर्स** स्थापित किए

2012: पैंटालून रिटेल में अपनी बहुसंख्यक हिस्सेदारी आदित्य बिड़ला नुवो को बेच दी, जिसने फर्म में 1,600 करोड़ रु. का निवेश किया

2015: फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेज के तहत व्हाइट-लेबल एफएमसीजी उत्पाद लॉन्च किए, खरीदारों को कहीं भी खरीदारी करने और डिलिवरी लेने की छूट दी

2016: 64 श्रेणियों में **27 प्राइवेट** लेबल लॉन्च करके उपभोक्ता सामानों के क्षेत्र में कदम रखा

2019: अमेजन ने करीब **2,000 करोड़ रु.** में फ्यूचर रिटेल की प्रोमोटर समूह कंपनी फ्यूचर कूपंस में 49 फीसद हिस्सेदारी ली

अगस्त 2020: फ्यूचर रिटेल ने अपनी खुदरा, लॉजिस्टिक्स और वेअरहाउसिंग इकाइयां **24,713 करोड़ रु.** में रिलायंस रिटेल को बेच दीं

अक्तूबर 2020: सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की एकल पीठ ने अमेजन की अपील पर फ्यूचर रिटेल को अपनी संपत्तियां किसी अन्य को बेचने का कोई कदम उठाने से रोक दिया

2021

2 फरवरी: दिल्ली हाइकोर्ट की एकल पीठ ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे को स्थगित रखने का आदेश दिया

2 फरवरी: सेबी ने 2017 के इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में बियानी, उनके भाई अनिल और अन्य पर शेयर बाजार से एक साल के लिए रोक लगाई

8 फरवरी: दिल्ली हाइकोर्ट की दो जजों की पीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई. **अगली सुनवाई 26 फरवरी को होनी है**

किए थे. अक्तूबर, 2020 में एसआइएसी की अदालत की एकल पीठ ने फ्यूचर रिटेल को अपनी संपत्तियां किसी अन्य पक्ष को बेचने का कोई भी कदम उठाने से रोक दिया. इस साल 2 फरवरी को दिल्ली हाइकोर्ट की एकल पीठ ने फ्यूचर-रिलायंस सौदे को स्थगित रखने का आदेश दिया, पर 8 फरवरी को अदालत की दो जजों की पीठ ने उस आदेश पर रोक लगा दी. मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को है.

ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्यूचर-रिलायंस सौदे को लेकर फ्यूचर ग्रुप और अमेजन के बीच यह लड़ाई दरअसल भारत के ई-टेल फलक पर कब्जे की लड़ाई है. खुदरा क्षेत्र पर जहां कोविड-19 की बुरी मार पड़ी, वहीं ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों के उत्पादों और ताजा सामानों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर देने के साथ ई-कॉमर्स की तरफ कुछ आकर्षण देखा गया. डेलॉइट और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 2019 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत का ई-कॉमर्स, जो 2017 में 24 अरब डॉलर (1.75 लाख करोड़ रूपए) का था, 2021 में छलांग लगाकर 84 अरब डॉलर (6 लाख करोड़ रुपए) पर पहुंच जाएगा. उभरते बाजारों की वृद्धि पर नजर रखने वाली अमेजन और वॉलमार्ट (जिसने मई 2018 में फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था) सरीखी दिग्गज वैश्विक ई-टेल कंपनियों के लिए भारत आकर्षक बाजार है. दत्ता कहते हैं कि चीन इन कंपनियों की पहुंच से बाहर है और इसलिए भारत ही संभावनाओं से भरपूर धरती है, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि वे बड़े, गहरे और जल्द निवेश करें. वे यह भी कहते हैं कि ऐसे में बराबर से आक्रामक और पूंजी से भरपूर रिलायंस सरीखी कंपनी का अमेजन के साथ टकराव होना स्वाभाविक है. हालिया अतीत में फिजिकल स्टोर वाली खुदरा कंपनियों के लिए कामकाज कर पाना मुश्किल रहा है, क्योंकि ई-टेल कंपनियां ने अपनी भारी छूट और आक्रामक इश्तहारबाजी की रणनीतियों के बल पर बाजार में तहलका मचा दिया है. केवल टाटा ग्रुप, आदित्य बिड़ला ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज सरीखी गहरी जेब वाली बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां ही इस चुनौती के आगे टिक पाई हैं.

नई मुसीबत

यह महीना बियानी के लिए और ज्यादा मुसीबत लेकर आया. 3 फरवरी को सेबी ने 2017 के इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े एक मामले में बियानी और उनके भाई अनिल सहित कई संबद्ध लोगों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने से एक साल के लिए रोक लगा दी. बियानी को फ्यूचर रिटेल के शेयरों की खरीद-बिक्री से भी दो साल के लिए रोक दिया गया है. मामला यह है कि फ्यूचर रिटेल ने अपने घरेलू खुदरा कारोबार का अप्रैल 2017 में एकीकरण किया था और उसके इस कदम का फायदा कंपनी के शेयरों को मिला था. सेबी की जांच में पाया गया कि यह एकीकरण 20 अप्रैल को सार्वजनिक जानकारी में आया, जबकि बियानी और उनसे जुड़े लोग उस साल मार्च से ही फ्यूचर रिटेल के शेयर खरीद रहे थे. इन शेयरों की खरीद के लिए धनराशियां बियानी परिवार के नियंत्रण वाली कंपनी फ्यूचर कॉर्पोरेट से हस्तांतरित की गई थीं. बियानी ने इस आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधीकरण का दरवाजा खटखटाया है.

केएस लीगल ऐंड एसोसिएट्स की मैनेजिंग पार्टनर सोनम चांदवानी के मुताबिक, ''सेबी का आदेश टिकने लायक नहीं है क्योंकि यह फ्यूचर ग्रुप के कारोबार के सार्वजनिक तौर पर ज्ञात पुनर्गठन को अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी के तौर पर बरतता है. हालांकि इस खास मामले में यह बहसतलब मुद्दा है कि 2017 में बियानी की खरीद-बिक्री अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी की खरीद-बिक्री के बराबर है या नहीं.'' बीएसई को दिए एक बयान में फ्यूचर रिटेल ने कहा कि बियानी को पूंजी बाजार से रोकने वाले सेबी के आदेश का फ्यूचर-रिलायंस के विलय की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

नियमित तौर पर सुर्खियों में रहने वाले बियानी एक बार फिर सबकी नजरों में हैं, मगर इस बार गलत वजहों से. अब जब खुदरा जगत ई-कॉमर्स क्षेत्र की इस जंग पर नजरें गड़ाए है, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बियानी के लिए राह का अंत है, या उनकी आस्तीन में अब भी कोई तुरुप का पत्ता छिपा है. ■

मोर्चे पर
अखनूर में नियंत्रण रेखा के पास तैनात भारतीय सुरक्षा बल

असलहों का जंजाल

मनमाने वैश्विक हथियार निर्माताओं पर निर्भरता से भारतीय सेना को परेशानी हो रही. त्रुटिपूर्ण हथियार उत्पादन और खरीद नीति इसकी वजह

संदीप उन्नीथन

जून 2020 में जब भारत का विशेष सैन्य बल लद्दाख में चीन के भारी फौजी जमावड़े के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की योजना बना रहा था, उसी की एक यूनिट को हथियारों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा था. छोटे हथियार बनाने वाली बेल्जियम की कंपनी एफएन हर्स्टेल (एफएनएच) ने कैबिनेट सचिवालय के तहत काम करने वाले एक विशेष अर्धसैनिक बल, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (एसएफएफ) को लगभग 1,500 छोटे हथियारों की आपूर्ति का अनुबंध तोड़ दिया. भारत और बेल्जियम की कंपनी के बीच तीन साल के मोल-तोल के बाद करीब 70 करोड़ रुपए मूल्य की पी90 कार्बाइन और एससीएआर असॉल्ट राइफल्स के लिए 2019 में एक करार हुआ और साल भर के भीतर आपूर्ति के लिए सहमति बनी थी.

अगस्त के अंत में एसएफएफ को उन्हें मिलने वाले हथियारों के बगैर ही लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान पर जाना पड़ा. एफएनएच के प्रवक्ता ने गोपनीयता का हवाला देकर इस विफल अनुबंध पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

इस घटना से चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के साथ तनाव की स्थिति में आयातित छोटे हथियारों पर भारत की बुरी तरह निर्भरता और उसके कारण पैदा होने वाली परेशानियों की थाह लगाई जा सकती है. इस बात का पूरा अंदेशा बना रहता है कि विदेशी हथियार फर्म मनमाने तरीके से कोई आड़ी-टेढ़ी वजह निकालते हुए करार को ऐसे समय भी तोड़ सकते हैं, जब आयातक देश की राष्ट्रीय सुरक्षा

यासिर इकबाल

सीमित आयात, असीमित उत्तरदायित्व

यूरोपीय बंदूक निर्माता एफएन हर्स्ट्ल के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का आयात अटक गया है. सेना की पैरा स्पेशल फोर्स इसी निर्माता से खरीदने जा रही है लेकिन अबकी बार इसे अमेरिका के रास्ते खरीदा जाएगा

भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स
1,400
एफएन स्कार एल 5.56x45 असाल्ट राइफलें
1,050
एफएन स्कार एच 7.62x51 असाल्ट राइफलें
100
बेरेट एम107 ए1 हैवी स्नाइपिंग राइफलें
715
एमके 48 'मैक्सिमी' जनरल पर्पज मशीनगन
अनुबंध: 500 करोड़ रुपए
स्थिति: विदेशी सैन्य बिक्री रूट के मार्फत अमेरिका से बातचीत चल रही है
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स
100
पी-9 पर्सनल डिफेंस वेपन
100
एफएन स्कार एचऐंडएल राइफलें
अनुबंध: लगभग 70 करोड़ रु.
स्थिति: रद्द. एफएन हर्स्ट्ल ने जून 2020 में हथियारों की सप्लाइ पर असमर्थता जताई

ग्राफिक्सः तन्मय चक्रवर्ती

पर कोई खतरा मंडरा रहा हो. यह तथ्य आयात को और पेचीदा बनाता है. करार रद्द करने का कारण आपूर्तिकर्ता देश की ओर से हथियार आपूर्ति की मंजूरी देने से इनकार से लेकर खरीदार देशों के मानवाधिकारों से जुड़े अपने मुद्दे तक कुछ भी हो सकता है.

एफएनएच के करार तोड़ने की वजह तो पता नहीं है लेकिन इसे पिछले अगस्त में ऐसे ही एक उदाहरण के आलोक में देखने की जरूरत है जब कंपनी ने अपने सबसे बड़े ग्राहक सऊदी अरब को छोटे हथियारों की आपूर्ति रोक दी थी. अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में इस उद्योग के 95 करोड़ यूरो (लगभग 8,396 करोड़ रुपए) के कारोबार में अकेले सऊदी अरब ने 22.5 करोड़ यूरो (लगभग 1,988 करोड़ रुपए) की खरीदारी की थी. यमन में सऊदी सैन्य हस्तक्षेप पर एक मानवाधिकार समूह की शिकायत के कारण इस सौदे को रोका गया.

एक हथियार निर्माता अपने मूल देश की विदेश नीति की अनदेखी करेगा, इसकी संभावना नहीं रहती. मसलन एफएनएच को ही लें. बेल्जियम की यह कंपनी कोई छोटी-मोटी फर्म नहीं है. दुनिया के शीर्ष पांच छोटे हथियार निर्माताओं में शुमार इस कंपनी के हथियारों का उपयोग यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमान भी करती है. भारत के सरकारी स्वामित्व वाले आयुध कारखानों में इसके तीन प्रसिद्ध उत्पादों—पिस्टल, मीडियम मशीन गन और सेल्फ-लोडिंग राइफल—का निर्माण पिछले चार दशकों से हो रहा है.

हालांकि, एफएनएच ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए छोटे हथियारों की आपूर्ति को हाल के किसी भी सौदे में भाग नहीं लिया है. (पाकिस्तान सेना को नई असॉल्ट राइफल की आपूर्ति करने के लिए 2016 की बोली में फर्म ने भाग लिया था) इन संभावित बाधाओं के बावजूद, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज ने एफएनएच हथियारों को हासिल करने के लिए घुमावदार रास्ता—अमेरिका के 'विदेशी सैन्य बिक्री' का चुना.

एक अन्य प्रमुख जर्मन हथियार निर्माता हेकलर ऐंड कोच भारतीय बाजार से दूर रहता है. इसकी एमपी5 सबमशीन गन्स एनएसजी (नेशनल सिक्योरिटी गार्ड) और मार्कोस (मरीन कमांडो) ने मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान इस्तेमाल की थीं. निर्माता का कहना है कि जर्मन निर्यात कानून 'जम्मू-कश्मीर की स्थिति' के मद्देनजर भारत को हथियारों की आपूर्ति की अनुमति नहीं देते. एचऐंडके प्रवक्ता का कहना है कि ''जर्मनी में छोटे हथियारों के निर्यात के लिए संघीय सरकार की मंजूरी लेनी होती है. कश्मीर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जर्मन सरकार ने हमारी कंपनी को बार-बार संकेत दिए हैं कि भारतीय रक्षा मंत्रालय को हथियार प्रदान करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी.''

भारत सरकार की ओर से स्वदेशी लघु हथियार उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा न देने के कारण विडंबनापूर्ण स्थिति पैदा हुई है—एक ऐसा देश जो मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजने में सक्षम है लेकिन हर साल लाखों असॉल्ट राइफल, पिस्टल और सबमशीन गन का आयात करता है और

छोटे हथियारों के दुनिया के सबसे बड़े आयातकों में से एक है. अकेले भारतीय सेना को अपनी थल सेना और स्पेशल फोर्सेज के आधुनिकीकरण के लिए 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की राइफलें, कार्बाइन और लाइट मशीन गन (एलएमजी) आयात करने की जरूरत है.

सेना समझती है कि विदेशी निर्भरता उसकी सीमाओं पर तैनात बलों की सैन्य ऑपरेशन की तैयारियों को किस हद तक प्रभावित कर सकती है. 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान सेना को तत्काल एंटी मटेरियल राइफल्स के लिए पुर्जों और खराब हथियारों की जगह नए हथियारों की जरूरत थी. हल्के बख्तरबंद वाहनों और बंकरों को नष्ट करने में सक्षम ये हथियार 1999 के करगिल युद्ध के बाद दक्षिण अफ्रीकी हथियार निर्माता डेनेल से खरीदे गए थे. 2005 में रक्षा मंत्रालय के डेनेल को ब्लैकलिस्ट करने के बाद उसके पुर्जों की आपूर्ति रुक गई. सेना के लिए यह बड़ा सदमा था जब उसे पता चला कि कंपनी दिवालिया हो गई थी और अब हथियारों की आपूर्ति करने में असमर्थ थी.

स्वदेशी रूप से हथियारों के उत्पादन से क्या फायदा मिल सकता है, यह सर्वविदित है. 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान, भारत सरकार ने अपने आयुध कारखानों में बनी राइफल्स और कार्बाइन की आपूर्ति करके 'मुक्ति वाहिनी' को उसकी आजादी की लड़ाई के लिए सक्षम बनाया था.

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के मनमाने रवैये से निबटने का एकमात्र समाधान वही हो सकता है जो एक खीझे हुए रक्षा सचिव ने एक बार साउथ ब्लॉक में सैन्य अधिकारियों के साथ बंद कमरे की बैठक में सुझाया था—भारत केवल चार रणनीतिक साझेदारों से हथियार आयात करे क्योंकि वे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हमेशा 'कोई न कोई रास्ता खोज ही लेंगे'.

शायद यह हमें संकेत देता है कि पिछले चार वर्षों में छोटे हथियारों के आयात में इतनी तेजी कैसे आई है, जिनमें से दो सौदे तो आपातकालीन त्वरित आपूर्ति प्रावधानों के अनुबंध के तहत किए जा रहे हैं. पिछले साल सेना ने फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत अमेरिकी बंदूक निर्माता एसआइजी सॉयर से 700 करोड़ रुपए की 72,000 राइफलें खरीदी थीं. सेना यूएई से 93,895 कार्बाइन आयात करना चाहती है. यूएई ऐसा देश है जिसका हथियार निर्माण का कोई इतिहास नहीं है. इसके साथ ही रूस के साथ साझेदारी में 7,50,000 एके-203 राइफल के उत्पादन का भी एक करार महत्वपूर्ण चरण में है. सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने 12 जनवरी को कहा कि अनुबंध पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे.

आयात, और अधिक आयात की जरूरतें पैदा करता है. सेना पहले ही अमेरिकी निर्माता को 72,000 राइफलों का ऑर्डर दोहरा चुकी है. इसलिए अन्य खरीद का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सस्ता, स्वदेशी विकल्प मौजूद है. मसलन, एके-203 जनरल मिखाइल कलाश्निकोव की 1947 में विकसित प्रतिष्ठित रूसी राइफल का आधुनिक संस्करण है. इसमें लकड़ी की जगह पॉलिमर का प्रयोग और डस्ट कवर पर एक पिकैटेनी रेल (हथियार के निशाना लगाने वाली जगह को कसने के लिए) के अलावा और कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है.

विदेशी हथियारों पर निर्भरता फौज की सैन्य ऑपरेशन की तैयारियों को प्रभावित कर सकती है जिसका सामना भारत ने 2019 में बालाकोट ऑपरेशन के दौरान किया

रक्षा मंत्रालय के पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में 'त्रिची असॉल्ट राइफल' और पश्चिम बंगाल की ईशापुर फैक्ट्री में 'घातक' राइफल के दो हथियार कारखाने पहले से ही हैं जो सस्ती एके-47 के क्लोन का निर्माण करते हैं (मूल एके-47 राइफल को कभी पेटेंट नहीं कराया गया था और इसलिए दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से इसकी नकल तैयार की जाती है). त्रिची असॉल्ट राइफल और घातक दोनों की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है. एके-203 की कीमत 75,000 रुपए आएगी क्योंकि रूस को लाइसेंस फीस भी चुकानी होगी. इन्फैंट्री के पूर्व महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी के अनुसार, सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभी हितधारक- उपयोगकर्ता, डिजाइनर और निर्माता—एक दूसरे के साथ बिना किसी तालमेल के काम करते हैं. जनरल कुलकर्णी 2016 के आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) और सेना की उस साझेदारी का हिस्सा थे, जिसने इंसास 1सी विकसित की थी, जो 1980 के दशक की राइफल का सबसे बेहतर संस्करण था. सेना के अपनी जरूरतें बदल देने के बाद इस हथियार को हटा दिया गया था.

राजवंत रावत

लक्ष्य पर नजर भारतीय सेना के ले. कर्नल प्रसाद बंसोड़ की डिजाइन की हुई 9x19 एमएम कार्बाइन का अनावरण 15 जनवरी को हुआ

ऑर्डर देकर स्वदेशी हथियारों को जो मदद दी जा सकती है, उससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस इकाइयों को लगभग 15,000 त्रिची असॉल्ट राइफल्स की आपूर्ति से प्राप्त अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली पिछले साल एक कॉम्पैक्ट एके-47 कार्बाइन के विकास में सफल रही. हालांकि, इंसास राइफल की परछाई-सेवा अवधि में गुणवत्ता और विश्वसनीयता की कसौटी पर पूरी नहीं उतरने के कारण—ओएफबी की परियोजनाओं के लिए अब तक मुश्किलें खड़ी करती रहती है.

भारत की छोटी शस्त्र इकाइयों—और ये दुनिया की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक हैं—के आधारभूत ढांचे का दशकों से भरपूर इस्तेमाल ही नहीं हुआ क्योंकि इन्हें नए ऑर्डर नहीं मिलते. इसकी सबसे बड़ी वजह इन इकाइयों में तैयार उत्पादों को लेकर भरोसे में कमी है. ईशापुर, त्रिची और कानपुर के तीन आयुध कारखानों—जो हर साल लगभग 1,00,000 राइफल्स और कार्बाइन के उत्पादन में सक्षम हैं—को दो साल पहले इंसास राइफल का उत्पादन बंद होने के बाद बड़े ऑर्डर मिलने बंद हो गए. ये कारखाने देश में एकमात्र ऐसे हैं जो 40 करोड़ रुपए प्रति मशीन की लागत वाली बैरल बनाने वाली आयातित मशीनों का उपयोग करके बंदूक के बैरल का निर्माण कर सकते हैं.

स्नाइपर राइफल्स, कार्बाइन और असॉल्ट राइफल्स की अपनी खुद की रेंज वाली निजी क्षेत्र की एकमात्र कंपनी, एसएसएस डिफेंस के सीईओ विवेक कृष्णन कहते हैं, ''आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल यह नहीं होना चाहिए कि हम भारतीय हथियार खरीदने लगें, बल्कि इसे सेना की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कमर कसने के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अगले 50 साल तक हथियारों की खरीद के लिए किसी और का मुंह न ताकना पड़े. यह केवल भारतीय उद्योग में निवेश करने से हो सकता है. इसके लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए जाते तो हथियारों का आयात भविष्य में भी आकर्षक विकल्प बना रहेगा. ■

सिनेमा

जल्द देखिए अपने नजदीकी सिनेमाघर में

सिनेमाघरों के अब पूरी तरह से खुल जाने के बाद प्रोड्यूसर और स्टुडियो साल भर से रोक कर रखी गई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की रिलीज की तारीखों का ऐलान करने को तैयार

सुहानी सिंह

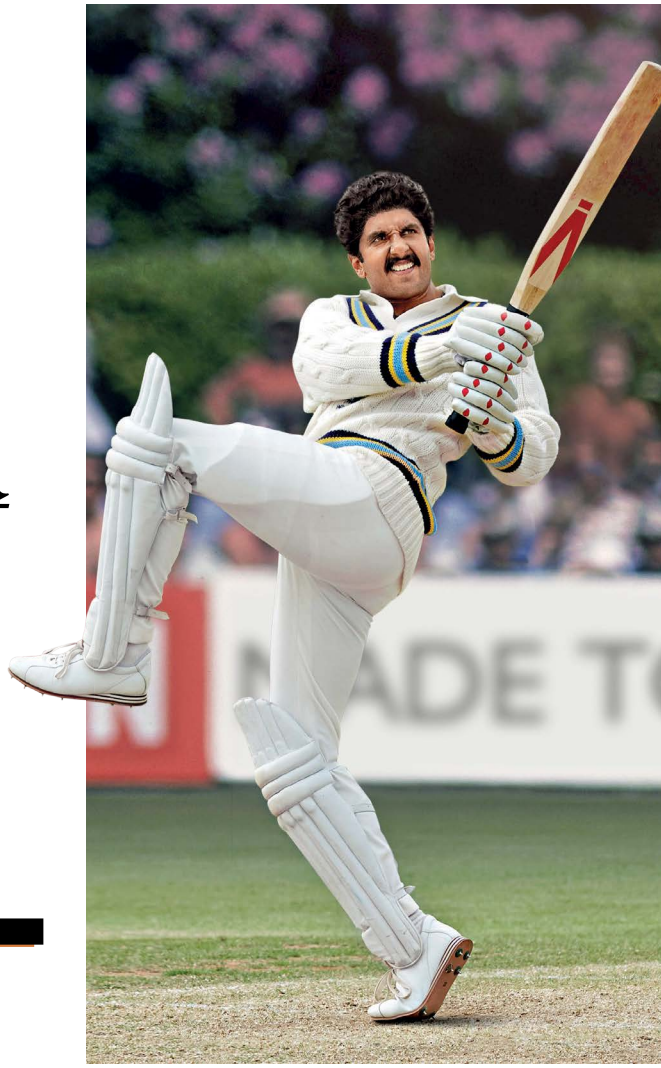

रिलायंस एंटरटेनमेंट के ग्रुप चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफीसर सुभाशीष सरकार बॉलीवुड स्टुडियो के उन कर्ताधर्ताओं में थे जो तमिल फिल्म *मास्टर* के रोजाना के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर उत्सुकता से नजर रखे थे. इंडस्ट्री के दो लोकप्रिय सितारों तलपति विजय और विजय सेतुपति की मौजूदगी से सजी इस ड्रामा फिल्म ने 13 जनवरी को अपनी रिलीज के बाद देश में 150 करोड़ रुपए और इसके अलावा विदेशों से 100 करोड़ रुपए और बटोर लिए. 1 फरवरी तक सिनेमाघर अपनी आधी क्षमता से ही खुले थे. ऐसे में यह आंकड़ा और भी रोमांचक है. सरकार कहते हैं, ''इसने भारतीय फिल्म उद्योग को ऑक्सीजन दे दी है. इसकी कामयाबी साबित करती है कि दर्शक घर से बाहर निकलकर मनोरंजन के लिए बेताब हो उठे हैं.'' जब से केंद्र ने सिनेमाघरों को पूरी क्षमता से खोलने की इजाजत दी है, नजरें सुभाशीष पर टिकी हैं जिन्होंने रिलायंस की दो बेशकीमती फिल्में रोक रखी हैं. इनमें से एक रोहित शेट्टी की *सूर्यवंशी* है जिसमें अक्षय कुमार हैं और दूसरी कबीर खान की *'83* जो भारत की पहली विश्व कप जीत को परदे पर साकार कर रही है.

सिनेमाघर वाले उम्मीद कर रहे हैं कि ये दो फिल्में बुरी तरह चरमरा गए उनके कारोबार में नई जान फूंकने में मददगार होंगी. यह पूरी तरह खुलने वाले आखिरी उद्योगों में से है. सुभाशीष को उम्मीद है कि वे इन दोनों में से एक फिल्म मार्च के आखिरी या अप्रैल के शुरुआती हफ्ते में होली-गुड फ्राइडे के दौर में रिलीज कर पाएंगे, जबकि दूसरी जून में रिलीज करने के लिए रखी गई है. 200-200 करोड़ रुपए के बजट से बनीं इन फिल्मों की रिलीज की तारीख वितरकों की सहमति से ही तय होगी. सुभाशीष कहते हैं, ''दोनों फिल्में साल भर से रोक रखी हैं. लागत, कारोबार की बात हम भूल ही गए हैं. हम इतना कुछ गंवा चुके हैं कि हालात का फायदा उठाने की स्थिति में भी नहीं रह गए हैं.''

15 अक्तूबर, 2020 को सिनेमाघर खुलने के बाद केवल इनी-गिनी फिल्में ही दर्शकों को बड़े परदे की तरफ रिझा पाने में कामयाब रही हैं. इनमें मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में

फिर ऐक्शन में
(बाएं से क्रमशः) रणवीर सिंह *'83* में; अक्षय कुमार *बेलबॉटम* में और सलमान खान *राधे* फिल्म के एक दृश्य में

टेनेट और *वंडर वूमैन 1984*, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर *ड्रेकुला सर* सरीखी कुछेक बंगाली फिल्में और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में रवि तेजा की *क्रैक* हैं. कारोबार मंदा था क्योंकि सिनेमाघर पुरानी फिल्में दिखा रहे थे और निर्माताओं ने छोटी और स्वतंत्र फिल्में रिलीज करने का विकल्प चुना. ऐसे में *मास्टर* परेशानहाल उद्योग के लिए आशा की किरण बन गई. पीवीआर पिक्चर्स लिमिटेड के सीईओ और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसीडेंट कमल ज्ञानचंदानी कहते हैं, ''इसने इस दलील को ही उलट दिया कि दर्शकों को थिएटरों की तरफ लौटने में लंबा वक्त लगेगा. वापसी के लिए बात बस बड़े सितारे वाली एक फिल्म के रिलीज होने की है.''

मास्टर की कामयाबी से उत्साहित दक्षिण के निर्माताओं ने सितारों के कंधों पर सवार फिल्मों की रिलीज की तारीखें पहले ही घोषित कर दी हैं (देखें बॉक्स). बॉलीवुड अलबत्ता एहतियात बरत रहा है. सिनेमाघरों के मालिकों ने एकजुट सोशल मीडिया अभियान चलाया और अभिनेता-निर्माताओं से प्रदर्शन उद्योग को बचा लेने की गुजारिश की. इसके बाद सलमान खान बॉलीवुड के पहले सितारे थे जो आगे आए और जिन्होंने अपनी अगली फिल्म *राधे* के ईद पर रिलीज की तारीख तय कर दी. बड़े बजट की दूसरी फिल्मों में आमिर खान की *लाल सिंह चड्ढा* 24 दिसंबर को आएगी, वहीं अक्षय कुमार की बहुत-सी फिल्मों में से केवल एक *बेलबॉटम* की तारीख 2 अप्रैल तय हुई है. यशराज फिल्म्स और धर्मा एंटरटेनमेंट दोनों में से किसी ने अपनी फिल्मों के लिए कोई तारीख नहीं रुकवाई है.

टी-सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भूषण कुमार इस बात से चौकन्ने हैं कि दक्षिण के सिनेमाघरों में जाने वाले दर्शक उत्तर और पश्चिम के दर्शकों से काफी अलहदा हैं. (*मास्टर* ने अकेले तमिलनाडु से 138 करोड़ रुपए कमाए.) राज्य में *मास्टर* के टिकट खरीदने के लिए भीड़ ने कैसे धक्कामुक्की की, इसकी चर्चा करते हुए कुमार कहते हैं, ''वे फिल्मों के बेहद दीवाने हैं. हम *मास्टर* के प्रदर्शन से बहुत उत्साहित नहीं हो सकते. हम यहां के लोगों की ओटीटी देखने की आदत को लेकर फिक्रमंद हैं.'' कुमार ने रुकी फिल्मों की लिस्ट छोटी करने के लिए 2020 में कम से कम तीन फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दीं. इनमें से दो *छलांग* और *दुर्गामती* अमेजन प्राइम को और एक नेटफिलक्स को बेची गईं. एक और *भुज—प्राइड ऑफ इंडिया* डिज्नी+हॉटस्टार पर रिलीज होने की कतार में है. वे कहते हैं, ''मेरे पास जमा फिल्में किसी भी दूसरे स्टुडियो के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं. अगर मैंने ओटीटी का रास्ता नहीं चुना होता और थिएटर खुलने तथा

दक्षिण में *मास्टर* की कामयाबी के बावजूद बॉलीवुड दर्शकों को लग चुके ओटीटी के चस्के की वजह से सतर्कता के साथ कदम बढ़ा रहा

कोविड से पहले के वक्त की तरह दर्शकों के लौटने का इंतजार करता रहता, तो मेरी फिल्मों को भीड़ भरे कैलेंडर में ज्यादा शो की जगह नहीं मिलती.''

सप्ताहांत की तारीखों को लेकर जद्दोजहद शुरू हो गई है. दो बड़ी फिल्मों की तारीखें आपस में टकरा रही हैं. *राधे* जॉन अब्राहम की मौजूदगी से सजी *सत्यमेव जयते 2* के साथ होड़ करेगी, तो अजय देवगन की अगुआई में फुटबॉल पर बनी ड्रामा फिल्म *मैदान* 13 अक्तूबर को मजबूत प्रतिद्वंद्वी *आरआरआर* का सामना करेगी, जो *बाहुबली 2* के बाद एस.एस. राजामौलि की पहली फिल्म है. बोनी कपूर इस बात को लेकर राजामौलि से नाराज थे कि उन्होंने *मैदान* की रिलीज के लिए तारीखें पिछले साल ही रुकवा ली थीं. उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से कहा, ''जब फिल्म उद्योग को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे में दो बड़ी बहुभाषी फिल्मों की तारीखों को लेकर टकराव की हम उम्मीद नहीं कर सकते. हमें एक दूसरे को जगह देनी चाहिए ताकि सभी ज्यादा से ज्यादा तादाद में दर्शक हासिल कर सकें.''

अब 2021 में न केवल 2020 की रुकी हुई फिल्में रिलीज होंगी बल्कि कई नई फिल्में भी आएंगी. नतीजा यह होगा कि फिल्मों की रिलीज का कैलेंडर बुरी तरह भर जाएगा. ज्ञानचंदानी कहते हैं कि ऐसे में मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि ''भारत जरूरत के मुकाबले बहुत कम स्क्रीन वाला बाजार'' है. भारत जहां हर साल अधिकतम फिल्में रिलीज करने वाले देशों में शीर्ष पर हैं, वहीं यहां 10,000 से भी कम स्क्रीन हैं. लॉकडाउन के बाद स्क्रीन की तादाद और भी घट रही है. पीवीआर ने पिछले साल तीन मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए जिनमें 14 स्क्रीन थे. उधर सैकड़ों सिंगलस्क्रीन सिनेमाघर हमेशा के लिए बंद हो गए. फिर भी कुछ सिनेमाघर मालिकों ने उम्मीद का दामन थामा हुआ है. आइनाक्स लीजर लिमिटेड के चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर राजेंद्र सिंह ज्याला कहते हैं, ''2021 सिनेमा का साल है. 50 से ज्यादा हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं की फिल्में परदे पर आने की उम्मीद है, उद्योग पूरे साल बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का गवाह बनेगा.'' ज्ञानचंदानी जोड़ते हैं, ''2021 के खासकर उत्तरार्ध में हम ऐसा कारोबार होता देखेंगे जो हमने एक दशक में नहीं देखा.''

यह इस पर निर्भर करेगा कि निर्माता और सिनेमाघर मालिक वर्चुअल प्रिंट शुल्क, जो सिनेमाघर प्रोड्यूसरों से उनकी फिल्म दिखाने की एवज में वसूलते हैं, और थिएटर से डिजिटल रिलीज के बीच की अवधि सरीखे मुद्दों पर कैसे राजी होते हैं. *मास्टर* बड़े परदे पर आने के महज 16 दिन बाद एमेजन प्राइम पर मौजूद थी. तमिल और तेलुगु फिल्में अमूमन बड़े परदे पर रिलीज होने के महीने भर बाद और हिंदी फिल्में दो महीने बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आती हैं. ओटीटी पर तुरत-फुरत रिलीज करने की खातिर *मास्टर* के निर्माताओं ने फिल्म के ऑनलाइन रिलीज होने के बाद सिनेमाघरों की कमाई छोड़ दी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हॉलीवुड के कई स्टुडियो ने सिनेमाघर और स्ट्रीमिंग रिलीज के बीच का अंतराल कम कर दिया है. यूनिवर्सल अब सिनेमाघरों में आने के महज 17 दिन बाद अपनी फिल्मों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेगा, जबकि वार्नर ब्रदर्स अमेरिकी सिनेमाघरों को मायूस करते हुए फिल्में सिनेमाघरों में और ऑनलाइन एक साथ रिलीज करेंगे. अपना नाम उजागर नहीं करने के आग्रह पर एक प्रोड्यूसर कहते हैं कि दक्षिण के सिनेमाघर मालिक दूसरी जगहों के सिनेमाघर मालिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मददगार और लचीले थे. वे कहते हैं, ''अगर हम इस अवधि को कम कर देते हैं तो हमें अपने डिजिटल भागीदारों से अतिरिक्त धन मिल जाता है और हम सिनेमाघरों में होने वाले नुक्सान की भरपाई कर लेते हैं.''

पर ज्ञानचंदानी *मास्टर* को नियम के अपवाद के तौर पर देखते हैं. वे ओटीटी रिलीज के बाद भी तमिलनाडु में इस फिल्म के अच्छे प्रदर्शन का हवाला देते हैं, जिसमें उसने तीसरे हफ्ते में 2.78 करोड़ रुपए कमाए. वे कहते हैं, ''यह सिनेमाघरों का लचीलापन दिखाता है, बावजूद इसके कि ओटीटी कम महंगी पेशकश है.'' बॉलीवुड को रक्षा के लिए मास्टर का इंतजार है. ■

2021 में आ रही हैं

अप्रैल

कर्नन

मारी सेल्वराज निर्देशित इस तमिल फिल्म के अभिनेता धनुष हैं

26 मार्च

हाथी मेरे साथी/काडन/आरण्य

इस बहुभाषी फिल्म में राणा डग्गूबत्ती हाथियों के आवास को घाघ कंपनियों के जाल से बचाते नजर आएंगे

13 मई

आचार्य

चिरंजीवी-राम चरण पिता-पुत्र इस ऐक्शन पैक फिल्म में धमाल करते दिखेंगे

9 अप्रैल

वकील साब

हिंदी फिल्म पिंक की इस तमिल रीमेक के जरिए वापसी कर रहे पवन कल्याण अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाने वाले वकील के रोल में

2 जुलाई

मेजर

तमिल स्टार महेश बाबू निर्मित यह ड्रामा मुंबई के ताज होटल पर 26/11 के हमले में शहीद एनएसजी कमांडो संदीप उन्नीकृष्णन की जिंदगी से प्रेरित है

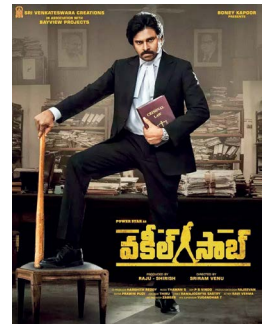

16 जुलाई

केजीएफ चैप्टर 2

कन्नड़ सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक के इस सीक्वल के कलाकारों की सूची में संजय दत्त और रवीना टंडन भी जुड़ रहे हैं

गौतम
मुखोपाध्याय

मेहमान का पन्ना

म्यांमार: तलवार की धार

एक चुनावी विवाद को लेकर म्यांमार में 1 फरवरी को जो सैन्य तख्तापलट हुआ, वह देश के लोगों की इच्छा के विरुद्ध एक और मर्मांतक हस्तक्षेप है. इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ पूरे म्यांमार में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन फूट पड़े हैं. यह कार्रवाई ठीक उस दिन की गई जब नवंबर 2020 के राष्ट्रीय चुनाव में डॉ. आंग सान सू की (अब हिरासत में) की अगुआई वाली सत्ताधारी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की तीसरी बड़ी जीत (पहली दो 1990 और 2015 में) के बाद नई संसद की पहली बैठक होने वाली थी.

सीनियर जनरल मिन ऑन्ग लाइंग ने 8 फरवरी को वादा किया कि एक साल के आपातकाल के दौरान नए चुनाव आयोग के हाथों चुनाव नतीजों में सुधार के बाद बहुदलीय लोकतंत्र बहाल कर दिया जाएगा. सेना ने ताकत का इस्तेमाल करने से अब तक परहेज किया है और टेलीकॉम/इंटरनेट/सोशल मीडिया पर पाबंदियों तथा राजनैतिक कर्फ्यू का ही सहारा लिया है, लेकिन मुमकिन है कि वहां तनाव बढ़कर हिंसा में बदल जाए.

एशिया के इस क्षेत्र और दुनिया के लिए तख्तापलट के व्यापक नतीजे होंगे. 2016 में जब अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा से डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में जा रहा था, नवबंर 2015 के चुनाव में सू की की जोरदार जीत लोकतंत्र के अनुमोदन के तौर पर अलग दिखाई दी थी. अब जब अमेरिका ने खुद अपने लगभग दक्षिणपंथी 'तख्तापलट' का स्वाद चख लिया है, यह तार्किक ही है कि राष्ट्रपति जो बाइडन लोकतंत्र को अपनी विदेश नीति का एक बड़ा आधार बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं. म्यांमार इसमें उनकी पहली परीक्षा है. मगर शुरुआती संकेत तो यही हैं कि बाइडन सुरक्षा मुद्दों पर चीन के साथ संभवत: कठोरता की नीति बरतना जारी रखेंगे और हिंद-प्रशांत के लिए मुख्य कर्ताधर्ता के तौर पर दिग्गज कूटनीतिक कुर्ट कैंपबेल की नियुक्ति को देखते हुए संभावना नहीं है कि अमेरिका अपनी 'बर्मा' नीति एक घटना के आधार पर तय करेगा या निरे प्रतिबंधों का सहारा लेगा.

सू की के साथ अपने रिश्तों को अच्छी तरह से संभालता आ रहा चीन भी एकाएक सकते में आ गया दिखता है, हालांकि वह म्यांमार के खिलाफ किसी भी अंतरराष्ट्रीय भर्त्सना या प्रतिबंध का फायदा उठाने से नहीं चूकेगा. प्रमुख रक्षा भागीदार रूस के साथ तातमादाव (म्यांमार के सैन्य प्रशासन) का रिश्ता जनरल मिन ऑन्ग लाइंग के मातहत फला-फूला है, जिन्होंने पिछली जुलाई में म्यांमार के जातीय हथियारबंद धड़ों को चीन के समर्थन की दबी-छिपी आलोचना करने के लिए रूसी मीडिया चैनल चुना था.

यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने तख्तापलट की खुलकर आलोचना की है. जापान ने थोड़ा एहतियात बरता, लेकिन किरिन बियर ने अपनी सबसे अव्वल 'म्यांमार' बियर को लेकर सैन्य उपक्रम म्यांमार इकॉनोमिक होल्डिंग्ज के साथ भागीदारी तोड़ दी है. सेना के खिलाफ खुद जनांदोलन का सामना कर रहा थाइलैंड चौकन्ना है. आसियान और सुरक्षा परिषद दोनों ने अपने सदस्यों के बीच मतभेदों में तालमेल बैठाने की खातिर सीधी भर्त्सना तो नहीं की, लेकिन आपातस्थिति के ऐलान पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की है और हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने और जन इच्छा का सम्मान करने की मांग की है. बांग्लादेश रोहिंग्याओं की वापसी के हुकूमत के वादे की निगरानी करेगा.

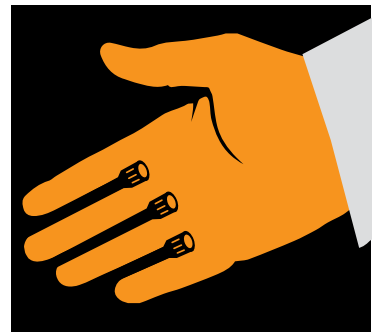

भारत ने अभी तक म्यांमार से सैन्य संबंध और वहां की जनाकांक्षा को राजनैतिक समर्थन दोनों को अलग-अलग रखा है. अब इसका इम्तहान होगा

भारत भी वैचारिक द्वंद्व से गुजरेगा. सहस्त्राब्दि बदलने के आसपास तातमादाव से अपने व्यावहारिक जुड़ाव के समय से ही भारत ने सेना और एनएलडी दोनों से भरोसे का रिश्ता विकसित किया है और सेना के साथ अपने रक्षा प्रशिक्षण, आपूर्ति और सुरक्षा संबंधों को म्यांमार की जन इच्छा को दिए जा रहे अपने राजनैतिक समर्थन से अलग रखा है. अब यह कसौटी पर कसा जाएगा.

कुछ हलकों में यह सोचा जा रहा है कि चीन को नियंत्रण में रखने के लिए भारत तातमादाव के साथ काम करने को मजबूर होगा. यह भ्रांत नजरिया है. चीन को अपने रणनीतिक निवेशों, जातीय हथियारबंद धड़ों पर प्रभाव और सुरक्षा परिषद में अपनी वीटो शक्ति की वजह से म्यांमार पर ज्यादा बढ़त जरूर हासिल है, लेकिन उसे वह भरोसा हासिल नहीं है जो भारत ने अर्जित किया है. सुरक्षा परिषद में अपने मौजूदा कार्यकाल के चलते भारत का वजन कुछ बढ़ जाएगा. भारत को अपनी प्रतिक्रिया में केवल चीन ही नहीं बल्कि म्यांमार के लोगों और अर्थव्यवस्था के साथ संबंध बढ़ाने में अपने दीर्घकालिक हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए. पिछले अक्तूबर में भारत के विदेश सचिव और सेना प्रमुख की असामान्य संयुक्त यात्रा इसी को दिमाग में रखकर की गई हो सकती है.

सेना और जनशक्ति के बीच टकराव में भारत को साफ तौर पर लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए. मगर उसे अपना भरोसा बनाए रखते हुए शांत कूटनीति का सहारा लेना चाहिए. तातमादाव से अगर कोई आर्थिक रिश्ते हों तो उन पर वह लगाम कस सकता है जबकि लोगों और जगहों को जोड़ने वाले बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण में निवेश को आगे बढ़ाता रह सकता है, खासकर उस उपेक्षित कृषि-अर्थव्यवस्था पर जोर देते हुए जिस पर म्यांमार के ज्यादातर लोग निर्भर हैं. म्यांमार में असैन्य शासन वापस लाने के लिए वह आसियान और जापान के साथ मिलकर भी काम कर सकता है.

गौतम मुखोपाध्याय *सीरिया, अफगानिस्तान और म्यांमार में भारत के राजदूत रह चुके हैं और अभी नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर विजिटिंग फेलो हैं*

इलस्ट्रेशन: तन्मय चक्रवर्ती

सवाल + जवाब

बेबाक विनोद

फिल्मकार **विधु विनोद चोपड़ा** हमेशा से बेबाक, दिलचस्प और आकर्षक व्यक्तित्व वाले रहे हैं. उनके और पटकथा लेखक अभिजात जोशी के बीच हुई बातचीत से तैयार किताब *अन्क्रिप्टेड* में भी वे सारे पहलू देखे जा सकते हैं

● फिल्म निर्माण से जुड़े किस्सों-वाकयों के अलावा आपने इस किताब में निजी जिंदगी के बारे में भी बात की है. वह सब साझा करना कितना कठिन था आपके लिए?

अभिजात से मेरा रिश्ता 26 साल पुराना है और मेरी जिंदगी के बारे में मुझसे ज्यादा चीजें उसे याद हैं. वह मेरे भाई जैसा है. मुझे लगता है, अपनी जिंदगी की बातें साझा करने का यह शायद सबसे अच्छा और एकमात्र रास्ता था क्योंकि मैं किताब नहीं लिख रहा था बल्कि एक दोस्त से बातें कर रहा था.

● किताब में कुछ बड़े ही खूबसूरत वाकए हैं—अमिताभ बच्चन आपके घर पर अपने पिता की कविता का पाठ कर रहे हैं; आर. डी. बर्मन परिंदा के लिए एक गाने की फंडिंग कर रहे हैं. आपको लगता है, इंडस्ट्री में आज भी उतनी ही गर्मजोशी है?

मेरे घर में, और मेरे दफ्तर में भी जहां मैं फिल्में बनाता हूं, अब भी वही गर्मजोशी है. इंडस्ट्री में वह गर्मजोशी है कि नहीं, यार ये आप लोग देखो. मुझे उसमें क्या लेना-देना! मुझे तो बस इसकी फिक्र है कि मेरी जिंदगी में गर्मजोशी बनी रहे. और उसके लिए हमेशा मेरी कोशिश जारी रहती है.

● *अन्क्रिप्टेड* पढ़ने में संस्मरण-सी लगती है जबकि है यह वार्तालाप. इस किताब के विचार ने किस तरह शक्ल ली?

अभिजात और मैंने जब बातचीत शुरू की तब सोचा भी नहीं था कि यह किताब बन जाएगी. पटकथा के अपने सत्रों के दौरान, वह भी पांच साल पहले, हम दोस्ताना अंदाज में कुछ बात करते जा रहे थे. और ये इसके पन्ने आल्मारी में कहीं पड़े थे. इन पर कहीं से (लेखिका) नसरीन मुन्नी कबीर की नजर पड़ गई, वो बोलीं कि इसमें तो किताब का पूरा मसाला है! हमने भी कह दिया, ''हां, हां, क्यों नहीं!''

● आप कश्मीर के एक छोटे-से मोहल्ले में पले-बढ़े. आज आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब फिल्मकारों में से हैं. आपकी सफलता के सूत्र क्या रहे हैं?

सच कहूं तो मेरी कामयाबी मुझे भी चौंकाती है. *थ्री ईडियट्स* में जैसा हमने कहा था कि अपने काम में हमेशा मैंने कामयाबी नहीं बल्कि उसे बेहतरीन बनाने के बारे में ही सोचा. आज मैं कामयाब हूं, यह एक तरह का चमत्कार ही है.

– श्रीवत्स नेवटिया

मंदार देवधर

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE